RNI No : MPHIN/2022/82783
कुल पृष्ठ : 52, मूल्य : 50 रुपए
वर्ष 03, अंक 5 मासिक पत्रिका
25 मई 2024

हमारा देश हमारा अभिमान

हर-हर महादेव

हिन्दू विवाह पर सर्वोच्च अदालत का फैसला...

स्वागत योग्य

आदरणीय पिताजी...

आप जैसे सुसंस्कारी वटवृक्ष की छाया मे पलकर दुनिया को परखने का हूनर सीखा। भले ही सशरीर आप हमारे बीच नही हो लेकिन आपका सानिध्य हर पल महसूस होता है। निष्पक्ष, निष्कपट,निष्कलंक, निस्वार्थ रहने के भाव व तटस्थ रहने की प्रवृत्ति का जो पाठ आपने पढ़ाया है उससे दुनिया जीतने का हौंसला अनवरत बना रहता है। आप जैसे पिता की संतान कहलाना गर्व महसूस कराता है। परमपिता परमेश्वर अपने श्री चरणों मे आपको स्थान दे। शत शत नमन...

मनोज चतुर्वेदी

विकास चतुर्वेदी

हमारा देश
हमाराअभिमान

25 मई 2024

वरिष्ठ संरक्षक मंडल

- अनन्त श्री विभूषित श्रीमद जगद्गुरु श्री राम स्वरूपचार्य जी महाराज कामदगिरि पीठाधीश्वर चित्रकूट धाम
- श्री महामंडलेश्वर रामप्रिय दास
- श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर अनिरुद वन जी, श्री धूमेस्वर धाम
- श्री डॉ. श्रीमन नारायण मिश्रा
- डॉ. श्रीमती शालिनी कौशिक
- श्री नागेंद्रनाथ सुरेंद्र नाथ चौबे

संरक्षक मंडल

- श्री लोकेश चतुर्वेदी
- श्री डॉ. दिनेश उपाध्याय
- श्री अरविंद जैन
- श्री प्रदीप कुमार शर्मा
- श्री शिवदयाल धाकड़
- श्री अरुण कांत शर्मा
- श्री महेश पुरोहित
- श्री विनोद भारद्वाज, अधिवक्ता ग्वालियर हाईकोर्ट,
- श्री मनोज भारद्वाज
- श्री अनिल जैन
- श्री निर्मल वासवानी
- श्री विद्याभूषण शर्मा
- श्रीमती अर्चना बाजपेयी
- एडवोकेट श्रीमती रिचा पांडेय (सुप्रीम कोर्ट)
- श्री के.एल.दलवानी
- श्री राकेश कुमार सगर
- श्री जयराज कुबेर
- श्री अभिनव पल्लव
- श्री बृजेश श्रीवास्तव
- श्री दीपक कुमार शुक्ला
- श्रीमति निवेदिता गुप्ता
- श्री विनोद कुमार बांगडे
- श्री विनायक शर्मा
- कमांडो कमल किशोर (पूर्व सांसद)
- श्री के. कान्याल

संपादक : मनोज चतुर्वेदी

पंकज दीक्षित
प्रमुख परामर्शदाता

विशेष संवाददाता
- रवि परिहार • रविकांत शर्मा

कानूनी सलाहकार
- एडवोकेट अनिल शुक्ला शासकीय अधिवक्ता, ग्वालियर हाईकोर्ट
- एडवोकेट एस.के. पाठक, ग्वालियर
- दीपेंद्र कुमार पाण्डेय, एडवोकेट, उच्च न्यायालय

ब्यूरो : अविनाश (उज्जैन संभाग)

छिंदवाड़ा ब्यूरो : जितेंद्र चौरे

मुम्बई ब्यूरो (महाराष्ट्र)
सचिंदर शर्मा (फ़िल्म डायरेक्टर)

सलाहकार

- डॉ सुनील शर्मा, नेत्र रोग विशेषज्ञ
- श्री डॉ. मुकेश चतुर्वेदी
- डॉ. दिनेश प्रसाद (हड्डी रोग सर्जन)
- श्री अनिल दुबे
- श्री विकास चतुर्वेदी
- श्री सुरेश शर्मा
- श्री नारायणदास गुप्ता
- श्री पीयूष श्रीवास्तव
- पंडित श्री चंद्रशेखर शास्त्री
- श्री बृज मोहन आर्य
- श्री विवेक शर्मा
- श्री अशोक कुमार वर्मा
- श्री आनंद कुमार
- श्रीमती रितु मुदगल
- श्री कुंज बिहारी शर्मा
- सुश्री पूजा मावई
- श्री संदीप कुमार पांडेय
- श्री मनोज सिंह
- प्रदीप यादव
- निरंजन शर्मा
- विनीत गोयल
- डॉ. सुधीर राजौरिया, हड्डी रोग विशेषज्ञ
- आशीष त्रिवेदी
- डॉक्टर अशोक राजौरिया
- हेमाटोलाजिस्ट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट
- डॉक्टर कमल कटारिया
- यशवंत गोयल
- दीपक भार्गव
- अमित जैन इंदौर
- सुरजीत परमार
- संजू जादौन
- डॉक्टर हिमांशु डेंटिस्ट
- रागिनी चतुर्वेदी
- प्रवेंद्र चतुर्वेदी
- प्रखर सिंह

ब्यूरो राजस्थान
सुभाष सोरल (फ़िल्म निर्माता) कोटा

ब्रजेश जैन साक्षात्कार व्यवस्थापक और विज्ञापन संवाददाता इंदौर

संवाददाता : संदीप पाटिल, इंदौर

मार्केटिंग प्रमुख : शैलेन्द्र जैन

मार्केटिंग मैनेजर
- सुनील • हरशूल

डिजाइन : मनोज पंवार

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक मनोज कुमार चतुर्वेदी द्वारा कंचन ऑफसेट डी-1/63, सेक्टर-4, विनय नगर ग्वालियर- फोन नं. 0751-2481433, (म. प्र.) से मुद्रित एवं शिव कॉलोनी गली नं. 4 , रेलवे स्टेशन के पीछे, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर, (मध्यप्रदेश) प्रकाशित। संपादक-मनोज कुमार चतुर्वेदी ।
(सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र ग्वालियर रहेगा।)

विवरणिका

संपादकीय	.....	02
शुभाशीष	.....	03
कवर स्टोरी	.....	04-05
देश	.....	06-07
विदेश	.....	08
देश	.....	09
देश	.....	10-11
देश	.....	12
सर्वे	.....	13
देश	.....	14-15
वित्त	.....	16
कृषि	.....	17
देश	.....	20-21
देश	.....	22
देश	.....	23
देश	.....	24
देश	.....	25
प्रदेश	.....	31
वित्त	.....	26
देश-प्रदेश	.....	27
राजधानी	.....	34
देश-विदेश	.....	35
स्वास्थ्य	.....	38-39
पर्यटन	.....	40-41
धर्म	.....	44
खेल	.....	45
ग्लैमर	.....	49
ग्लैमर	.....	50

48

अंकिता ने करण जौहर की स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 को किया रिजेक्ट

संपादकीय

अपनी अस्तित्व बचाने के संकट से जूझती कम्युनिस्ट पार्टियां...

वामदलों की चुनावों में सूखा 2009 के चुनावों से लगातार बढ़ता गया है। 2004 में जहां 59 सीटे थी जो 2009 में कम होकर 24 रह गई, 2014 के चुनावों में उसकी भी आधी यानी 12 और 2019 के चुनावों में उसकी आधी यानी कि 6 रह गई। देश की कम्युनिस्ट पार्टियों के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। साल 2004 कम्युनिस्ट पार्टियों के उम्थान का काल कहा जाए तो उसके बाद वाम दलों का लोकसभा में प्रतिनिधित्व लगातार कम ही होता जा रहा है। अब 18 वीं लोकसभा के चुनावों में वामदलों के सामने अपने अस्तित्व को बचायें रखने का संकट खड़ा हो गया है। आजादी से पहले और उसके बाद के दौर में एक समय था जब वामदलों की पूरे देष में तूती बोलती थी। सरकार भले ही कम ही राज्यों में रही हो पर वामदल और उसके अनुसंघी संगठन चाहे वह स्टूडेंट फैडरेशन हो या मजदूर संगठन या लेखक संघ सभी की अपनी पहचान और फोलोवर्स रहे हैं। पर समय का बदलाव देखिये कि आज वामदलों के सामने पहचान बनाये रखने का संकट खड़ा हो गया है। प. बंगाल में तो वामदलों तीन दशक से भी अधिक समय तक एक सत्र राज किया, वहीं त्रिपुरा, केरल में भी वामदलों की सरकार रही है। पर 2019 के लोकसभा के चुनाव आते-आते तो हालात यह हो गई कि वामदलों के गढ़ प. बंगाल में तो वामदलों को एक भी सीट नहीं मिली, वहीं त्रिपुरा में भी खाता खोलने में विफल रही। दरअसल समय की मांग को समझना और उसके अनुसार समयानुकूल बदलाव करना अपने आप में बड़ी बात होती है। जनभावना को भी समझना जरुरी हो जाता है। केवल विचारधारा और एग्रेसिव होने से काम नहीं चल सकता। फिर अपने अपने अहम् के चलते समय पर सही निर्णय नहीं लेने का परिणाम देर सबेर भुगतना पड़ता है। ज्योति बसु के पास तीन बार प्रधानमंत्री बनने के अवसर आये पर पोलिट ब्यूरों ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाने पर सहमति नहीं दी। कल्पना कीजिए कि ज्योति बसु तीन में से किसी एक अवसर पर प्रधानमंत्री बनते तो उसका लाभ अंततोगत्वा वामदलों को ही मिलता पर आपसी मतभेदों या मनभेदों के चलते सही विकल्प नहीं चुनने का परिणाम आज सामने हैं।

मनोज चतुर्वेदी
संपादक

शुभाशीष

इस तरह की थी शिवाजी महाराज के शासनकाल की आर्थिक नीतियां

शिवाजी महाराज के राज्य में प्रारम्भिक काल में व्यापार बहुत कम मात्रा में होता था और राज्य की अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। इस राज्य में उस समय चौथ एवं सरदेशमुखी, यह दो प्रकार के कर प्रचलन में थे। इतिहास के किसी भी खंडकाल में भारतीय सनातन संस्कृति का अनुपालन करते हुए किए गए समस्त प्रकार के कार्यों में सफलता निश्चित मिलती आई है। ध्यान में आता है कि भारतीय आर्थिक दर्शन भी सनातन संस्कृति के अनुरुप ही रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज भी हमारे वेदों एवं पुराणों में वर्णित नियमों के अनुसार ही अपने राज्य में आर्थिक नीतियों का निर्धारण करते थे। अपनी रियासत के नागरिकों को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं हो और वे परिवार सहित अपने लिए दो जून की रोटी की व्यवस्था आसानी से कर सकें, इसका विशेष ध्यान आपके शासनकाल में रखा जाता था। उस खंडकाल में नागरिकों के लिए रोजगार हेतु कृषि क्षेत्र ही मुख्य आधार था। कृषि गतिविधियों के साथ साथ पशुपालन कर ग्रामों में निवासरत नागरिक अपने एवं अपने परिवार का भरण पोषण सहज रुप से कर पाते थे एवं अति प्रसन्नचित तथा संतुष्ट रहते थे, हालांकि कालांतर में व्यापार एवं उद्योग को भी बढ़ावा दिया जाने लगा था। विश्व के कई भागों में सभ्यता के उदय से कई सहस्त्राब्दी पूर्व, भारत में उन्नत व्यवसाय, उत्पादन, वाणिज्य, समुद्र पार विदेश व्यापार, जल, थल एवं वायुमार्ग से बिक्री हेतु वस्तुओं के परिवहन एवं तत्संबंधी आज जैसी उन्नत नियमावलियां, व्यवसाय के नियमन एवं करारोपण के सिद्धांतों का अत्यंत विस्तृत विवेचन भारत के प्राचीन वेद ग्रंथों में प्रचुर मात्रा में मिलता है। प्राचीन भारत में उन्नत व्यावसायिक प्रशासन व प्रबंधन युक्त अर्थतंत्र के होने के भी प्रमाण मिलते हैं। हमारे प्राचीन वेदों में कर प्रणाली के सम्बंध में यह बताया गया है कि राजा को अत्यधिक कराधान रुपी अत्याचार से विरत रहना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार करों की अधिकता से प्रजा में दरिद्रता, लोभ, असंतोष, विराग आदि भाव उपजते हैं। राजा द्वारा, स्मृतियों द्वारा निर्धारित, कर के अतिरिक्त अन्य कर लगाया जाना निछिद्ध था। कर की मात्रा वस्तुओं के मूल्य एवं समय पर निर्भर होती थी।

डॉ. श्रीमन नारायण मिश्रा
संरक्षक

हिन्दू विवाह पर सर्वोच्च अदालत का फैसला...

स्वागत योग्य

हिंदू विवाह से जुड़ा यह फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी 'गाने और डांस', 'शराब पीने और खाने' का आयोजन या अनुचित दबाव डालकर दहेज और गिफ्ट्स की मांग करने का मौका नहीं है। विवाह कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं है।

देश की सर्वोच्च अदालत ने हिन्दू विवाह को लेकर बड़ा फैसला देकर न केवल हिन्दू विवाह के संस्कारों एवं पारंपरिक रिवाजों को पुष्ट किया है बल्कि उन्हें कानूनी दृष्टि से आवश्यक स्वीकार किया है। आज जबकि हिन्दू विवाह की पवित्रता एवं परम्परा तथाकथित आधुनिक जीवन एवं प्रभाव के कारण धुंधली होती जा रही है, पाश्चात्य संस्कृति की आंधी में हिन्दू विवाह की पवित्रता समाज में समय के साथ घटी है और उसमें सुधार एवं सुदृढ़ता की जरूरत है। जो लोग विवाह को मात्र एक पंजीकरण मानते हैं, उन्हें चेत जाना चाहिए। उन्हें सात फेरों का अर्थ समझना होगा। बिना सात फेरों, हिन्दू रीति-रिवाजों एवं वैवाहिक आयोजनों के कोर्ट की दृष्टि में भी विवाह मान्य नहीं होगा। हिंदू विवाह पर कोर्ट का ताजा फैसला न केवल स्वागतयोग्य है बल्कि इसके दूरगामी परिणाम सुखद होंगे। इससे हिन्दू संस्कृति एवं संस्कारों को बल मिलेगा। पारिवारिक-संस्था को मजबूती मिलेगी।

हिंदू विवाह से जुड़ा यह फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी 'गाने और डांस', 'शराब पीने और खाने' का आयोजन या अनुचित दबाव डालकर दहेज और गिफ्ट्स की मांग करने का मौका नहीं है। विवाह कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं है। यह एक गंभीर बुनियादी सांस्कृतिक एवं पारिवारिक आयोजन है, जिसे एक पुरुष और एक महिला के बीच संबंध बनाने के लिए मनाया जाता है, जो भविष्य में एक अच्छे परिवार के लिए पति और पत्नी का दर्जा प्राप्त करते हैं। यह भारतीय हिन्दू समाज-व्यवस्था की एक बुनियादी इकाई एवं मजबूत सांस्कृतिक एवं पारिवारिक आयाम है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि बिना सात फेरों के हिन्दू विवाह को मान्यता नहीं मिल सकती है अर्थात शादी के लिए हिन्दू विवाह अधिनियम में जो नियम और प्रावधान बनाए गए हैं उसका पालन करना होगा। इस तरह कोर्ट ने अपने फैसले में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत हिंदू विवाह की कानूनी आवश्यकताओं और पवित्रता को स्पष्ट किया है। अधिनियम के अनुसार, एक हिंदू विवाह किसी भी पक्ष के पारंपरिक संस्कारों और समारोहों के अनुसार संपन्न किया जाएगा। समारोहों में सप्तपदी (दूल्हा और दुल्हन द्वारा पवित्र अग्नि के चारों ओर संयुक्त रूप से सात कदम उठाना) शामिल है, और जब वे सातवां चरण एक साथ लेते हैं तो विवाह पूर्ण और बाध्यकारी हो जाता है। कुल मिलाकर हिन्दू विवाह एक संस्था है, संस्कार है और विवाह कोई व्यावसायिक लेन-देन नहीं है।

कोर्ट ने जोर दिया है कि हिंदू विवाह की वैधता के लिए सप्तपदी (पवित्र अग्नि के चारों ओर सात फेरे) जैसे उचित संस्कार और उससे जुड़े समारोह जरूरी है। विवाद की स्थिति में समारोह के प्रमाण पेश करना जरूरी है। कोर्ट की सात फेरों और उससे जुड़े समारोह का मूल्य समझाने की यह कोशिश हिन्दू विवाह को न केवल मजबूती प्रदान करेंगी बल्कि आधुनिकता की आंधी में धुंधलाते मूल्यों को नियंत्रित करने का काम करेगी। इसमें कोई शक नहीं कि विवाह संस्कार का मूल महत्व पहले की तुलना में कम हुआ है, अब विवाह बहुतों के लिए एक दिखावा, मजबूरी या समझौता भर रह गया है। न्यायमूर्ति बी नागरत्ना ने अपने प्रासंगिक एवं उपयोगी फैसले में बिल्कुल सही कहा है कि हिंदू विवाह एक संस्कार है, जिसे भारतीय समाज में एक महान मूल्य की संस्था के रूप में दर्जा दिया जाना चाहिए। पारंपरिक संस्कारों या सात फेरों जैसी रीतियों के बिना हुए विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 के अनुसार हिंदू विवाह नहीं माना जाएगा। इस वजह से कोर्ट ने युवा पुरुषों और महिलाओं से आग्रह किया हैं कि वो विवाह की संस्था में प्रवेश करने से पहले इसके बारे में गहराई से सोचें और भारतीय समाज में उक्त संस्था कितनी पवित्र है, इस पर विचार करें।

प्रश्न है कि हिन्दू विवाह को लेकर कोर्ट को जागरूक होने एवं हिन्दू संस्कारों को मजबूती देने की जरूरत क्यों पड़ी? हिन्दू विवाह से जुड़े संस्कारों एवं पारंपरिक रीति-रिवाजों को लेकर अनेक मामले कोर्ट की चौखट पर आते रहे हैं, हर बार कोर्ट सजगता, दूरदर्शिता एवं विवेक से विवाह-संस्था से जुड़े मामलों पर अपना नजरिया प्रस्तुत करती रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पिछले दिनों यह माना कि हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार, हिंदू विवाह को संपन्न करने के लिए कन्यादान का समारोह जरूरी नहीं है। उस फैसले में भी सप्तपदी के महत्व को दर्शाया गया था। मध्यप्रदेश की एक परिवार अदालत के फैसले में महिला पक्ष को यह समझाया गया था कि सिंदूर लगाना एक विवाहित हिंदू महिला का धार्मिक कर्तव्य होता है। सर्वोच्च न्यायालय के ताजा फैसले में ऐसी ही समझाइश की कोशिश झलकती है। कुल मिलाकर, न्यायालय का संदेश यह है कि फिजूल के तमाशे-दिखावे से बचते हुए विवाह के मूल अर्थ को समझना चाहिए। हिंदू विवाह को लेकर अब ज्यादा स्पष्टता की जरूरत है और विशेषतः हिन्दू संस्कारों एवं संस्कृति को बल देने की भी। क्योंकि भारत में परिवार संस्था कायम है तो इसका कारण हिन्दू संस्कार एवं परम्पराएं ही हैं। इस तरह कोर्ट ने अपने फैसले में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत हिंदू विवाह की कानूनी आवश्यकताओं और पवित्रता को स्पष्ट किया है।

हिन्दू विवाह एक आदर्श परम्परा एवं संस्कार है। हिंदू धर्म में विवाह को सोलह संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है। विवाह = वि $ वाह, अतः इसका शाब्दिक अर्थ है - विशेष रूप से उत्तरदायित्व का वहन करना। पाणिग्रहण संस्कार को सामान्य रूप से हिंदू विवाह के नाम से जाना जाता है। अन्य धर्मों में विवाह पति और पत्नी के बीच एक प्रकार का करार होता है जिसे विशेष परिस्थितियों में तोड़ा भी जा सकता है परंतु हिंदू विवाह पति और पत्नी क बीच जन्म-जन्मांतरों का सम्बंध होता है जिसे किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़ा जा सकता। अग्नि के सात फेरे लेकर और ध्रूव तारा को साक्षी मान कर दो तन, मन तथा आत्मा एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। यह दो परिवारों का भी मिलन है। हिंदू विवाह में पति और पत्नी के बीच शारीरिक संम्बंध से अधिक आत्मिक संम्बंध होता है और इस सम्बंध को अत्यंत पवित्र माना गया है।

हिन्दू विवाह का न केवल पारिवारिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व है, बल्कि उसका गहन आध्यात्मिक महत्व भी है। हिंदू धर्म ने चार पुरुषार्थ (जीवन की चार बुनियादी खोज), यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष निर्धारित किया है। विवाह संस्कार का उद्देश्य 'काम' के पुरुषार्थ को पूरा करना और फिर धीरे-धीरे 'मोक्ष' की ओर बढ़ना है। एक पुरुष और महिला के जीवन में कई महत्वपूर्ण चीजें शादी से जुड़ी होती हैं; उदाहरण के लिए, पुरुष और महिला के बीच प्यार, उनका रिश्ता, संतान, उनके माता-पिता, उनके जीवन में विभिन्न सुखद घटनाएं, सामाजिक स्थिति और समृद्धि। हिंदू समाज में एक विवाहित महिला को अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। उसके माथे पर कुमकुम-सिन्दूर के साथ एक महिला की दृष्टि, उसके गले में एक मंगलसूत्र पहने हुए, हरी चूड़ियाँ, पैर के अंगूठे के छल्ले और छह या नौ-यार्ड साड़ी स्वचालित रूप से एक पर्यवेक्षक के मन में उसके लिए सम्मान उत्पन्न करता है। हिंदू विवाह के सात वचनों में से, कम से कम तीन ऐसे हैं, जहां जोडे अपने बुजुर्गों की देखभाल करने का वादा करते हैं। पांचवां वचन अपनी संतान पैदा करने और उसकी देखभाल करने का है।

हाल के वर्षों में, भारत में हिन्दू विवाह परम्परा एवं संस्कृति से अनेक विसंगतियां एवं विकृतियां जुड़ गयी है, डेटिंग संस्कृति की शुरुआत के साथ, लव-मेरिज का प्रचलन बढ़ा है। संभावित दूल्हा और दुल्हन अपने दम पर जीवनसाथी चुनना पसंद करते हैं। आज के रोमांटिक-रिश्ते वास्तव में विवाह नहीं हैं, बल्कि एक नई प्रथा है, जिसके विपरीत प्रभाव से परिवार-संस्था बिखरने लगी है। विवाह के साथ प्रीवेडिंग का प्रचलन भी अनेक विकृतियों का वाहक बना है, बड़े-बड़े भव्य आयोजन एवं होटल संस्कृति ने भी विवाह की पवित्रता को धुंधलाया है। आयोजनों में शराब एवं अन्य नशों का बड़ा प्रचलन भी दुर्घटनाओं का कारण बना है। जिनके कारण विवाह होने से पहले ही उसमें दरारें पड़ते हुए देखी गयी है।

औसत से ज्यादा वोटिंग क्यों नहीं होती, क्या है वजह...

यह विडंबना ही कही जाएगी कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पंजीकृत मतदाताओं में से चालीस प्रतिशत मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग ही नहीं करते...

मौजूदा लोकसभा चुनाव में औसत मतदान 60 प्रतिशत के आसपास रहना निर्वाचन आयोग ही नहीं, राजनेताओं के लिए भी चिंता का विषय है। इससे लोकतंत्र के मूल उद्देश्य पूरे होते नहीं दिखते। स्थिति यह है कि कुल पंजीकृत मतदाताओं के एक चौथाई हिस्से से भी कम का समर्थन पाकर पार्टियां सरकार बना लेती हैं और फिर पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। उत्तर और पश्चिम इलाकों में, जहां इस समय प्रचंड गर्मी है, वहां तो कम मतदान हो ही रहे हैं, पर्वतीय क्षेत्रों और दक्षिण राज्यों, जहां गर्मी नहीं है, में भी मतदाताओं में उत्साह नहीं नजर आता है। इसकी एक वजह राजनीतिक व्यवस्था से मोहभंग भी हो सकता है।

निर्वाचन आयोग और राजनीतिक दलों की तरफ से मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने के तमाम प्रयास किए जाते हैं। लोगों को अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रेरित किया जाता है, लेकिन इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। कुछेक अपवादों को छोड़ दें, तो कभी वोटिंग औसत से ज्यादा नहीं बढ़ी। सिर्फ 2014 और 2019 में मतदाताओं ने उत्साह दिखाया था और औसतन 66 प्रतिशत से ज्यादा मतदान हुआ था।

सवाल यह है कि ऐसे में क्या उपाय किए जाएं कि मतदाता मतदान करने के लिए प्रेरित हों। कम वोटिंग भारत ही नहीं, दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों के लिए चिंता का विषय है। कई देशों ने मताधिकार का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया, तो कुछ देशों ने मतदान नहीं करने पर अलग-अलग तरह से दंड लगाने के कानून बनाए। हालांकि कुछ देशों ने बाद में व्यावहारिक परेशानियों के चलते इसे रद्द कर दिया।

सबसे पहले बेल्जियम ने 1892 में वोटिंग अनिवार्य करने का कानून बनाया। फिर अर्जेंटीना ने 1914 में और ऑस्ट्रेलिया ने 1924 में ऐसा ही कानून लागू किया। उसके बाद ऑस्ट्रिया, ब्राजील, मिस्र, फिजी, बुल्गारिया, बोलीविया, इटली, ग्रीस, फ्रांस (सिर्फ सीनेट), अमेरिका (कुछ राज्य), मैक्सिको, फिलीपीन, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, स्पेन, तुर्किये, वेनेजुएला, पेरू, पनामा आदि ने भी कानून बनाए। इनमें कुछ देशों ने कानून को आंशिक या पूर्ण रूप से रद्द कर दिया।

भारत की स्थिति कुछ भिन्न है। यहां कई बार वोटिंग अनिवार्य करने को लेकर लोकसभा में चर्चा हुई। यही निष्कर्ष निकला कि ऐसा करना व्यावहारिक नहीं होगा। इस संबंध में सबसे पहले चर्चा 1950 में तब शुरू हुई, जब जनप्रतिनिधित्व अधिनियम लागू किया जा रहा था। डॉ. भीमराव आंबेडकर सहित संविधान सभा के कई सदस्यों ने इसे सिरे से नकार दिया। 1990 में दिनेश गोस्वामी कमेटी ने वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के उपायों पर विचार करने के दौरान इसे अनिवार्य किए जाने पर भी गौर किया और अंततः इसे नामंजूर कर दिया। वर्ष 2001 में कंसल्टेशन पेपर ऑफ नेशनल कमीशन रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कंस्टीट्यूशन ने इस मुद्दे पर विचार करने के बाद कहा कि वोट नहीं देने पर दंड का प्रावधान रखने से कई जटिलताएं पैदा होंगी। चुनावी खर्च को लेकर गठित तारकुंडे कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि वोटिंग अनिवार्य करने से मतदाताओं में रोष पैदा होगा और इसके दुरुपयोग की आशंका रहेगी। बेहतर होगा कि वोटरों को मतदान के लिए उत्साहित किया जाए।

लोकसभा में 2004 , 2009, 2012 एवं 2014 में प्राइवेट बिल पेश किए गए, लेकिन हर बार प्रस्ताव का विरोध हुआ। वर्ष 2009 में इस पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका पेश की गई, जिसमें मताधिकार का उपयोग नहीं करने वाले के घर की बिजली, पानी आदि काटने और आर्थिक दंड लगाने की मांग की गई। कोर्ट ने इसे बेहद अमानवीय बताकर याचिका खारिज कर दी। देश में चुनावों में अशिक्षित और अल्पशिक्षित मतदाताओं में मतदान को लेकर जितना उत्साह दिखता है, उतना प्रबुद्ध वर्ग में नहीं। प्रबुद्ध वर्ग का एक बड़ा हिस्सा आलस और अरुचि की वजह से घर से नहीं निकलता। वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी होना भी कम मतदान का एक कारण है। चुनाव से पहले मतदाता सूची को ठीक से अपडेट नहीं किया जाता और किया भी जाता है, तो उनमें कई त्रुटियां दिखती हैं। लोगों को शिकायत रहती है कि नाम शामिल करने, संशोधन आदि का फॉर्म बूथ लेवल अफसर (बीएलओ) को समय पर देने के बाद भी कुछ नहीं होता। यह विडंबना ही कही जाएगी कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पंजीकृत वोटरों में से 40 प्रतिशत वोट ही नहीं देते।

क्या कांग्रेस का भरोसेमंद चेहरा बनकर उभरीं प्रियंका गांधी...

प्रियंका गांधी के राजनीतिक भविष्य को लेकर कांग्रेस में हमेशा से असमंजस की स्थिति रही है। कहा तो यहां तक जाता है कि गांधी परिवार राहुल और प्रियंका के बीच अनजाने में ही कोई राजनीतिक रस्साकशी की स्थिति पैदा नहीं होने देना चाहता, इसी कारण से अब तक प्रियंका गांधी को चुनावी पिच पर नहीं उतारा गया है।

इस चुनाव में कांग्रेस को अंतिम रूप से क्या हासिल होने जा रहा है, यह तो चार जून को ही पता चलेगा, लेकिन अब तक की परिस्थितियों से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस एक बार फिर मजबूत वापसी कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो इसका पूरा श्रेय उस राहुल गांधी को जाएगा, जो हार की अंतहीन श्रृंखला के बाद भी न तो कमजोर पड़े और न ही अपने उद्देश्य से डिगे। इस चुनाव में प्रियंका गांधी ने जो क्षमता दिखाई है, उसने कांग्रेस और राहुल गांधी को एक भरोसेमंद साथी दे दिया है, जिनके भरोसे राहुल गांधी महत्त्वपूर्ण कार्य छोड़कर अपना पूरा ध्यान देश की राजनीति पर दे सकेंगे। रायबरेली और अमेठी में पूरे चुनाव की कमान अपने हाथ में संभालकर प्रियंका गांधी ने अपनी इस क्षमता का परिचय भी दे दिया है। कांग्रेस के जानकार इसे पार्टी की एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं। प्रियंका गांधी के राजनीतिक भविष्य को लेकर कांग्रेस में हमेशा से असमंजस की स्थिति रही है। कहा तो यहां तक जाता है कि गांधी परिवार राहुल और प्रियंका के बीच अनजाने में ही कोई राजनीतिक रस्साकशी की स्थिति पैदा नहीं होने देना चाहता, इसी कारण से अब तक प्रियंका गांधी को चुनावी पिच पर नहीं उतारा गया है। लेकिन जिस तरह उन्होंने यूपी विधानसभा चुनाव से ही कांग्रेस पार्टी का कार्यभार संभाला था, इस बात की उम्मीद जताई जाने लगी है कि अब प्रियंका गांधी की सक्रिय राजनीति में एंट्री में बहुत देर नहीं है। अब अनुमान यही लगाया जा रहा है कि यदि राहुल गांधी वायनाड के साथ-साथ रायबरेली से भी चुनाव जीतते हैं, तो उन्हें एक सीट छोड़नी पड़ेगी, और प्रियंका गांधी को इसी सीट से मैदान में उतारा जा सकता है।

प्रधानमंत्री पर हमला कर बटोरी सुर्खियां : वर्तमान लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हुई हैं, उसे लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं की जा रही हैं। उनके आक्रामक तेवर कांग्रेसियों को खूब भा रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की राजनीति का जवाब देने के लिए कांग्रेस को जिस आक्रामक नेता की आवश्यकता थी, वह प्रियंका गांधी के रूप में उन्हें पूरी होती दिखाई दे रही है। देश के सामान्य कांग्रेस समर्थक जनता के बीच लोगों को इसमें इंदिरा गांधी की छवि भी दिखाई दे रही है। लोगों की यह भावना कांग्रेस को मजबूती दे सकती है। प्रियंका गांधी ने भाजपा पर हमलावर होने में अपनी राजनीतिक परिपक्वता भी दिखाई है। एक निजी चैनल को दिए गए एक साक्षात्कार के दौरान जब उनसे यह पूछा गया कि भाजपा नेताओं का यह आरोप है कि कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसलिए स्वीकार नहीं कर पाती, क्योंकि वे एक गरीब परिवार से हैं। इस पर प्रियंका गांधी ने जवाब दिया कि उन्हें इस बात का गर्व है कि कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्रियों ने एक ऐसे लोकतंत्र की नींव रखी जिसमें एक गरीब चाय वाला भी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकता है। इस जवाब से प्रियंका गांधी ने सफलतापूर्वक यह साबित कर दिया कि यदि आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तो ऐसा सिस्टम विकसित करने का श्रेय कांग्रेस को जाता है। ऐसा सिस्टम उसी नेहरू-इंदिरा की राजनीति को जाता है, जिसके खिलाफ भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हमलावर रहते हैं। प्रियंका गांधी ने इस जवाब में अप्रत्यक्ष तरीके से भाजपा पर हमला भी कर दिया कि वह ऐसा सिस्टम विकसित नहीं कर पा रही है, जिसमें कोई सामान्य गरीब आगे बढ़ने की बात सोच सकता है। प्रियंका गांधी की इस क्षमता ने उनके आलोचकों को भी अपना प्रशंसक बना दिया है।

इसी तरह प्रियंका गांधी ने साक्षात्कार में आम लोगों के जीवन में टीवी पर एक अलग इंडिया और असलियत में दूसरा इंडिया होने की बात कही है। यह उस असमानता को दिखाने के लिए पर्याप्त है, जिसके बारे में वे लगातार विभिन्न मंचों से आवाज उठती रही हैं। उनकी इसी क्षमता को देखते हुए अनेक लोग ऐसा मानते हैं कि यदि प्रियंका गांधी को आगे बढ़ने का अवसर दिया जाता है, तो वे एक बेहतर राजनेता साबित हो सकती हैं।

नई कांग्रेस का भविष्य बेहतर

उनके आलोचकों का तर्क रहता है कि जब यूपी विधानसभा चुनाव में उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी, प्रियंका गांधी अपने आपको साबित नहीं कर सकीं। उनकी अगुवाई में मजबूती से लड़ी कांग्रेस को उस चुनाव में सबसे कम वोट शेयर और सबसे कम सीटों पर रह जाना पड़ा था। लेकिन राजनीतिक आलोचक विवेक सिंह का मानना है कि उस चुनाव में जनता, विशेषकर पूरा मुस्लिम समुदाय भाजपा के विकल्प के रूप में सपा को आजमाने की सोच बैठा। इस कारण प्रियंका गांधी की पूरी मेहनत का लाभ सपा को मिल गया। विवेक सिंह के अनुसार, लेकिन अब राहुल गांधी और प्रियंका प्रियंका गांधी जिस तरह मजबूती से लोगों के सामने आई हैं, गैर भाजपाई वोटरों के दावेदार के रूप में कांग्रेस एक बार फिर सबसे बड़ी दावेदार पार्टी साबित हो सकती है। ऐसे में यदि राहुल और प्रियंका मजबूती से आपसी तालमेल बेहतर करते हुए चुनाव आगे बढ़ें, तो कांग्रेस का नया सूर्योदय हो सकता है। उन्हें लगता है कि रायबरेली और अमेठी का चुनाव परिणाम सामने आने के बाद प्रियंका गांधी के राजनीतिक भविष्य की तस्वीर ज्यादा साफ हो सकती है।

पाकिस्तान के शोषण के कारण पीओके की जनता हुई बेहाल

कब्जे वाले क्षेत्र की वापसी का वक्त आ गया

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में पिछले कुछ दिनों से आटे की आसमान छूती कीमत और बिजली के बिल में अप्रत्याशित बढ़ोतरी के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन जारी है। वहां की बदहाली का मुख्य कारण पीओके के साथ पाकिस्तान का सौतेला व्यवहार है। पाकिस्तान पीओके के संसाधनों की लगातार लूट में लगा है। इसी नीति के विरोध में यह प्रदर्शन उग्र रूप ले चुका है। लोगों का कहना है कि पीओके स्थित मंगला बांध से उत्पादित बिजली की पाकिस्तान में आपूर्ति की जाती है। हमें मिलने वाली सब्सिडी बंद कर बिजली के बिल में अप्रत्याशित बढ़ोतरी की गई है।

पीओके स्थित मंगला से बांध दो से ढाई हजार मेगावाट बिजली पैदा होती है। इसकी उत्पादन लागत दर ढाई से तीन रुपये प्रति यूनिट है और पाकिस्तान सरकार उपभोक्ताओं से 50 से 60 रुपये प्रति यूनिट वसूल करती है। इस आंदोलन का नेतृत्व जम्मू-कश्मीर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी कर रही है। आंदोलन को कुचलने के लिए हजारों की संख्या में रेंजर्स तैनात किए गए हैं। इसमें दोनों तरफ से हुई झड़पों में आंदोलनकारी, रेंजर्स और पुलिस कर्मचारी मारे गए हैं। अब इस मुद्दे की गूंज ब्रिटेन और कई देशों में पहुंच गई है। ब्रिटेन में पाकिस्तान कश्मीर पीपुल्स पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान वाणिज्य दूतावास के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया है।

सूत्रों के अनुसार, अब मुजफ्फराबाद में हेलीकॉप्टरों के माध्यम से सेना के कमांडो की तैनाती की जा रही है, जिससे हिंसा और जान-माल के नुकसान की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। पीओके के हालात अब इतने बदहाल हो गए हैं कि वहां के लोग पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ खुली बगावत पर उतर आए हैं। वे खुलेआम कह रहे हैं कि 'हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, कम से कम हमें वहां दो वक्त की रोटी तो मिल जाएगी। यहां जीना दूभर हो गया है। यहां के प्राकृतिक संसाधनों को पाकिस्तान लूट रहा है। वह अपनी जरूरत की चीजें निकाल कर ले जाता है, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता।'

गौरतलब है कि विगत 10 मई को वहां भारतीय तिरंगा लहराए गए। कई जगह पर 'हमें भारत से मिला दो' के नारे लिखे हुए पोस्टर भी लगाए गए। दरअसल पीओके के लोग देख रहे हैं कि जम्मू-कश्मीर के निवासी शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में खुशहाली और विकास की नई लहर चल पड़ी है। हाल ही में हुए संसदीय चुनाव में जम्मू-कश्मीर में 38 फीसदी का रिकॉर्ड मतदान हुआ, जो पहले हुए मतदानों से काफी ज्यादा है।

पाकिस्तान की सरकार ने पीओके को 23 अरब पाक रुपये का अनुदान दिया है, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। हकीकत तो यह है कि पीओके के लोग पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। इसलिए अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पीओके जाकर बातचीत के जरिये वहां की समस्याओं का हल निकालना चाहते हैं। अब देखना होगा कि उनकी बातचीत क्या रंग लाएगी। देखा जाए, तो 1947 के बाद भारत की किसी भी सरकार ने पीओके को पाकिस्तान के कब्जे से छुड़ाने की कोई कोशिश नहीं की। लेकिन हमारी मौजूदा मोदी सरकार के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री ने पीओके के संजीदा हालात को देखते हुए कहा है कि पीओके भारत का हिस्सा है और हम इसे हर हाल में पाकिस्तान के चंगुल से निकाल कर रहेंगे।

उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत इसे वापस लेने के लिए ठोस कदम उठाएगा, ताकि इसके दूसरे हिस्से को जम्मू-कश्मीर के साथ मिलाया जा सके। अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर के हालात काफी बेहतर हुए हैं। इससे पहले संसद में दो प्रस्ताव भी पास हो चुके हैं। अब पाकिस्तान से हिसाब लेने का समय आ गया है। पीओके में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई वहां के युवाओं को हथियार और प्रशिक्षण देकर भारत के खिलाफ भड़काती है और जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ करा रही है। पीओके में आतंकियों के प्रशिक्षण शिविर भी बने हुए हैं। अगर पीओके को कब्जे से छुड़ा लिया गया, तो ये शिविर बंद हो जाएंगे। उम्मीद करनी चाहिए कि आगामी चार जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जब नई सरकार का गठन हो जाएगा, तो इसके तुरंत बाद सरकार अपने एजेंडे में पीओके की वापसी को प्राथमिकता में रखेगा।

हम कब बंद करेंगे प्लास्टिक का उपयोग?

यूएन की बाध्यकारी संधि जैसी पहल के बाद भी सवाल का जबाव मिलना बाकी

प्लास्टिक प्रदूषण से दुनिया का कोई भी राष्ट्र अछूता नहीं है... यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र ने एक बाध्यकारी संधि की पहल की है...

हाल ही में कनाडा की राजधानी ओटावा में प्लास्टिक प्रदूषण पर अंतरराष्ट्रीय संधि के लिए गहन मंथन के बाद राष्ट्रों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि के प्रारूप पर सहमति बनी, जो इसी वर्ष के अंत में बुसान में होने वाली बैठक में सहभागियों के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। प्लास्टिक प्रदूषण से दुनिया का कोई भी राष्ट्र अछूता नहीं है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र एक बाध्यकारी संधि के लिए पहल की है।

प्लास्टिक प्रदूषण से समस्त मानवता और जैविक सभ्यता निरंतर प्रभावित हो रही है। 20वीं सदी की महान उपलब्धि प्लास्टिक धीरे-धीरे संपूर्ण मानव सभ्यता व प्रकृति के लिए एक बड़े संकट के रूप में प्रकट हो गई है। पिछले कुछ वर्षों में एक ही बार उपयोग में आने वाली प्लास्टिक सामग्री पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन अब भी प्रतिवर्ष 600 अरब डॉलर मूल्य का करीब 40 करोड़ टन प्लास्टिक का उत्पादन हो रहा है। यह उत्पादन 2050 तक करीब 100 करोड़ टन प्रतिवर्ष से भी बढ़ जाएगा। तथ्य यह है कि जितने प्लास्टिक का उत्पादन हो रहा है, उसके नौ फीसदी की ही रीसाइक्लिंग हो पा रहा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार, अधिकांश प्लास्टिक या तो खुले में जलाया जा रहा है या यत्र-तत्र फेंक दिया गया है। दीर्घ आयु होने के नाते इसका निरंतर उपयोग या दुरुपयोग होता रहता है। इन्हीं वजहों से वर्ष 2040 तक सभी प्रकार के प्लास्टिक उत्पादन को 60 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है, अन्यथा यह चक्र कभी रुकने वाला नहीं है। प्लास्टिक के समर्थक तर्क देते हैं कि इससे 3.5 फीसदी ही कार्बन उत्सर्जन होता है, लेकिन प्लास्टिक की पहुंच और भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पश्चिम प्रशांत महासागर में 36,000 फुट की गहराई और माउंट एवरेस्ट की 29,000 फुट ऊंचाई तक प्रचुर मात्रा में प्लास्टिक पाया गया है। यह तो वह प्लास्टिक है, जो हम प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं। व्यापक जनजागृति और तमाम प्रयासों के बावजूद हम अपने शरीर में जगह बना चुके प्लास्टिक से बेखबर हैं। हमें इसका जरा भी इल्म नहीं है कि प्लास्टिक के साथ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कई प्रकार के रसायन हमारे शरीर में प्रवेश कर चुके हैं। संभवतः इस पृथ्वी पर अब ऐसा कोई भी स्थान शेष नहीं है, जहां प्लास्टिक न हो। भोजन, पानी, वस्त्र, आदि के जरिये प्लास्टिक के सूक्ष्म कण हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। यहां तक कि सौंदर्य प्रसाधन एवं स्वास्थ्य रक्षा हेतु भी प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है। बीस वर्ष पूर्व पहली बार छोटे प्लास्टिक यानी 2-5 मिलीमीटर आकार वाले प्लास्टिक के कणों की खोज हुई, जो प्लास्टिक के बड़े टुकड़ों के टूटने से बने थे। फिर नैनो प्लास्टिक का पता चला, जो अत्यंत ही सूक्ष्म आकार के होते हैं। नैनो प्लास्टिक अपने सूक्ष्म आकार के कारण सामान्य दृष्टि से ओझल रहते हैं और विभिन्न माध्यमों से हमारे शरीर में पहुंचकर ऊतकों में जमा हो जाते हैं तथा दूरगामी असर पैदा करते हैं। विभिन्न अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि बढ़ते कैंसर, दिमागी रक्तस्राव जैसी गंभीर अवस्थाओं के लिए प्लास्टिक भी बहुत बड़ा कारक है।

प्लास्टिक मुक्त वातावरण की संकल्पना के लिए सबसे बड़ा अवरोध है इसका सार्थक विकल्प न होना। यदि कुछ विकल्प सुझाए भी गए हैं, तो वे सुगमता की कसौटी पर प्लास्टिक से कोसों दूर हैं। बहरहाल इस विकट समस्या से निजात पाने के लिए जरूरी है, प्लास्टिक की रीसाइक्लिंग व पुनः उपयोग की व्यवस्था को सुदृढ़ करना। भारत में स्वच्छ भारत अभियान के बाद प्लास्टिक उपयोग में सांकेतिक रूप से कमी आई है। अनेक स्टार्ट अप के माध्यम से प्लास्टिक संग्रहण, पृथकीकरण एवं पुनः उपयोग के कार्यों में तेजी आई है। लेकिन ये सभी प्रयास सूक्ष्म एवं नैनो प्लास्टिक को रोकने में कहीं कारगर नहीं है। जब तक हर व्यक्ति निजी स्तर पर प्लास्टिक के उपयोग से परहेज नहीं करेगा, तब तक इससे निजात पाना असंभव है।

नीतिगत स्तर पर प्लास्टिक उत्पादन में कमी लाने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। जब तक प्लास्टिक के उपयुक्त विकल्प नहीं मिलते, रीसाइकल एवं अपसाइकल को प्रोत्साहित करने की नीति अपनानी होगी। खुले में छूटा प्लास्टिक सृष्टि पर आक्रमण की क्षमता रखता है। विनाश से बचने के लिए हर व्यक्ति को उत्तरदायी होना होगा। प्लास्टिक का न्यूनतम अथवा वर्जित उपयोग सबके हित में है।

राष्ट्रहित के लिए युवा शक्ति का मतदान...

सात चरणों में पूर्ण होने वाले इस वर्ष के लोकसभा के ये चुनाव देश के इतिहास के सबसे बड़े चुनाव होंगे

किसी भी राष्ट्र की विकास यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव आते है और आज भारत विश्व में जिस गति से आगे बढ़ रहा है उसमे युवाओं की महती भूमिका है। अर्थव्यस्था, विज्ञान, अनुसंधान, खेल, राजनीति, रणनीति, सुरक्षा कोई भी क्षेत्र आज युवाओं से अछूता नहीं है।

भारत इन दिनों अपना सबसे बड़े और पावन पर्व का आयोजन बड़े धूमधाम से कर रहा है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में भारत के नागरिक अपने राष्ट्र को सशक्त और मजबूत सरकार देने के प्रयास में लगे हैं। सात चरणों में पूर्ण होने वाले इस वर्ष के लोकसभा के ये चुनाव देश के इतिहास के सबसे बड़े चुनाव होंगे। जिसमे से पहले चरण का मतदान पूर्ण हो चुका है, शेष अभी बाकी हैं। बैसे तो 18 वर्ष के ऊपर के सभी मतदाता अपने मत का प्रयोग करते ही हैं, परन्तु हम सभी जानते हैं कि भारत युवाओं का देश है, यंगिस्तान कहे जाने वाले अपने भारत में आज लगभग 66% युवा मतदाता हैं। मतदाताओं का ये प्रतिशत किसी भी राष्ट्र की दशा और दिशा बदलने के लिए पर्याप्त है। आज भारत का युवा पहले के मुकाबले अपने राष्ट्र के प्रति और अधिक जागरूक और सक्रिय हो गया है। इसका अंदाजा अपने इर्द गिर्द हो रही कुछ घटनाओं को देखकर लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे गतवर्ष महिला समन्वय की तरफ से ब्रज प्रान्त में महिला सम्मलेन और इस वर्ष उसी क्रम में तरुणी और युवा सम्मेलनों का आयोजन कई स्थानों पर कराया गया था। सम्मेलनों में संख्या विशेषकर युवा तरुणियों की बढ़ती संख्या इस बात की ओर इशारा तो कर रही थी कि कहीं न कहीं हमारा युवा मतदाता अपने राष्ट्र की उन्नति को लेकर बेहद संवेदनशील रवैया अपना रहा है। फैशन, कैरियर, टेक्नोलॉजी के साथ अब भारत का युवा अपनी संस्कृति और राष्ट्र के हित को लेकर भी जागरूक है। इस बात पर पक्की मुहर तब लग गयी जब चुनाव आयोग ने इस वर्ष के आकडे जारी किये और उसमे मतदाता सूची के पुनरीक्षण में स्पष्ट किया गया कि 18 से 29 साल के आयु वर्ग में 2.63 करोड़ नये मतदाताओं ने पंजीकरण कराया है इसमें भी महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक रही। ये बड़े ही हर्ष का विषय है कि युवाओं विशेषकर महिलाओं में अपने राष्ट्र के प्रति ये विजन देखने को मिल रहा है।

समाज में आज युवा-वर्ग भारत की हर राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्थिति, परिस्थिति और इसके साथ ही इन सभी में भारत की भूमिका को देखते हुए बहुत गंभीरतापूर्वक विचार कर रहा है। अब वह समय नहीं जब युवा अपने सिलेबस से बाहर की बात कहकर अनदेखा कर दिया करता था बल्कि इसके उलट अब वह समाज में सामाजिक कार्यों से जुड़कर किस प्रकार की भूमिका हमारी होनी चाहिए ? इस बात पर विचार करता है। किसी भी राष्ट्र को तभी पूरी दुनिया सम्मान से देखती है और सम्मान देती है जब वह अपनी संस्कृति, विरासत पर गर्व करते हुए आगे बढता है। यह बात अब भारत का युवा जान चुका है और इसमें कोई संदेह भी नहीं कि युवा ही हमारे राष्ट्र का भविष्य हैं। आज भारत युवा शक्ति समपन्न राष्ट्र है, इतनी युवा शक्ति तो भारत के पास तब भी नहीं थी जब हमने आज़ादी पायी थी। ज़रा विचार कीजिये इतनी विशाल युवा-शक्ति यदि कुछ करने की ठान ले तो वह भारत को किस ऊंचाई पर ले जा सकती है। आज का युवा देश की तरक्की देख रहा है, सम्पूर्ण विश्व में भारत की साख पर गर्व भी महसूस कर रहा है। इसके साथ ही एक और शक्ति को भी अपने अन्तेमन में महसूस कर रहा है वो है भारत की आध्यात्मिक शक्ति। यह स्पष्ट है कि युवा शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति को महसूस कर पूर्ण सम्मान के साथ उसका समर्थन भी कर रही है। ये दोनों विश्व की महानतम शक्तियां हैं और इतिहास साक्षी है कि जब जब दो पावन शक्तियों का संयोग हुआ है तब तब इतिहास रच गया है। यह हमारा सौभाग्य ही है कि ये दो महान शक्तियां केवल भारत के पास ही हैं।

विवेकानंद द्वारा रचित कर्मयोग में कर्म के रहस्य का ज्ञान का वर्णन किया गया है जिसमें सत्व, रजो और तम इन तीनों गुणों का सम्बन्ध मुख्यतः कर्मयोग से बताया गया है। कर्मयोग ही हमें यह शिक्षा देता है कि तीनो गुणों का उचित उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, हम अपना कार्य अच्छी प्रकार कैसे करें साथ ही यदि हम लोग सुसंस्कृत, सुशिक्षित हैं तो हमें चिंतन, दर्शन, कला और विज्ञान में आनंद मिलता है इसके साथ ही धार्मिक चिंतन के अभ्यास में भी अलग ही आनंद है बल्कि स्वामी विवेकानंद जी ने तो अध्ययन के रूप में भी धर्म को अत्यंत आवश्यक माना है। क्योंकि यह सर्वविदित है कि युवा सहज ही चिंता, तनाव, अवसाद से घिर जाता है तब आध्यात्म ही सबसे उपयुक्त मार्ग है जिसके माध्यम से सकारत्मक सोच और रचनात्मक द्रष्टिकोण प्राप्त किया जा सकता है। आध्यात्मिक होने का मतलब ये कदापि नहीं कि आपको संन्यास की ओर ले जाया जा रहा है बल्कि आध्यात्म के माध्यम से जीवन को बेहतर बनाने का तरीका हमारे शास्त्रों में बताया गया है। आज का युवा भी इन्ही सब आध्यात्मिक बातों का निरंतर चिंतन करते हुए आगे बढ़ रहा है।

किसी भी राष्ट्र की विकास यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव आते है और आज भारत विश्व में जिस गति से आगे बढ़ रहा है उसमे युवाओं की महती भूमिका है। अर्थव्यस्था, विज्ञान, अनुसंधान, खेल, राजनीति, रणनीति, सुरक्षा कोई भी क्षेत्र आज युवाओं से अछूता नहीं है। इसी महती भूमिका का निर्वहन हमें मतदान वाले दिन भी करना है। राष्ट्र हित में दिया गया हमारा एक वोट एक शक्तिशाली राष्ट्र की गारंटी है। 66% जैसे बड़े प्रतिशत के साथ आध्यात्मिक शक्ति को साथ लेकर हम जो भी संकल्प ले लेंगे उसे रोकने की किसी में हिम्मत नहीं है। आज हमारे राष्ट्र को हमारे मत के रूप में हमारी आवश्यकता है।

एक स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत को एक शक्तिसंपन्न सरकार देना भी हम युवाओं का ही उत्तरदायित्व है। आइये हम सभी संकल्प लें की लोकतंत्र के इस महान पर्व को उत्सव के रूप में मनाते हुए, राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका सुनिश्चित करते हुए हम सभी मतदान करेगे और करवाएगें।

भारत में कौन डाल सकता है वोट, यह संवैधानिक अधिकार है या मौलिक ?

1950 में 'सार्वभौमिक मताधिकार' की अवधारणा के तहत भारत के नागरिकों को पूर्ण मतदान अधिकार की गारंटी दी गई। सभी भारतीय जो वोट देने के पात्र हैं, उनके पास वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने और राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर है।

वोट देने का अधिकार मौलिक अधिकार है या संवैधानिक अधिकार, यह हमेशा से बहस का विषय रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वोट देने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। अब, फैसले ने एक सवाल खड़ा कर दिया है कि 'मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार क्यों है?' मतदान का अधिकार भारत के संविधान में अनुच्छेद 326 के तहत उल्लिखित है। वे अधिकार जो भारतीय संविधान में निहित हैं और भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, और भाग III के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं, संवैधानिक अधिकारों के रूप में जाने जाते हैं। चूँकि वोट देने का अधिकार संविधान के अंतर्गत वर्णित है न कि मौलिक अधिकारों की श्रेणी में, इसलिए इसे संवैधानिक अधिकार कहा जाता है।

भारत में वोट देने का अधिकार

1950 में 'सार्वभौमिक मताधिकार' की अवधारणा के तहत भारत के नागरिकों को पूर्ण मतदान अधिकार की गारंटी दी गई। सभी भारतीय जो वोट देने के पात्र हैं, उनके पास वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने और राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर है। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिक, जाति, धर्म, सामाजिक वर्ग या आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना, भारतीय संविधान के तहत वोट देने के हकदार हैं। एक मतदाता के रूप में आपके पास विशेषाधिकार हैं, जिनकी गारंटी संविधान द्वारा दी गई है, जो मतदाता अधिकारों की रक्षा करता है। यह उन शर्तों को भी स्थापित करता है जिन पर नागरिक इस अधिकार के हकदार हैं। 1988 के 61वें संवैधानिक संशोधन ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के लिए मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी।

कौन मतदान कर सकता है?

भारतीय संविधान के अनुसार, वे सभी भारतीय नागरिक जिन्होंने मतदान के लिए पंजीकरण कराया है और जिनकी आयु अठारह वर्ष से अधिक है, मतदान करने के हकदार हैं। ये लोग नगरपालिका, राज्य, जिला और स्थानीय सरकारी निकायों के चुनावों में मतदान करने के पात्र हैं। किसी को भी मतदान करने से तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक कि वह अयोग्यता की आवश्यकताओं को पूरा न कर ले। प्रत्येक मतदाता को केवल एक वोट डालने की अनुमति है। योग्य मतदाताओं को फोटो चुनाव पहचान पत्र या ईपीआईसी कार्ड प्राप्त करने के लिए उस निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकरण कराना होगा जिसमें वे अब रहते हैं। यदि कोई पंजीकृत नहीं है या उसके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो उसका चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना निषिद्ध है।

मतदान अधिकार

भारतीय संविधान द्वारा मतदान को लेकर कुछ अधिकार भी दिए गए है।

1) जानने का अधिकारः प्रत्येक मतदाता को चुनाव में खड़े उम्मीदवारों के बारे में जानकारी पाने का अधिकार है।

2) वोट न देने का अधिकार (नोटा): मतदाताओं को वोट न डालने का विकल्प दिया गया है, और इसे सिस्टम में नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) के रूप में नोट किया गया है।

3) अस्वस्थ और अशिक्षित मतदाताओं को विशेष सहायताः जो मतदाता शारीरिक विकलांगता या किसी अन्य प्रकार की दुर्बलता के कारण मतदान करने में असमर्थ हैं और जो डाक मतपत्र का उपयोग करने में असमर्थ हैं, वे निर्वाचन अधिकारी से विशेष सहायता का अनुरोध कर सकते हैं, जो उनका रिकॉर्ड करेगा। चुनाव संहिता के दिशानिर्देशों के अनुसार मतदान करें।

विरासत के सहारे जीत की तलाश करते हुए राहुल...

कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी के नामांकन जमा करने के समय जिस प्रकार से बड़े नेताओं का जमघट लगा, वह भले ही जनता में प्रभाव डालने के लिए किया हो, लेकिन इससे यह भी राजनीतिक सन्देश सुनाई दे रहा है कि अब रायबरेली की सीट भी कांग्रेस के लिए आसान नहीं है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी उत्तरप्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव न लड़ पाने की हिम्मत के बाद आखिर परम्परागत रायबरेली से नामांकन दाखित कर दिया। यह बात सही है कि राहुल गांधी के अमेठी छोड़ने के बाद कांग्रेस राजनीति में कोई ठोस सन्देश देने में सफल नहीं हो रही थी, जिसके कारण कांग्रेस के कई नेता अमेठी के बारे में बोलने से किनारा करने लगे थे। अब राहुल गांधी अपने दादा फिरोज खान, दादी इंदिरा गांधी और माँ सोनिया गांधी की विरासत को बचाने के लिए मैदान में आ गए हैं। यहाँ सवाल यह नहीं हैं कि राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस ने रायबरेली को क्यों चुना, बल्कि सवाल यह है कि राहुल गांधी ने अमेठी को क्यों छोड़ा। क्या वास्तव में राहुल गांधी को फिर से अपनी पराजय का डर लगने लगा था? अगर यह सही है तो फिर ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी हर बार अपने लिए सुरक्षित स्थान की तलाश क्यों करते हैं। उल्लेखनीय है कि जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अमेठी में अपनी जमीन खिसकती दिखाई दी, तब उन्होंने एकदम सुरक्षित लगने वाली सीट केरल की वायनाड को चुना। वहाँ से चुनाव जीते जरूर, लेकिन अमेठी की हार कांग्रेस परिवार की हार थीं, जिसे कांग्रेस आज तक भुला नहीं पायी है। ऐसे में कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ाना खतरे से खाली नहीं था।

कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी के नामांकन जमा करने के समय जिस प्रकार से बड़े नेताओं का जमघट लगा, वह भले ही जनता में प्रभाव डालने के लिए किया हो, लेकिन इससे यह भी राजनीतिक सन्देश सुनाई दे रहा है कि अब रायबरेली की सीट भी कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। यह इसलिए भी कहा जा सकता है कि वहाँ लगभग सभी बड़े नेता उपस्थित हुए। यहाँ तक कि प्रियंका वाड्रा के पति रोबर्ट वाड्रा भी कांग्रेस के विरासती राजनेता के तौर पर उपस्थित हुए। ऐसे में एक सवाल यह भी आता है कि एक ही परिवार के चार व्यक्तियों को कांग्रेस के बड़े नेताओं के रूप में प्रचारित करना निसंदेह कांग्रेस पर परिवारवादी होने को ही प्रमाणित करता है। जिस परिवारवाद के आरोप के कारण कांग्रेस असहज हो जाती है, आज कांग्रेस ने फिर से उसी रास्ते पर कदम बढ़ाने को अपनी नियति मान लिया है। हालांकि कांग्रेस ने आनन फानन में राहुल गांधी को रायबरेली से उम्मीदवार बनाकर यह तो सन्देश दिया ही है कि भारत में रायबरेली ही राहुल गांधी के लिए सबसे सुरक्षित लोकसभा सीट है।

यहाँ कांग्रेस का परम्परागत मतदाता है, वहीं यह क्षेत्र नेहरू गांधी परिवार की विरासत भी है। कहा जाता है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर अपनी विरासत को विस्मृत कर देता है, तो उसे नए सिरे से अपनी ज़मीन तैयार करनी पड़ती है। और अगर विरासत के आधार पर अपने कदम बढ़ाता है तो उसकी आधी राह आसान हो जाती है। राहुल गांधी के सामने तमाम सवाल होने के बाद भी ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी आधी बाधा को पार कर लिया है। रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ इसलिए भी माना जाता है कि क्योंकि यहाँ से इंदिरा गांधी के पति फिरोज खान दो बार सांसद रहे, उसके बाद इंदिरा गांधी भी सांसद रहीं। अब पिछले पांच बार से सोनिया गांधी लोकसभा का चुनाव जीती हैं। मजेदार बात यह भी है कि वर्ष 1977 के आम चुनाव में जनता लहर में इंदिरा गांधी को भी पराजय का दंश भोगना पड़ा। उसके बाद एक बार भाजपा ने भी परचम लहराया है। इसलिए यह कहा जाना कि रायबरेली में कांग्रेस आसानी से विजय प्राप्त करेंगी, कठिन ही है। आज कांग्रेस की स्थिति देखकर यह भी कहने में गुरेज नहीं होना चाहिए कि आज की कांग्रेस के पास इंदिरा गांधी जैसा नेता नहीं है। जब इंदिरा गांधी चुनाव हार सकती हैं, तब आज तो कांग्रेस की स्थिति बहुत कमजोर है।

ऐसा तो तब हुआ, जब उत्तरप्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं था, इसलिए कांग्रेस उत्तरप्रदेश में अच्छी खासी जीत हासिल करती थी। लेकिन अब उत्तरप्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य बदला हुआ है। अब कांग्रेस के पास पहले जैसा वोट बैंक भी नहीं है, हालांकि इस चुनाव में सपा का समर्थन कांग्रेस के पास है, इसलिए चुनाव में सपा के कार्यकर्ता भी राहुल का प्रचार करेंगे, ऐसे में निश्चित ही कांग्रेस का वजूद बढेगा ही, यह तय है, लेकिन कितना बढ़ेगा, यह कहने में जल्दबाजी ही होगी।

वर्तमान में कांग्रेस के लिए यह पेचीदा सवाल ही था कि कांग्रेस की ओर से अमेठी और रायबरेली से किसको प्रत्याशी घोषित किया जाए, क्योंकि इन दोनों सीटों पर प्रथम तो गांधी परिवार का पुख्ता दावा बनता था। इसलिए दोनों क्षेत्रों में से किसी एक से प्रियंका वाड्रा को चुनाव मैदान में उतारने की क़वायद भी की जा रही थी, लेकिन प्रियंका को इस बार चुनाव लड़ने से दूर कर दिया। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी के रायबरेली से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद कांग्रेस अमेठी के चुनाव को गंभीरता से लेगी, क्योंकि अब कांग्रेस का पूरा जोर राहुल गांधी को जिताने में लगेगा। राहुल गांधी को जिताना कांग्रेस की मजबूरी है, क्योंकि अब राहुल गांधी ही नहीं, पूरी कांग्रेस की साख दांव पर लगी है। अगर कांग्रेस रायबरेली से चुनाव हारती है तो देश में कांग्रेस के बारे में गलत सन्देश जाएगा।

मिलावट का कहर...

स्वास्थ्य के लिए जहर

मिलावट करने वालों को न तो कानून का भय है और न आम आदमी की जान की परवाह है। दुखद एवं विडम्बनापूर्ण तो ये स्थितियां हैं जिनमें खाद्य वस्तुओं में मिलावट धडल्ले से हो रही है और सरकारी एजेन्सियां इसके लाइसेंस भी आंख मूंदकर बांट रही है।

भारतीय मसालों की गुणवत्ता की साख जब दुनिया में धुंधली हुई है, मिलावटी मसालों पर देश से दुनिया तक बहस छिड़ी हुई है, तब दिल्ली में मिलावट के एक बड़े मामले का पर्दापाश होना न केवल चिंताजनक है बल्कि दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर भारत के लिये शर्मनाक है। भारत में मिलावट का मामला मसालों तक ही सीमित नहीं है। मिलावटखोरों ने दवाइयों, तेल, घी, दूध, मिठाइयों से लेकर अनाज तक किसी चीज को नहीं छोड़ा है। हर साल त्योहारों पर देशभर से मिलावटी मावा और मिलावटी मिठाइयों की खबरे आती हैं। प्रश्न है कि आखिर मिलावट का बाजार इतना धडल्ले से क्यों पनप रहा है, क्यों सिस्टम लाचार है, मिलावटखोरी का अंत क्यों नहीं हो पा रहा है? लोकसभा चुनाव के दौरान मिलावट की त्रासद एवं जानलेवा घटनाओं का उजागर होना, क्यों नहीं चुनावी मुद्दा बनता?

कह तो सभी यही रहे हैं--"बाकी सब झूठ है, सच केवल रोटी है।" लेकिन इस बड़े सच रोटी यानी पेट भरने की खाद्य-सामग्री को मिलावट के कारण दूषित एवं जानलेवा कर दिया गया है। देश में खाद्य पदार्थों में मिलावट मुनाफाखोरी का सबसे आसान जरिया बन गई है। खाने-पीने की चीजें बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। किसी भी वस्तु की शुद्धता के विषय में हमारे संदेह एवं शंकाएं बहुत गहरा गयी हैं। मिलावट का धंधा शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक भी फैला हुआ है और इसकी जड़ें काफी मजबूत हो चुकी हैं। जीवन कितना विषम और विषभरा बन गया है कि सभी कुछ मिलावटी है। सब नकली, धोखा, गोलमाल ऊपर से सरकार एवं संबंधित विभाग कुंभकरणी निद्रा में है। मिलावटी खाद्य पदार्थ धीमे जहर की तरह हैं। ये दिल और दिमाग से जुड़ी बीमारियों, अल्सर, कैंसर वगैरह की वजह बन सकते हैं। खाने वालों को आभास भी नहीं होता कि वे धीरे-धीरे किसी गंभीर बीमारी की ओर जा रहे हैं। वे किसी पर भरोसा कर कुछ खरीदते हैं और मिलावटखोर तमाम कानून बने होने एवं प्रशासन की सक्रियता के बावजूद इस भरोसे को तोड़ रहे हैं। उनकी वजह से दूसरे देशों का भी भरोसा भारतीय उत्पादों पर कम होने की स्थितियां बनती जा रही है। कुछ दिनों पहले ही हांगकांग और सिंगापुर ने लिमिट से ज्यादा पेस्टिसाइड का आरोप लगाकर दो भारतीय ब्रैंड के कुछ मसालों को बैन किया था। अगर ऐसा हुआ तो इनके निर्यात से करोड़ों डॉलर की आमदनी पर आंच आएगी।

मिलावट करने वालों को न तो कानून का भय है और न आम आदमी की जान की परवाह है। दुखद एवं विडम्बनापूर्ण तो ये स्थितियां हैं जिनमें खाद्य वस्तुओं में मिलावट धडल्ले से हो रही है और सरकारी एजेन्सियां इसके लाइसेंस भी आंख मूंदकर बांट रही है। जिन सरकारी विभागों पर खाद्य पदार्थों की क्वॉलिटी बनाए रखने की जिम्मेदारी है वे किस तरह से लापरवाही बरत रही है, इसका परिणाम आये दिन होने वाले फूड प्वाइजनिंग की घटनाओं से देखने को मिल रहे हैं। मिलावट के बहुरुपिया रावणों ने खाद्य बाजार जकड़ रखा है। मिलावट का कारोबार अगर फल-फूल रहा है, तो जाहिर है कि इसके खिलाफ जंग उस पैमाने पर नहीं हो रही है, जैसी होनी चाहिए। इस मामले में भारत अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश से कुछ सबक ले सकता है, जिसने हल्दी में लेड की मिलावट पर काबू पा लिया। मिलावटखोर हल्दी की चमक बढ़ाने के लिए लेड का इस्तेमाल करते हैं और यह समस्या पूरे दक्षिण एशिया की है।

मिलावट सबसे बड़ा खतरा है। मारने वाला कितनों को मारेगा? एक आतंकवादी स्वचालित हथियार से या बम ब्लास्ट कर अधिक से अधिक सौ दो सौ को मार

देता है। लेकिन खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाला हिंसक एवं दरिंदा तो न जाने कितनों को मृत्यु की नींद सुलाता है, कितनों को अपंग और अपाहिज बनाता है। इन हिंसक, क्रूर एवं मुलाफाखोरों पर लगाम न लगने की एक वजह यह भी है कि ऐसा करने वालों को लगता है, इससे होने वाले मुनाफे की तुलना में मिलने वाली सजा बहुत कम है। जाहिर है, सजा कड़ी करने के साथ ही यह भी पक्का करना होगा कि दोषी किसी तरह से बच न निकलें। यही नहीं, लोगों को पता होना चाहिए कि मिलावट की शिकायत कहां करनी है। हमारे प्रयासों में कमी न रहे, तभी यह काला धंधा रुक सकेगा।

कारोबार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण मिलावट हर जगह देखने को मिलती है। कहीं दूध में पानी की मिलावट होती है, तो कहीं मसालों में रंगों की। दूध, चाय, चीनी, दाल, अनाज, हल्दी, फल, आटा, तेल, घी आदि ऐसी तमाम तरह की घरेलू उपयोग की वस्तुओं में मिलावट की जा रही है। यानी, पूरे पैसे खर्च करके भी हमें शुद्ध खाने का सामान नहीं मिल पाता है। मिलावट इतनी सफाई से होती है कि असली खाद्य पदार्थ और मिलावटी खाद्य पदार्थ में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। जीवन मूल्यहीन और दिशाहीन हो रहा है। हमारी सोच जड़ हो रही है। मिलावट, अनैतिकता और अविश्वास के चक्रव्यूह में जीवन मानो कैद हो गया है। घी के नाम पर चर्बी, मक्खन की जगह मार्गरीन, आटे में सेलखड़ी का पाउडर, हल्दी में पीली मिट्टी, काली मिर्च में पपीते के बीज, कटी हुई सुपारी में कटे हुए छुहारे की गुठलियां मिलाकर बेची जा रही हैं। दूध में मिलावट का कोई अंत नहीं। नकली मावा बिकना तो आम बात है। राजस्थान और गुजरात में चल रहा नकली जीरे का कारोबार अब दिल्ली एवं देश के अन्य हिस्सो तक पहुंच गया है। दिल्ली में पहली बार पकड़ी गई नकली जीरे की खेप ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत के लोगों को न शुद्ध हवा मिल रही है और न शुद्ध पानी और न ही शुद्ध खाने का निवाला, कैसी अराजक शासन व्यवस्था है? मिलावट के कारण हम एक बीमार समाज का निर्माण कर रहे हैं। शरीर से रुग्ण, जीर्ण-शीर्ण मनुष्य क्या सोच सकता है और क्या कर सकता है? क्या मिलावटखोर परोक्ष रूप से जनजीवन की सामूहिक हत्या का षड्यंत्र नहीं कर रहे? हत्यारों की तरह उन्हें भी अपराधी मानकर दंड देना अनिवार्य होना चाहिए। मिलावट एक ऐसा खलनायक है, हत्यारी प्रवृत्ति है, जिसकी अनदेखी जानलेवा साबित हो रही है। चाहे प्रचलित खाद्य सामग्रियों की निम्न गुणवत्ता या उनके जहरीले होने का मततब इंसानों की मौत भले ही हो, पर कुछ व्यापारियों एवं सरकारी अधिकारियों के लिए शायद यह अपनी थैली भर लेने का एक मौका भर है। त्यौहारों पर मिलावटी मिठाइयां खाने से अपच, उलटी, दस्त, सिरदर्द, कमजोरी और बेचैनी की शिकायते सुनने में आती रही है। इससे किडनी पर बुरा असर पड़ता है। पेट और खाने की नली में कैंसर की आशंका भी रहती है। खाद्य उत्पाद विनियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने 2006 के खाद्य सुरक्षा और मानक कानून में कड़े प्रावधान की सिफारिश की थी। कानून को सिंगापुर के सेल्स आफ फूड एक्ट कानून की तर्ज पर बनाया गया जो मिलावट को गम्भीर अपराध मानता है। फूड इंस्पैक्टरों का दायित्व है कि वह बाजार में समय-समय पर सैम्पल एकत्रित कर जांच करवाएं लेकिन जब सबकी 'मंथली इन्कम' तय हो तो फिर जांच कौन करे? हालत यह है कि बाजारों में धूल-धक्कड़ के बीच घोर अस्वास्थ्यकर माहौल में खाद्य सामग्रियां बेची जा रही है। सीएजी ऑडिट के दौरान जो तथ्य उजागर हुए हैं, वे भ्रष्टाचार को तो सामने लाते ही है साथ-ही-साथ प्रशासनिक लापरवाही को भी प्रस्तुत करते हैं। देश में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने का काम करने वाली सरकारी एजेन्सी की दशा कितनी दयनीय है और वहां कितनी लापरवाही बरती जा रही है, सहज अनुमान लगाया जा सकता है।

अरविन्द केजरीवाल को अंतरिम जमानत अपवाद नहीं : सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना किसी के लिए कोई अपवाद नहीं है और इस फैसले के 'आलोचनात्मक विश्लेषण' का स्वागत है।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत के संबंध में दिए गए कुछ बयानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केजरीवाल के वकीलों के दावों तथा जवाबी दावों पर विचार करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा, ''हमने किसी के लिए अपवाद स्वरूप कुछ नहीं किया है। हमने अपने आदेश में वही कहा, जो हमें न्यायोचित लगा।'' ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चुनावी रैलियों में दिए गए केजरीवाल के इन भाषणों पर विरोध जताया कि अगर जनता आम आदमी पार्टी को वोट देती है तो उन्हें दो जून को जेल वापस नहीं जाना पड़ेगा। पीठ ने मेहता से कहा, ''यह उनका मानना है। हम कुछ नहीं कह सकते।'' उसने कहा, ''हमारा आदेश इस बारे में बहुत स्पष्ट है कि उन्हें कब आत्मसमर्पण करना है। यह उच्चतम न्यायालय का आदेश है। विधि का शासन इस आदेश से संचालित होगा।'' मेहता ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने अपने दावों से जमानत की शर्त का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा, ''वह क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? यह संस्था पर तमाचे की तरह है।''

न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि अदालत का आदेश स्पष्ट है कि उन्हें दो जून को आत्मसमर्पण करना होगा। पीठ ने कहा, ''हमने आदेश में ऐसा कुछ नहीं कहा है कि वह मामले के बारे में नहीं बोल सकते।'' केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कार्यवाही के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिए बिना उनके एक साक्षात्कार का उल्लेख किया जिसमें शाह ने कहा था कि कई लोगों को लगता है कि अदालत ने केजरीवाल के साथ विशेष रुख अपनाया है। पीठ ने सिंघवी से कहा कि वह इस मुद्दे में नहीं जा रही। सिंघवी ने इस बात से इनकार किया कि केजरीवाल ने ऐसा कोई बयान दिया था कि लोग यदि उनकी पार्टी को वोट नहीं देते तो उन्हें जेल वापस जाना पड़ेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि इस संबंध में वह शपथपत्र दे सकते हैं। शीर्ष अदालत कथित आबकारी घोटाले से जुड़े एक धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई कर रही थी। न्यायालय ने 10 मई को इस मामले में केजरीवाल को एक जून तक अंतरिम जमानत दी थी। एक जून को लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के तहत मतदान होगा। न्यायालय ने उन्हें दो जून को आत्मसमर्पण करने को कहा है। केजरीवाल को इस मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था।

बढ़ रहा है तलाक का चलन

पारंपरिक भारतीय मूल्य लगा सकते हैं इस पर विराम

बढ़ते तलाक की समस्या का समाधान पारंपरिक भारतीय पारिवारिक मूल्यों में तलाशा जा सकता है। हमने परिवार के साथ समय बिताना कम कर दिया है। एक साथ भोजन करने और दिल से दिल की बातचीत करने का कोई विकल्प नहीं है, जहां परेशानियों व खुशियों का आदान-प्रदान होता है।

दंत चिकित्सक की कुर्सी बातचीत करने के लिए सबसे अच्छी जगह होती है, आपका मुंह खुला हुआ होता है और आपको जवाब देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप ऐसा कर ही नहीं सकते। सौभाग्य से मेरे पास एक बातूनी दंत चिकित्सक है। यह युवा महिला विवाह बाजार में तब से है, जबसे मैं उसे जानती हूं। वह लगभग 35 वर्ष की है और विवाह बाजार पर उसकी बातचीत आमतौर पर प्रफुल्लित करने वाली होती है। लेकिन पिछली कुछ मुलाकातों (हां, मैं अक्सर दंत चिकित्सक के पास जाती हूं) में वह तलाकशुदा लोगों की बढ़ती संख्या के बारे में बताती रही है।

डेढ़ दशक पहले एक योग्य और शिक्षित युवा महिला, जिसने कभी शादी नहीं की हो, कभी तलाकशुदा लोगों की ओर देखती तक नहीं थी। निश्चित रूप से ऐसे लोग थे, पर बहुत कम थे। तलाकशुदा पुरुषों एवं महिलाओं के लिए फिर से जीवनसाथी तलाशना मुश्किल था, महिलाओं के लिए तो यह और भी चुनौतीपूर्ण था। मगर अब विवाह बाजार बदल चुका है, सभी इच्छुक विवाह बाजार में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और अब तलाक को कलंक समझे जाने की प्रवृत्ति कम हो रही है।

शहरी इलाकों में तलाक अब सामान्य बात हो गई है, हालांकि लोग अब भी यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि यह अच्छी बात है या बुरी। उदारीकरण के बाद के युग में भारतीय समाज में नाटकीय बदलाव आए हैं, क्योंकि पारिवारिक इकाई में रिश्ते और लैंगिक भूमिकाएं भी विकसित हुई हैं। जिस भारतीय समाज में कभी तलाक के बारे में सुनने को नहीं मिलता था, वहां आंकड़े बताते हैं कि पिछले दो दशकों में तलाक के मामलों में 350 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। अपेक्षित रूप से बड़े शहरों में तलाक के मामलों में ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2014 से 2017 के बीच तलाक के मामलों में मुंबई में 40 फीसदी की और दिल्ली में 1990 से 2012 के बीच 36 फीसदी की वृद्धि हुई है। ये आंकड़े चिंताजनक हैं, क्योंकि देश में अब भी तलाक के मामले एक फीसदी के निचले स्तर पर हैं। हालांकि धीरे-धीरे इनमें वृद्धि हो रही है, जिससे भारतीय विवाह की स्थिरता की अवधारणा खतरे में है। वर्ष 2019 में दिल्ली में 60 फीसदी से अधिक तलाक की पहल महिलाओं ने की। इसके कई कारण हैं-उच्च साक्षरता दर, आर्थिक स्वतंत्रता और अपने अधिकारों के प्रति बढ़ती जागरूकता ने महिलाओं को अपने जीवन और निर्णयों की जिम्मेदारी खुद लेने के लिए प्रेरित किया है।

शोध के मुताबिक, दिलचस्प बात यह है कि पारंपरिक विवाहों की तुलना में अंतर्जातीय और अंतर्धार्मिक विवाहों में वैवाहिक विफलता की दर उच्च है। लेकिन इसकी सफलता एवं विफलता का अनुमान केवल आंकड़ों से नहीं लगा सकते। ऐसे कई कारक हैं, जो तलाक की बढ़ती प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करते हैं और महिला सशक्तीकरण के कदमों को तलाक दर के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि वह इस देश की महिलाओं एवं बेटियों से अन्याय के साथ-साथ एक गलत धारणा होगी।

आइए, देखते हैं कि वे कौन से कारण हैं, जो तलाक दर को प्रभावित करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि 53 फीसदी तलाक की पहल 24 से 35 वर्ष के लोगों द्वारा होती है। जाहिर है कि पीढ़ीगत नजरिये में बदलाव हो रहा है। जैसे-जैसे दुनिया ऑनलाइन एक-दूसरे से जुड़ रही है, मानवीय रिश्ते और अधिक नाजुक हो गए हैं। 'समझौता' एक बुरा शब्द बन गया है, जबकि एक समय यह वैवाहिक जोड़ों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला गुण था। अब समझौते को विफलता माना जाता है। इसके अलावा, हनीमून स्थलों के साथ इंस्टाग्राम के लिए तैयार और फिल्टर की गई छवियां, गंतव्य शादियां, दुल्हन के पहनावे एक तरह की वैवाहिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती हैं, जिससे वैवाहिक रिश्ते संबंधों के जुड़ाव की तुलना में उत्सव ज्यादा बन जाते हैं। ये सब चीजें युवा जोड़ों के समक्ष एक नई वास्तविकता प्रस्तुत करते हैं, जो स्थायी रिश्ते के लिए अस्थिर नींव प्रदान करता है।

पारिवारिक संरचना भी नाटकीय रूप से बदली है और नौकरी की जरूरतों के कारण घर से दूर जाने की मजबूरी ने परिवार में बुजुर्गों की भागीदारी लगभग समाप्त कर दी है। अब युवा अपने दम पर रिश्ते तय करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि 15 भारतीय जोड़ों में से एक बांझपन से जूझ रहा है। हालांकि प्रजनन संबंधी उपचार में नाटकीय प्रगति हुई है, मगर यह बहुत महंगा विकल्प है। ज्यादातर जोड़े वित्तीय स्थिरता सहित कई कारणों से माता-पिता बनने में देरी कर रहे हैं। बच्चे जोड़ों के लिए दांपत्य संभालने और रिश्तों में स्थिरता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण प्रेरणा होते हैं। पारिवारिक मूल्य और जुड़ाव अब भी भारतीय समाज को दूसरों से अलग करते हैं और तलाक के आंकड़े कम रखते हैं।

कृषि-खाद्य के लिए नीति बने

किसानों के खर्च और कर्ज में कमी बेहद जरूरी

राष्ट्रीय व स्थानीय स्तर पर कृषि व खाद्य नीति की बहुत चर्चा होती रही है। इसके बावजूद ऐसी समग्र नीति नहीं बन पाई है, जिसमें सभी जरूरतों का संतुलित समावेश हो सके। ऐसी समग्र नीति में आठ उद्देश्यों का संतुलित निर्वाह होना चाहिए, जो परस्पर एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।

पहला उद्देश्य तो यह है कि किसानों को, विशेषकर छोटे व मध्यम किसानों को संतोषजनक, टिकाऊ व रचनात्मक आजीविका उपलब्ध हो। संतोषजनक का मतलब उन्हें उपज की उचित कीमत मिले, जिससे जीवन-निर्वाह के अनुकूल आय प्राप्त हो। टिकाऊ का अर्थ आजीविका व इसका आधार भावी पीढ़ी के लिए भी टिका रहे। पानी-मिट्टी जैसी खेती की बुनियादी जरूरतें अच्छी स्थिति में बनी रहें। रचनात्मक का अर्थ खेती-किसानी के ज्ञान का किसान बेहतर उपयोग कर सकें, जिसमें परंपरागत ज्ञान व महिला किसानों की समझ की बड़ी भूमिका है। खर्च और कर्ज में कमी जरूरी है।

दूसरा उद्देश्य यह है कि उपभोक्ताओं को ऐसे खाद्य पदार्थ उचित कीमत पर मिलें, जो उन्हें स्वस्थ व नीरोग रखें। तीसरा उद्देश्य यह है कि कृषि व गांव का पर्यावरण अच्छा रहे। भू-जल स्तर ठीक बना रहे, मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरा शक्ति बनी रहे, जल-स्रोत उपलब्ध हों, किसान के मित्र, जो कीट-पतंगे, मधुमक्खियां, पक्षी आदि हैं, उनकी भी रक्षा हो तथा परागण की क्रिया ठीक से हो। सभी गांवों में भरपूर स्थानीय प्रजातियों के वृक्ष रहें। परंपरागत बीजों की रक्षा भी बहुत जरूरी है।

चौथा उद्देश्य यह है कि जलवायु बदलाव के मौजूदा दौर में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम रखा जाए और इस कारण उत्पन्न प्रतिकूल मौसमी स्थितियों व आपदाओं का सामना करने की क्षमता विकसित हो। बुरे मौसम व आपदा से किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए पहले से बेहतर तैयारी करनी होगी। यदि ग्रीनहाउस गैसों को नियंत्रित करने का कार्य ठीक से हो, तो इसके लिए विश्व स्तर पर स्थापित कोष से धनराशि प्राप्त की जा सकती है और किसानों को दी जा सकती है।

पांचवां उद्देश्य है कि भूमिहीन खेत मजदूरों को बेहतर मजदूरी और जहां संभव हो, कुछ भूमि देकर उनकी सहायता की जाए। इसी तरह प्रवासी मजदूरों की भलाई का भी पूरा ध्यान रखना होगा। विशेषकर डेयरी व पशुपालन, किचन गार्डन आदि के माध्यम से भी इनकी मदद हो सकती है। छठा उद्देश्य है कि खेती के उत्पादों पर आधारित लघु व कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि केवल खेती से गांव व गांव के लोगों की समृद्धि का मजबूत आधार नहीं बनता है। इससे स्थानीय स्तर पर अधिक रोजगार का सृजन भी होगा। इसमें महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। सातवां उद्देश्य यह है कि देश के विभिन्न भागों की अलग-अलग स्थितियों के अनुसार कृषि विकास की अलग-अलग जरूरतों के अनुकूल नियोजन होने चाहिए। यानी विकेंद्रित स्थानीय जरूरतों के अनुकूल कृषि नीति पर अधिक जोर देना चाहिए। आठवां और अंतिम उद्देश्य यह है कि खेती व ग्रामीण विकास के लिए सरकारों को अपना बजट बढ़ाना चाहिए। एक बार किसानों के कर्ज को माफ कर ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए कि सस्ती तकनीक अपना कर वे आगे कर्ज से बच सकें।

बेशक इन सब उद्देश्यों का एक साथ एक समग्र संतुलित नीति में समावेश चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इस राह पर चलते हुए हम बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। इन सभी उद्देश्यों में कोई आपसी टकराव नहीं है। इन सभी उद्देश्यों को हम एक साथ एक समय में समावेशी नीति से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमें यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब तक इन नीतियों के साथ कुछ समाज-सुधार के कार्य नहीं जुड़ेंगे, तब तक बेहतर से बेहतर आर्थिक नीतियां भी सफल नहीं होंगी। नशे के विरुद्ध, दहेज के विरुद्ध सशक्त आवाज उठानी होगी। तरह-तरह की उपभोक्तावाद आधारित फिजूलखर्ची को भी कम करना ही होगा। आज की दुनिया में शॉर्ट-कट बहुत पसंद किए जाते हैं। ऐसे में, आश्चर्य नहीं कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दों को छोड़कर प्रायः सतही तौर पर एक-दो उद्देश्यों या फार्मूलों पर चर्चा होती रही है। लेकिन सही व टिकाऊ समाधान तभी मिलेंगे, जब इनके लिए समग्र नीतियां बनेंगी, जब अल्पकालीन हितों के साथ दीर्घकालीन हितों पर भी ध्यान दिया जाएगा।

चीन से बढ़ता आयात भी एक चुनौती है, कारोबारी भागीदारी में पिछड़ा अमेरिका

विगत 12 मई को आर्थिक शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले वित्त वर्ष (2023-24) में चीन 118.41 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। उसने भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है।

पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में चीन से आयात 44.7 प्रतिशत बढ़कर 70.32 अरब डॉलर से 101.75 अरब डॉलर हो गया, जबकि चीन को भारत का निर्यात 16.66 अरब डॉलर रहा। प्रमुख रूप से लौह अयस्क, सूती धागा, कपड़े, हथकरघा, मसाले, फल और सब्जियां, प्लास्टिक और लिनोलियम जैसे क्षेत्रों में भारत का निर्यात बढ़ा है। चीन से आयात में वृद्धि के कारण भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 2023-24 में 85.09 अरब डॉलर हो गया। यदि जीटीआरआई रिपोर्ट का विश्लेषण करें, तो पाते हैं कि चीन से आयात में कमी नहीं आने के कई कारण हैं। भारत ने 2023-24 में चीन से 4.2 अरब डॉलर का टेलीकॉम व मोबाइल फोन आयात किया है, जो इस वर्ग में कुल आयात का 44 फीसदी है। इसी तरह, भारत ने कुल कंप्यूटर व प्रौद्योगिकी आयात का 77 प्रतिशत, नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े उपकरणों के आयात का 65.5 प्रतिशत, इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी के कुल आयात का 75 प्रतिशत हिस्सा चीन से मंगाया है। साफ है कि भारत आवश्यक व रणनीतिक तौर पर बेहद जरूरी सेक्टर में भी चीन से आयातित उत्पादों पर काफी निर्भर है।

हालांकि पिछले एक दशक से स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहित करके चीन से आयात घटाने के प्रयास हुए हैं। चीनी सामान के बहिष्कार व सरकार द्वारा विभिन्न चीनी एप पर प्रतिबंध, चीनी सामान के आयात पर नियंत्रण, कई चीनी सामान पर शुल्क वृद्धि, सरकारी विभागों में चीनी उत्पादों की जगह यथासंभव स्थानीय उत्पादों के उपयोग को प्रोत्साहन दिया है। पीएम मोदी द्वारा स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने व वोकल फॉर लोकल मुहिम के प्रसार ने स्थानीय उत्पादों की खरीद को पहले की तुलना में अधिक समर्थन दिया।

आत्मनिर्भर भारत अभियान में मैन्यूफैक्चरिंग के तहत 24 सेक्टर को प्राथमिकता के साथ तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। पिछले दो वर्ष में सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव (पीएलआई) स्कीम के तहत 14 उद्योगों को करीब दो लाख करोड़ रुपये आवंटित किए। अब देश के कुछ उत्पादक चीन के कच्चे माल का विकल्प बनाने में सफल भी हुए हैं।

चीन से व्यापार घाटा कम करने के लिए सरकार को और अधिक कारगर प्रयास करने होंगे, तो दूसरी ओर देश के उद्योग-कारोबार क्षेत्र को भी चीन से व्यापार असंतुलन दूर करने के लिए प्रतिस्पर्धा करने के प्रयास करने होंगे। भारतीय निर्यातकों के समक्ष आ रहे बाजार पहुंच के मुद्दों को सरकार को प्राथमिकता के आधार पर चीन से बात करनी होगी। देश से निर्यात बढ़ाने और आयात घटाने के लिए अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण की रफ्तार तेज करने के साथ युवा श्रमशक्ति को कौशलयुक्त करना होगा। नई लॉजिस्टिक नीति और गति शक्ति योजना के कारगर क्रियान्वयन से लॉजिस्टिक लागत घट सकती है।

अब फिर से देशवासियों को चीनी उत्पादों की जगह स्वदेशी उत्पादों के उपयोग का संकल्प लेना होगा। यह समझना होगा कि चीन से व्यापार असंतुलन की गंभीर चुनौती के लिए सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि देश का उद्योग-कारोबार और कंपनियां भी जिम्मेदार हैं। उन्होंने कलपुर्जे सहित संसाधनों के विभिन्न स्रोत और मध्यस्थ विकसित करने में प्रभावी भूमिका नहीं निभाई है। साथ ही बड़ी कंपनियां शोध एवं नवाचार में भी बहुत पीछे हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि जीटीआरआई रिपोर्ट के मद्देनजर भारत व्यापार घाटा कम करने के लिए रणनीतिक रूप से तेजी से आगे बढ़ेगा। यह भी उम्मीद है कि जिस तरह भारत ने भारतीय खिलौना उद्योग को पल्लवित-पुष्पित करके चीनी खिलौनों के आयात में भारी कमी की, उसी तरह उद्योग-कारोबार के अन्य क्षेत्रों में भी चीन से आयात घटाने व निर्यात बढ़ाने के नए उपाय किए जाएंगे। साथ ही देश के बाजार में चीनी उत्पादों के वर्चस्व को तोड़ने के लिए प्रमुख उद्योग और कारोबार स्थानीय विकल्प प्रस्तुत करने की डगर पर तेजी से आगे बढ़ेंगे।

इस वजह से देश में आया भीषण आंधी-तूफान, और चलेंगी धूल भरी आंधिया

मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा का कहना कि देश के अधिकतर समुद्री इलाकों वाले क्षेत्रों में इस तरीके के आंधी-तूफान अगले कुछ दिनों तक आएंगे। वजह बताते हुए महापात्रा कहते हैं कि लगातार बढ़ रही उमस और तापमान के चलते यह परिस्थितियां बन रही हैं।

बीते कुछ दिनों से देश के अलग-अलग हिस्सों में चल रहा आंधी-तूफान फिलहाल अगले चार दिनों तक थमने का नाम नहीं लेगा। यह तूफान न सिर्फ तीव्र गति से देश के अलग-अलग हिस्सों को प्रभावित करेगा, बल्कि बदली हुई परिस्थितियों में कई इलाकों के तापमान को भी बढ़ाएगा। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय पात्रा ने अमर उजाला डॉट कॉम को बताया कि उमस और लगातार बढ़ता हुआ तापमान देश में आंधी-तूफान के हालात बना रहा है। फिलहाल जो मौसम की परिस्थितियों बन रही हैं, उसमें आंधी-तूफान के बने रहने का अनुमान लगाया गया है। मुंबई में ऐसी ही परिस्थितियों में आए भीषण तूफान ने 14 लोगों की जान ले ली। जबकि दर्जनों लोग अभी भी घायल होकर अस्पताल में दाखिल हैं।

मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा कहते हैं कि उन्होंने देश के अलग-अलग हिस्सों के लिए आज भी अलर्ट जारी किया है। उनका कहना कि देश के अधिकतर समुद्री इलाकों वाले क्षेत्रों में इस तरीके के आंधी-तूफान अगले कुछ दिनों तक आएंगे। वजह बताते हुए महापात्रा कहते हैं कि लगातार बढ़ रही उमस और तापमान के चलते यह परिस्थितियां बन रही हैं। मौसम विभाग के महानिदेशक कहते हैं कि मुंबई में जिस तरीके से तेज गति का तूफान आया, इस तरह से अभी भी कुछ इलाकों में तूफान आने की संभावनाएं बन रही हैं। मौसम विभाग ने ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए संबंधित राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया है।

मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में अभी कई राज्यों में लगातार पारा बढ़ता रहेगा, जिसके चलते इस तरह के चक्रवर्ती तूफान की संभावनाएं बन रही हैं।

इसके अलावा मध्यप्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ समेत कई इलाकों में अभी भी 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान लगाया जा रहा है। विभाग के अनुमान के मुताबिक मंगलवार और बुधवार को मध्यप्रदेश में तेज आंधी और तूफान आ सकता है।

इसके चलते मध्यप्रदेश में जिम्मेदार महकमों को अलर्ट पर रखा गया है। मध्यप्रदेश के अलावा बिहार और उड़ीसा में भी आंधी तूफान की संभावनाएं बनी हुई हैं। आंधी तूफान तेज गति के साथ आने वाला है। इसलिए किसी भी तरीके के जान माल के नुकसान से बचाव के लिए संबंधित राज्यों को पहले से ही एडवाइजरी जारी कर अलर्ट कर दिया गया है।

मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा कहते हैं कि इन इलाकों में आंधी तूफान के साथ साथ बारिश का भी अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि बारिश सिर्फ इन इलाकों में ही नहीं, बल्कि उत्तर भारत से लेकर बंगाल के कई हिस्सों में भी होगी। इसके अलावा नॉर्थ-ईस्ट के हिमालय रेंज के साथ-साथ अंडमान में भी बारिश और आंधी-तूफान का अनुमान लगाया जा रहा है।

मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक उत्तर भारत के भी कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान बना हुआ है। इसमें जम्मू-कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश समेत उत्तराखंड के कुछ हिस्से शामिल हैं।

मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में राजस्थान सबसे ज्यादा गर्म राज्य होने वाला है। इसके चलते राजस्थान और गुजरात में भी धूल भरी आंधियां चल सकती हैं। जबकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के हिस्सों में भी लगातार तापमान बढ़ता रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार से लेकर शनिवार तक उत्तर भारत के कई हिस्सों में गर्म हवाएं चलेंगी। इन गर्म हवाओं का असर मध्यप्रदेश से बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों तक रहेगा। यही गर्म हवाएं और उमस बड़े थंडरस्टॉर्म को बढ़ाएंगी।

क्या हो अगर NOTA को मिल जाए सर्वाधिक वोट, क्या वापस होंगे चुनाव?

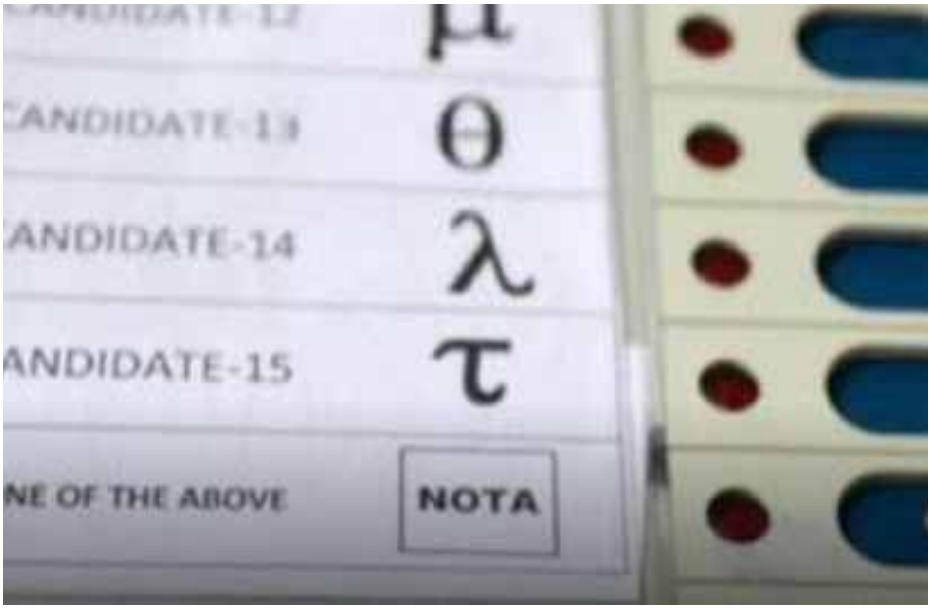

आयुर्वेद एवं योग चिकित्सक डा. नितिन बलवंत शुक्ल का कहना है कि विकल्पों पर विचार करना चाहिए नोटा पर अधिक मतदान होने से द्वितीय स्थान पर आने वाला प्रत्याशी विजयी माना जाएगा...

इंदौर लोकसभा चुनाव में पिछले दिनों हुए अप्रत्याशित घटनाक्रम के बाद कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने नामांकन वापस ले लिया था, इतना ही नहीं वे भाजपा में भी शामिल हो गए। इसके बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव के मैदान से पूरी तरह बाहर हो गई और अब इंदौर की जनता से नोटा को अपना मत देने की अपील कर रही है। लिहाजा कांग्रेस नोटा के पक्ष में जोर-शोर से जुटी है। लेकिन यहां सवाल यह है कि क्या वाकई नोटा को मत देने पर इसका चुनाव पर असर पड़ेगा? तो फिलहाल इसका जवाब फिलहाल ना ही नजर आता है।

क्या है नोटा का प्रावधान

साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक ऐतिहासिक फैसले ने मतदाताओं को नोटा का विकल्प उपलब्ध करवाया। जिसके अनुसार यदि कोई मतदाता किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहता तो वह नोटा को अपना मत दे सकता है। यदि किसी क्षेत्र में सभी उम्मीदवारों के मुकाबले नोटा को अधिक वोट मिल जाते हैं तो नियम 64 के अनुसार जिस उम्मीदवार को सर्वाधिक वोट मिले हैं, उसे चुनाव आयोग विजयी घोषित करता है। इसके अलावा यदि 99 प्रतिशत मत भी नोटा को मिलते हैं तो भी इसका चुनाव पर कोई असर नहीं होगा। इस परिस्थिति में किसी उम्मीदवार को एक प्रतिशत भी वोट मिले हैं, तो भी वही निर्वाचित होगा।

क्या कहते हैं जानकार?

उद्योगपति व शिक्षाविद वीरेंद्र गोयल का कहना है कि वर्तमान में नोटा का कोई असर नहीं नोटा एक विकल्प तब बनेगा, जब ऐसा कानून आए कि नोटा को सर्वाधिक मतदान मिलने पर अन्य उम्मीदवार अयोग्य घोषित किए जाएं। चुनाव प्रक्रिया दोबारा हो। साथ ही चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवार दोबारा चुनाव न लड़ सकें तभी नोटा का उद्देश्य सिद्ध होगा। हालांकि नोटा का एक उद्देश्य रहता है, उसकी चर्चा भी होती है। नोटा बेकार तो नहीं है, लेकिन उसका असर नहीं है। अगर नोटा के जीतने पर चुनाव निरस्त कर दिए जाएं, तो उसका उद्देश्य सफल होगा।

आयुर्वेद एवं योग चिकित्सक डा. नितिन बलवंत शुक्ल का कहना है कि विकल्पों पर विचार करना चाहिए नोटा पर अधिक मतदान होने से द्वितीय स्थान पर आने वाला प्रत्याशी विजयी माना जाएगा। नोटा का विकल्प चुनकर लोग यह दर्शाते हैं कि हमें उम्मीदवारों के प्रति नाराजगी है और वह हमारे मापदंडों पर खरे नहीं उतर रहे। इसी प्रकार सामान्य अर्थों में तो नोटा का वोट व्यर्थ ही जाता है। लेकिन इंदौर के संदर्भ में माना जाएगा कि जनता को विकल्प नहीं मिला। उम्मीदवारों में अगर कोई कांग्रेस का होता तो लोग उन्हें भी मत देते। हालांकि किसी उम्मीदवार को मत देना अधिक उचित रहता है।

पाकिस्तान की गोलियों का जवाब तोप से देंगे

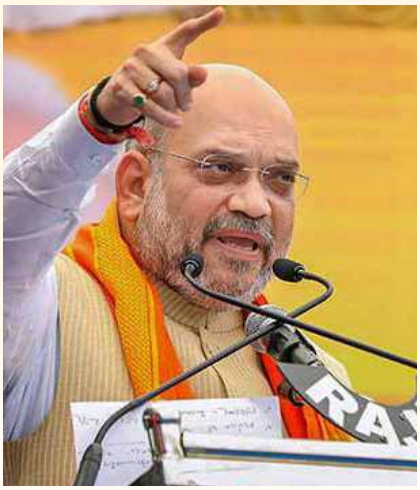

तेलंगाना में रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को घेरा। भाजपा नेता ने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर रेवंत रेड्डी की टिप्पणी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक की और आतंकवादियों को खत्म किया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को तेलंगाना में हुंकार भरी। यहां एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, इसके डर से कांग्रेस पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) पर भारत का अधिकार छोड़ना चाहती है।

अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा : रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, 'कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, इसलिए भारत को पीओके के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। परमाणु बम के डर से वे पीओके पर भारत का अधिकार छोड़ना चाहते हैं। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी फिर एक बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और इस बार पाकिस्तान की गोलियों का जवाब तोप से दिया जाएगा।'

तेलंगाना के सीएम पर साधा निशाना

अमित शाह ने इस दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को भी घेरा। भाजपा नेता ने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर रेवंत रेड्डी की टिप्पणी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक की और आतंकवादियों को खत्म किया।' बता दें कि रेवंत रेड्डी ने पुलवामा हमले को रोकने में खुफिया विफलता का दावा किया था। उन्होंने आगे कहा, 'पुलवामा घटना के बाद सर्जिकल स्ट्राइक से पीएम मोदी ने राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की। मोदी जी से मेरा एक सवाल है, वह क्या कर रहे हैं? पुलवामा घटना क्यों हुआ? आपने इसे क्यों होने दिया? आंतरिक सुरक्षा को लेकर आप क्या कर रहे हैं? आपने आईबी या आरएंडएडब्ल्यू जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया?'

विदेशी विचारों वालों की जगह इटली

पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा में मीडिया से चर्चा में कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कि कांग्रेस का भारत की माटी से, भारत की जनता से कोई लेना-देना नहीं है। ये तो विदेशी विचारों से प्रभावित होकर काम करते हैं। इनकी सही जगह भारत नहीं, इटली है। कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी बौखलाए हुए हैं। कांग्रेस का भारतीय संस्कृति से, जीवन मूल्यों से परंपराओं से कोई लेना-देना नहीं है। ये भारत की जड़ों से कटे हुए हैं। इनके नेता सलाहकार कहते हैं- कोई चीन जैसा लगता है कोई नेपाल, कोई कहीं जैसा लगता है। अरे, हम सब भारत माता के लाल, भेदभाव का कहां सवाल, हम सब एक ही हैं, अलग भाषा अलग वेष फिर भी अपना एक देश। गुरुवार को भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनसभाओं को संबोधित करने खंडवा पहुंचे थे। उन्होंने प्रत्याशी पाटिल के समर्थन में मूंदी, सिंगोट और खकनार में जनसभा को संबोधित किया। खकनार में चौहान ने कहा कि हम केवल वोट के लिए काम नहीं करते, बल्कि जनता की जिंदगी बदलने के लिए काम करते हैं। चाहे केंद्र सरकार हो या मप्र की भाजपा सरकार हो। भाजपा देश की तीन करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएगी।

जीरो प्रतिशत ब्याज पर किसानों को लोन दिया

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के जमाने में 18 प्रतिशत ब्याज पर लोन मिलता था। कई जगह जाता था तो पता चलता था कर्ज नहीं चुकाने पर किसी का ट्रैक्टर खींच ले गए, किसी की मोटर तो किसी की मोटरसाइकिल ले गए। किसान कहते थे एक लाख लिया था तो दो लाख ले लिए। तब हमने निर्णय लिया कि जीरो प्रतिशत ब्याज पर कर्जा दिया जाएगा। मूंदी में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि दिलों का रिश्ता पदों से नहीं होता है। मेरा लक्ष्य जनता की सेवा है। इसके मद्देनजर खेती को फायदे का धंधा बनाया। सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता दी और जनहित के कार्यों को आगे बढ़ाया। नर्मदा का पानी मालवा-निमाड़ में पहुंचाया। बेटियों के लिए कन्यादान योजना और लाड़ली बहनों की योजना को हमने लागू किया।

संविधान की प्रस्तावना नहीं बदलेगी सरकार आरक्षण रहेगा बरकरार : सिंह

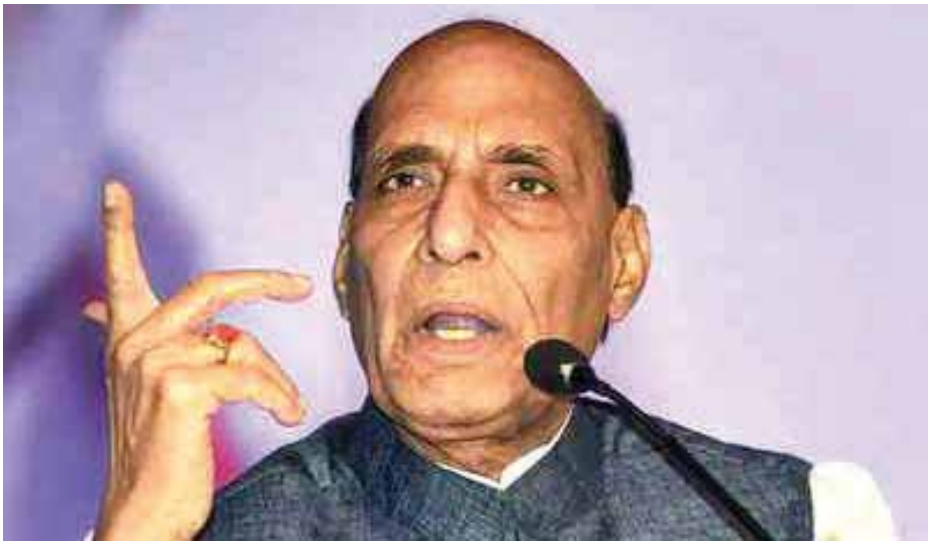

कांग्रेस के कुछ अन्य पदाधिकारियों ने आशंका जताई है कि भाजपा संविधान की प्रस्तावना से ''धर्मनिरपेक्ष'' शब्द हटा सकती है। रक्षा मंत्री ने कहा, ''कांग्रेस ने संविधान में 80 बार संशोधन किए

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार कभी भी संविधान नहीं बदलेगी और न ही आरक्षण खत्म करेगी। उन्होंने कांग्रेस पर "भय" पैदा करने और वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। सिंह ने एक साक्षात्कार के दौरान कांग्रेस पर यह अफवाह फैलाने का आरोप लगाया कि भाजपा सत्ता में रही तो संविधान बदल देगी। उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि संविधान की प्रस्तावना को बदलने का कोई सवाल ही नहीं है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि भाजपा अगर सत्ता में रही तो वह संविधान को "फाड़कर फेंक देगी।" कांग्रेस के कुछ अन्य पदाधिकारियों ने आशंका जताई है कि भाजपा संविधान की प्रस्तावना से "धर्मनिरपेक्ष" शब्द हटा सकती है। रक्षा मंत्री ने कहा, "कांग्रेस ने संविधान में 80 बार संशोधन किए। उन्होंने आपातकाल के दौरान प्रस्तावना में बदलाव किया।" सिंह ने कहा, "भाजपा संविधान नहीं बदलेगी। संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा था कि प्रस्तावना में कोई बदलाव होगा। आपने (कांग्रेस) संविधान के मूल विचार को चोट पहुंचाने का काम किया।"

उन्होंने कहा, संविधान की प्रस्तावना को बदलने का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने इसे बदल दिया और अब वे हम पर निराधार आरोप लगा रहे हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान के सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है। साल 1976 में 42वें संशोधन के तहत भारत के परिचय को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया था। सिंह ने कहा, ''वे (कांग्रेस) नागरिकों में डर पैदा करके लोगों का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।'' उन्होंने कहा, ''मैं सुझाव देना चाहता हूं कि उन्हें विश्वास पैदा करके लोगों का समर्थन हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, न कि डर पैदा करके। चुनावी अभियान तथ्यों पर आधारित होना चाहिए।

शुक्रवार को राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) भारत के लोकतंत्र पर लगातार हमला कर रहे हैं तथा देश के संविधान को नष्ट करना चाहते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा, कांग्रेस भय का माहौल पैदा कर रही है और वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैला रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरक्षण के मुद्दे पर भी कांग्रेस देश को गुमराह कर रही है। सिंह ने कहा, ''कांग्रेस लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। आरक्षण खत्म नहीं होगा। वे हम पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस ने भाजपा नेताओं से इस बारे में पार्टी का रुख स्पष्ट करने को कहा है कि क्या वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा हटा देगी। कांग्रेस के स्पष्टीकरण मांगे जाने पर सिंह ने कहा, हम आरक्षण के साथ बिलकुल भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। देश भर में बड़े पैमाने पर प्रचार कर रहे सिंह ने कहा कि भाजपा जाति, पंथ और धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करती है क्योंकि उसका ध्यान देश को मजबूत करने पर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस समाज में सद्भाव को बढ़ावा नहीं देती क्योंकि उसका दृष्टिकोण वोट बैंक की राजनीति पर केंद्रित रहा है।

नेपाल ने गुणवत्ता संबंधी चिंताओं के कारण मसाला उत्पादों पर प्रतिबंध

नेपाल के खाद्य प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता नियंत्रण विभाग के अनुसार, एमडीएच और एवरेस्ट के चार मसाला उत्पादों को संदिग्ध एथिलीन ऑक्साइड या ईटीओ विकार के कारण शुक्रवार से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके तहत एमडीएच के मद्रास करी पाउडर, सांभर मसाला पाउडर और मिश्रित मसाला करी पाउडर तथा एवरेस्ट के फिश करी मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सिंगापुर और हांगकांग के बाद, नेपाल ने भी कथित गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को लेकर भारतीय कंपनियों के कुछ मसाला उत्पादों के आयात और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेपाल के खाद्य प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता नियंत्रण विभाग के अनुसार, एमडीएच और एवरेस्ट के चार मसाला उत्पादों को संदिग्ध एथिलीन ऑक्साइड या ईटीओ विकार के कारण शुक्रवार से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके तहत एमडीएच के मद्रास करी पाउडर, सांभर मसाला पाउडर और मिश्रित मसाला करी पाउडर तथा एवरेस्ट के फिश करी मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। विभाग ने शुक्रवार को जारी एक नोटिस में कहा, चूंकि इन चार उत्पादों में एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई है, इसलिए खाद्य विनियमन 2027 बीएस के अनुच्छेद 19 के अनुसार देश के भीतर इन उत्पादों के आयात और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नोटिस में कहा गया, हमारा ध्यान उन मीडिया रिपोर्ट पर गया, जिनमें बाजार में इन घटिया उत्पादों की बिक्री और इनके उपभोग के लिए हानिकारक

होने के बारे में बताया गया था।

खाद्य गुणवत्ता नियंत्रण निगरानी संस्था ने आयातकों और व्यापारियों से इन उत्पादों को बाजार से वापस लेने का भी आग्रह किया है। पिछले महीने, सिंगापुर और हांगकांग ने कैंसर से जुड़े कुछ ईटीओ के संदिग्ध ऊंचे स्तर का हवाला देते हुए एमडीएच और एवरेस्ट के कुछ मसालों की बिक्री रोक दी थी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने तब से देश में विभिन्न ब्रांडों के मिसे मसालों की गुणवत्ता जांच करने के लिए कदम उठाए हैं।

मोटा अनाज आपकी जिंदगी के लिए हैं सुपर फूड, कृषि विभाग भी दे रहा है अनुदान...

लोग अब अपनी हेल्थ को देखते हुए पौराणिक खानपान की तरफ रुख करने लगे हैं। ऐसे में अब बाजार में मोटे अनाज की डिमांड धीरे-धीरे बढ़ने लगी। इसका उत्पादन काफी कम है, जिसकी वजह से बाजार में काफी महंगे मिलते हैं। लेकिन लोगों को आसानी से मोटे अनाज मिल पाए इसके लिए कृषि विभाग ने इसकी खेती कराने के लिए सोचा। इससे जिले में मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ेगा और किसानों को फायदे के साथ-साथ लोगों को आसानी से मोटा अनाज उपलब्ध हो जाएगा। कृषि विभाग के द्वारा जिले में आठ तरह के कृषि को शुरू कराया जाएगा। इसके लिए किसानों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इसको लेकर कृषि अधिकारी अनिल कुमार यादव ने बताया कि यहां पर किसानों को ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कंगनी, अंदुआ, कुकटी और सांवा का बीज दिया जाएगा। इसको लेकर किसान सलाहकार के माध्यम से कृषि विभाग किसानों को जागरूक भी कर रहा है।

मोटे अनाज से हड्डियां मजबूत होती है : वहीं, डाइटीशियन अनिता कुमारी बताती है कि इसके खाने से हड्डी मजबूत होती है। मोटे अनाज में कैल्शियम की कमी दूर होती है। पाचन क्रिया काफी मजबूत होता है। खास कर डायबिटीज मरीजों के लिए यह काफी लाभकारी

होता है।

एक किसान को दो एकड़ के लिए मिलेंगे पैसे : उन्होंने बताया कि एक किसान को दो एकड़ के लिए पैसे दिए जाएंगे। प्रति एकड़ चार हजार रुपये दिए जाएंगे। इसमें दो हजार बीज के लिए व दो हजार खेती के लिए मिलेंगे। मोटे अनाज की खेती क्लस्टर में कराई जाएगी। ताकि उसकी देखभाल अच्छे से हो सके। उन्होंने बताया कि इसकी खेती सड़क किनारे कराई जाएगी। ताकि अन्य किसान देखकर प्रेरित हो और किसान इसकी खेती की तरफ रुख करें।

मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की रिपोर्ट में हुआ खुलासा, एक एकड़ में दो की जगह पांच बोरी तक यूरिया डाल रहे किसान...

यूरिया खाद का अत्यधिक इस्तेमाल करना फसल के लिए खतरनाक

छिंदवाड़ा. खेती में यूरिया के अत्यधिक इस्तेमाल से साल दर साल मिट्टी की सेहत बिगड़ रही है। जमीन में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और जिंक की कमी वर्तमान में फसल उत्पादन प्रभावित होने के साथ मानव स्वास्थ्य पर विपरीत असर पडऩे की चेतावनी भी दे रही है। किसानों का असंतुलित खाद डालने का लोभ सब पर भारी है। ये तथ्य मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की एक रिपोर्ट में हुआ है।

इस पर कृषि वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने चिंता जाहिर करते हुए किसानों को संयमित व्यवहार करने की सलाह दी है। खरीफ सीजन अगले माह 15 जून को मानसूनी बारिश के साथ शुरू हो जाएगा। जिसमें छिंदवाड़ा और पांढुर्ना जिले के 2.98 लाख किसान 5 लाख हैक्टेयर के रकबे में फसल लगाएंगे। इस खेती के लिए 86 हजार मीट्रिक टन खाद आ चुका है। किसानों सोसाइटी से इसका उठाव भी शुरू कर दिया है। ऐसे में किसानों को संयमित रूप से एक एकड़ में 2 से 3 बोरी यूरिया डालने की सलाह दी जा रही है। वजह साफ है कि मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की रिपोर्ट में यूरिया का अत्यधिक इस्तेमाल खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है।

असंतुलन से उत्पादन, लागत, मानव स्वास्थ्य प्रभावित- कृषि विभाग की मैदानी रिपोर्ट में ये तथ्य आया हैं कि जहां किसानों को मक्का समेत अन्य फसलों में एक एकड़ में दो बोरी यूरिया की जरूरत है, वे ज्यादा उत्पादन के लोभ में बेहिसाब 5-6 बोरी तक इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पौधे की ग्रोथ समय से ज्यादा होने पर फसल लेट रही है। फसल की लागत भी दुगनी हो रही है। ये उपज जब मानव आहार बनती है तो उनके स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ता है।

खरीफ में मक्का, कपास व धान प्रमुख फसल

खरीफ सीजन में पांच लाख हैक्टेयर का रकबा है। इनमें मक्का 3.60 लाख, कपास 56 हजार, धान 32 हजार, अरहर 18 हजार, सोयाबीन 13 हजार, कोदो कुटकी 10 हजार और रामतिल का रकबा 3 हजार हैक्टेयर है। इसके अलावा दूसरी फसल भी होती है।

प्रयोगशाला रिपोर्ट में जिंक की सर्वाधिक कमी

मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की 31 मार्च की स्थिति में जारी रिपोर्ट के अनुसार छिंदवाड़ा और पांढुर्ना जिलों के किसानों से उनके खेतों की मिट्टी के 12300 नमूने लिए गए। इनमें सबसे ज्यादा जिंक तत्व की कमी पाई गई है। शेष तत्व आयरन, मैगनीज, कापर, सल्फर और बोरान की स्थिति संतोषजनक है। कृषि अधिकारियों के मुताबिक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की कमी भी बनी हुई है। जिसे किसान अनदेखा कर रहे हैं।

ये कर लें किसान तो दूर हो जाए संकट- रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि खेती में यूरिया के इस्तेमाल से केवल नाइट्रोजन और डीएपी से नाइट्रोजन, फास्फोरस की पूर्ति होती है। पोटाश, जिंक की कमी बनी रहती है। वैज्ञानिकों के अनुसार यदि किसान एनपीके और जिंक का संतुलित इस्तेमाल कर लें तो मिट्टी की सेहत सुधर सकती है। फिलहाल कृषि विभाग ने अपने मैदानी कर्मचारियों को किसानों को समझाइश देने में लगाया है।

इनका कहना है...

▸ खरीफ सीजन की मक्का समेत अन्य फसलों में यूरिया के अत्यधिक इस्तेमाल से हो रहे मिट्टी में हो रहे नुकसान से किसानों को अवगत कराया जा रहा हैं। मिट्टी परीक्षण की रिपोर्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और जिंक की कमी सामने आई है। इससे जिले का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। फिलहाल किसानों को खाद में एनपीके व जिंक का संतुलित इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है।

-जितेन्द्र कुमार सिंह, उपसंचालक कृषि

बड़ा चुनावी मुद्दा महिला उत्पीड़न, कई दलों पर लगा यह दाग...

चुनाव में भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जनता दल सेक्युलर और तृणमूल कांग्रेस सहित कई राजनीतिक दलों के नेताओं पर महिला उत्पीड़न करने के आरोप लगे। रेवन्ना कांड और संदेशखाली कांड ने लोगों के दिलों को झकझोर कर रख दिया।

इस चुनावी महाभारत को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने महिलाओं पर बड़ा दांव लगाया है। हर दल ने सत्ता पाने पर महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं शुरू करने का दावा किया है। लेकिन अब तक का अनुभव बताता है कि यह चुनाव बेटियों की इज्जत पर भारी पड़ा है। इसी चुनाव में भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जनता दल सेक्युलर और तृणमूल कांग्रेस सहित कई राजनीतिक दलों के नेताओं पर महिला उत्पीड़न करने के आरोप लगे। रेवन्ना कांड और संदेशखाली कांड ने लोगों के दिलों को झकझोर कर रख दिया। लेकिन लगभग सभी राजनीतिक दलों ने अपने नेताओं पर लगे आरोपों को दूसरे दलों की साजिश करार दिया, तो दूसरे दलों को महिलाओं के सम्मान-सुरक्षा की उपेक्षा करने वाला बताया।

भाजपा पर आरोप

इस चुनाव में सबसे चर्चित मामला प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल का रहा। जनता दल (सेक्युलर) के हासन लोकसभा सीट से प्रत्याशी प्रज्वल रेवन्ना के सेक्स टेप ने कर्नाटक की राजनीति में भूचाल ला दिया। भाजपा के साथ गठबंधन होने के कारण वह भी इस मामले में विपक्ष के निशाने पर आ गई। कांग्रेस ने भाजपा पर सेक्स स्कैंडल के आरोपी का साथ देने का आरोप लगाया। लेकिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने तुरंत अपनी पार्टी के महिला शक्ति के साथ खड़े होने की बात कही। भाजपा ने रेवन्ना का मामला अब तक दबाए रखने और हजारों महिलाओं के अपराधी रेवन्ना को विदेश भाग जाने के लिए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर भी हमला बोला। रेवन्ना कांड का कर्नाटक में चुनाव पर क्या असर हुआ, यह देखने वाली बात होगी।

कांग्रेस भी घिरी

कांग्रेस ने मणिपुर में महिलाओं के साथ हिंसा होने और बृजभूषण शरण सिंह के द्वारा महिला खिलाड़ियों का उत्पीड़न करने के मामले में भी भाजपा को घेरा है। भाजपा को इसके कारण भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन कांग्रेस भी महिला उत्पीड़न के मामले में बराबर घिरी हुई है। कांग्रेस की पूर्व नेता राधिका खेड़ा ने अपनी ही पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेताओं पर पार्टी के ही रायपुर कार्यालय में उनका उत्पीड़न करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने यहां तक कहा कि उन्होंने अपने साथ हुए उत्पीड़न की जानकारी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और जयराम रमेश सहित कई बड़े नेताओं को इसकी जानकारी दी, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी और उन्हें न्याय नहीं दिलाया। अंत में राधिका खेड़ा ने भाजपा ज्वाइन कर लिया।

ममता पर भारी संदेशखाली

ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अभी भी सबसे मजबूत खिलाड़ी बनी हुई हैं, लेकिन उनकी पार्टी के नेता शाहजहां शेख के ऊपर संदेशखाली की अनेक महिलाओं से जबरदस्ती शारीरिक संबंध स्थापित करने के गंभीर आरोप लगे हैं। भाजपा ने इस मामले को बेहद मजबूती के साथ उठाया और ममता बनर्जी के राज में उन्हीं की पार्टी के नेताओं के द्वारा

महिलाओं का उत्पीड़न होने का आरोप लगाया। वहीं, तृणमूल कांग्रेस ने इसे भाजपा की साजिश करार दिया है। लेकिन माना जा रहा है कि ममता बनर्जी को संदेशखाली कांड के कारण बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है।

स्वाति मालीवाल विवाद में घिरे केजरीवाल

आम आदमी पार्टी भी महिला उत्पीड़न के गंभीर आरोपों से घिर गई है। पार्टी की ही राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से कथित तौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास में मुख्यमंत्री के पीए बिभव कुमार के द्वारा मारपीट की गई है। स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के इशारे पर उनसे हिंसा किए जाने का आरोप लगाया है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसे भाजपा की साजिश करार दिया है। वहीं, भाजपा ने कहा है कि यह आम आदमी पार्टी का आंतरिक मामला है। भाजपा का कहना है कि जो केजरीवाल अपनी ही पार्टी की महिला सांसद को न्याय नहीं दे सकते, वे दिल्ली की महिलाओं के साथ क्या न्याय करेंगे।

क्यों हो रहा उत्पीड़न?

राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष ममता शर्मा ने अमर उजाला से कहा कि सच्चाई यह है कि महिला सशक्तीकरण के मामले में कागजी कार्रवाई ज्यादा हो रही है, जबकि असलियत में कोई काम नहीं हो रहा है। पुरुष आज भी महिलाओं को अपने बराबर मानने को तैयार नहीं हो रहे। राजनीतिक दलों के अंदर भी महिला उत्पीड़न की सेल नहीं बन रही। जहां महिला उत्पीड़न सेल बने हैं, वे प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रहे। इसका बड़ा असर यह है कि आज भी हर मंच पर महिलाओं का शोषण हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सभी दलों को एक साथ आकर इस समस्या का हल निकालना चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए कि हर घर में बेटी है और यदि सही सिस्टम नहीं बनेगा तो हर बेटी महिला उत्पीड़न के दायरे में रहेगी।

महिला उत्पीड़न पर साथ आएं सभी दल...

सामाजिक महिला अधिकार कार्यकर्ता अंबर जैदी ने अमर उजाला से कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल भी इस समस्या को सुलझाने के प्रति गंभीर नहीं हैं। अपनी पार्टी का मामला आते ही महिला नेता भी पीड़ित की बजाय अपनी पार्टी लाइन के अनुसार बयान देती हैं। उन्हें लगता है कि महिला उत्पीड़न के मामले में सभी लोगों को एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए, इसके बाद ही महिलाओं को उत्पीड़न से बचाया जा सकता है।

नहीं डालेंगे अपना वोट तो सरकार से कैसे कर सकेंगे सवाल..?

पहले चरण के मतदान के दौरान देश के कई हिस्सों में कई मतदान केन्द्रों पर मतदान का बहिष्कार के समाचार भी देखने सुनने को मिले। यह भी अपने आप में सही विकल्प नहीं कहा जा सकता। आखिर मतदान का बहिष्कार कर हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं।

18 वीं लोकसभा के लिए पहले चरण का 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रेल को देश के 13 राज्यों के 89 लोकसभा सीटों के लिए होने जा रहा है। पहले चरण का मतदान 2019 की तुलना में कम हुआ है। यह अपने आप में चिंतनीय हो जाता है। मतदान कम होने के कारणों का विश्लेषण करने का ना तो यह सही समय है और ना ही यह विश्लेषण का समय है कि मतदान कम होने से किसे लाभ होगा या किसे हानि होगी। लाभहानि का आकलन करना राजनीतिक दलों का विषय हो सकता है। पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिकों द्वारा मताधिकार का उपयोग नहीं करना अपने आप में गंभीर हो जाता है। एक और हम निर्वाचित सरकार से अपेक्षाएं रखते हैं और रखनी भी चाहिए वहीं हम अपनी सरकार चुनने के लिए घर से मतदान करने के लिए भी निकलना अपनी तोहिन समझने लगते हैं। आखिर इतनी गैर जिम्मेदार नागरिक हम कैसे हो सकते हैं? यहां पर बरबस देश की सर्वोच्च अदालत की टिप्पणी पर ध्यान चला जाता है कि जब हम मतदान के दायित्व को पूरा नहीं कर सकते तो फिर चुनी हुई सरकार से सवाल करने या उससे किसी तरह की अपेक्षा रखने का हक भी हमें नहीं होना चाहिए। एक एनजीओ के द्वारा दायर पीएल को इसी भावार्थ के साथ खारिज कर दिया गया था। वैसे भी हमारा दायित्व हो जाता है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में हम थोड़ा सा समय निकाल कर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। पांच साल में एक बार मिलने वाले अवसर को नकारात्मक सोच या गैरजिम्मेदारी से खो देना किसी भी हालात में उचित नहीं माना जा सकता।

लोकतंत्र के महायज्ञ में प्रत्येक मतदाता को अपने मताधिकार का उपयोग कर मतदान करके अपनी आहुति देने का अवसर मिलता है। ऐसे में मतदान का बहिष्कार या फिर लापरवाही के कारण मतदान नहीं करना किसी अक्षम्य अपराध से कम नहीं कहा जा सकता है। वर्तमान सिनेरियों में नोटा प्रयोग भी मंथन का विषय होना चाहिए। नोटा के प्रवधान को लेकर पक्ष विपक्ष में अनेक तर्क दिए जा सकते हैं पर समय आ गया है कि उस पर बड़ी बहस हो और उसको अधिक प्रभावी या कारगर बनाने के प्रावधान किये जाये। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मतदान को लेकर की गई टिप्पणी भी इस मायने में महत्वपूर्ण हो जाती है कि यदि हम मताधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं तो फिर सरकार के खिलाफ किसी तरह की ग्रिवेंस करना उचित नहीं ठहराया जा सकता। सजग व जिम्मेदार नागरिक के रुप में प्रत्येक मतदाता का दायित्व हो जाता है कि वह अपने मताधिकार का प्रयोग करे। अब तो निर्वाचन आयोग ने मतदान सुविधाजनक भी बना दिया है। बुजुर्ग व दिव्याग मतदाताओं को घर बैठे मतदान का अवसर प्रदान कर दिया हैं वहीं मतदाताओं के लिए जागरुकता अभियान से लेकर निष्पक्ष चुनाव के लिए कारगर कदम उठाये जाने लगे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव तिथियों की घोषणा करते समय साफ कर दिया कि आयोग चार एम पर प्रभावी कार्यवाही करने को प्रतिवद्ध है और उसकी सूक्ष्म मोनेटरिंग की जा रही है।

भारत : तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से पहले रोजगार में वृद्धि की जरूरत

इन दिनों हर जगह तकरीबन इस बात की ही चर्चा रहती है कि भारत बड़ी तेजी से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। पर इस बात के पीछे क्या आर्थिक तथ्य और साक्ष्य हैं? पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का तमगा भारत को 2022 में मिला, जब उसने अर्थव्यवस्था के जीडीपी के आकार में इंग्लैंड को पीछे छोड़ा। 2014 में भारत दसवें पायदान पर हुआ करता था। उस समय भारत का जीडीपी 18.6 खरब अमेरिकी डॉलर के बराबर था और भारत से आगे तब क्रमशः इटली (21.4 खरब डॉलर), ब्राजील (22.1 खरब डॉलर), इंग्लैंड (27.9 खरब डॉलर), फ्रांस (28.1 खरब डॉलर), जर्मनी (37 खरब डॉलर), जापान (52.1 खरब डॉलर), चीन (95.7 खरब डॉलर) तथा सबसे आगे अमेरिका (175.5 खरब डॉलर) थे। इससे साबित होता है कि पिछले एक दशक में भारत के जीडीपी में तकरीबन दो गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। यह अपने आप में आश्चर्यजनक है, क्योंकि इस दौरान पूरे विश्व ने कोरोना महामारी के चलते लगभग दो वर्षों तक आर्थिक मंदी के दौर को देखा है और भारतीय अर्थव्यवस्था ने तो उस दौरान आजादी के बाद पहली दफा लगभग 25 फीसदी की नकारात्मक विकास दर को भी सहन किया था।

भारत के तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का पहली दफा उल्लेख अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने किया था। उसने भारत की लगातार चल रही छह और सात फीसदी की वार्षिक आर्थिक प्रगति दर को देखते हुए अनुमान लगाया कि वर्ष 2027 तक भारत का जीडीपी 50 खरब अमेरिकी डॉलर के स्तर से ऊपर निकल जाएगा। अभी भारत से आगे चल रहे जर्मनी और जापान तब क्रमश 49.5 खरब डॉलर और 50.8 खरब डॉलर के स्तर पर रहते हुए भारत से पीछे होंगे और तब भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। लेकिन इस हकीकत को भी समझना अत्यंत आवश्यक है कि भारत आज भी प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से बहुत पीछे है। अगर इंग्लैंड से ही तुलना की जाए, जिसे पीछे छोड़कर भारत पांचवीं अर्थव्यवस्था बना है, तो प्रति व्यक्ति आय में आज भी दोनों देशों में 20 गुना का अंतर है।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2012 में भारत में तकरीबन एक करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार थे, जबकि 2022 में इनकी संख्या 2.29 करोड़ तक जा पहुंची थी, जिसके चलते बेरोजगारी की दर पिछले 10 वर्षों में 2.18 फीसदी से बढ़कर चार फीसदी पर पहुंच गई।

इसके अलावा, पिछले एक दशक में प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से वैश्विक रैंकिंग में भारत मात्र छह पायदान ही ऊपर आया है। वर्तमान समय में 189 देशों में से भारत प्रति व्यक्ति आय में 141वें स्थान पर है, जबकि 2013-14 में भारत 147वें स्थान पर था। इससे स्पष्ट है कि पिछले एक दशक में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी लगभग आधी से ही अधिक हुई है, जबकि जीडीपी दोगुना से अधिक बढ़ा। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2012 में भारत में तकरीबन एक करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार थे, जबकि 2022 में इनकी संख्या 2.29 करोड़ तक जा पहुंची थी, जिसके चलते बेरोजगारी की दर पिछले 10 वर्षों में 2.18 फीसदी से बढ़कर चार फीसदी पर पहुंच गई।

इसके अलावा, भारत का कृषि क्षेत्र बहुत पीछे हो चुका है। जीडीपी में उसके अंशदान को बढ़ाना अब अत्यंत आवश्यक हो गया है, अन्यथा प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी बहुत आसानी से नहीं की जा सकती। 50 फीसदी जनसंख्या का रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर रहना ही इसका प्रमुख कारण है। इसके अलावा, विनिर्माण क्षेत्र, जो रोजगार सृजन का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, को बड़ी तेजी से मुख्यधारा में लाना होगा।

सरकारी स्कूलों के 90 हजार विद्यार्थियों को जुलाई तक लैपटाप की राशि मिलने की उम्मीद

इस बार प्रदेश के 12वीं पास 90 हजार 400 विद्यार्थियों को लैपटाप के लिए 25-25 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। इस पर सवा दो सौ करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च होगी। दरअसल, प्रदेश में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल से 12वीं में 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले मेधावी विद्यार्थियों को लैपटाप के लिए 25-25 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। पिछले साल 78 हजार 641 विद्यार्थियों को लैपटाप खरीदने के लिए राशि दी गई थी। यह संख्या पिछले साल की तुलना में 11 हजार 759 अधिक है।

वहीं इस बार प्रदेश के स्कूलों के दो टापर विद्यार्थियों को स्कूटी भी प्रदान की जाएगी। यह संख्या करीब सात हजार है। जुलाई तक लैपटाप की राशि मिलने की संभावना है। स्कूल शिक्षा विभाग ने माध्यमिक शिक्षा मंडल से मेधावी विद्यार्थियों के आंकड़े मागे हैं। वहीं, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पिछले साल की घोषणा पर अमल किया गया तो इस बार से सीबीएसई के विद्यार्थियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। हालांकि फिलहाल इस पर संशय है। विभाग के उपसचिव प्रमोद सिंह ने बताया कि इस साल 90 हजार 400 विद्यार्थियों को लैपटाप की राशि दी जाएगी।

सीबीएसई के विद्यार्थियों पर संशय बरकरार

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मप्र बोर्ड के मेधावी विद्यार्थियों को लैपटाप की राशि देने के लिए पिछले साल 20 जुलाई को लाल परेड ग्राउंड में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मप्र बोर्ड के 12वीं में 75 फीसद से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 78 हजार 641 विद्यार्थियों के खाते में लैपटाप खरीदने के लिए 196 करोड़ की राशि ट्रांसफर की थी। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि मप्र की 12वीं के विद्यार्थियों के साथ सीबीएसई के मेधावी विद्यार्थियों को अगले साल से 25-25 हजार रुपये की राशि लैपटाप के लिए मिलेगी, लेकिन अब तक विभाग को इस बारे में निर्देश नहीं दिए गए हैं। अगर सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थी योजना में शामिल होंगे तो करीब एक लाख विद्यार्थी और बढ़ जाएंगे। हालांकि चुनावी आचार संहिता खत्म होने के बाद इस पर निर्णय लिया जा सकता है।

सात हजार विद्यार्थियों को देंगे स्कूटी

इस बार भी 12वीं के सभी स्कूलों के टापर को स्कूटी प्रदान की जाएगी। इसमें सात हजार विद्यार्थी शामिल हैं। पिछले साल सरकारी स्कूल के हर एक टापर को स्कूटी दी गई थी। हालांकि उस दौरान कार्यक्रम में निजी स्कूल के विद्यार्थियों को शामिल करने की बात कही गई थी, लेकिन अभी इस पर अमल नहीं हुआ है। इसमें सरकारी स्कूलों के 12वीं पास एक टापर को स्कूटी भी देने की योजना शुरू की है। वह सिर्फ स्कूल में टापर होना चाहिए। चाहे वह 12वीं में द्वितीय श्रेणी से ही क्यों ना पास हुआ हो।

वर्ष 2009-10 में शुरू हुई थी योजना

मप्र बोर्ड 12वीं के मेधावी वद्यार्थियों को लैपटाप के लिए 25-25 हजार रुपये की राशि देने की योजना मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत वर्ष 2009-10 में शुरू की गई थी। योजना के प्रारंभ में 85 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को लैपटाप दिया गया था। इस दौरान विद्यार्थियों की संख्या भी 20 से 25 हजार के आसपास होती थी। इसके बाद एक साल 70 प्रतिशत तक अंक कर दिए गए थे। वर्तमान में 12वीं में 75 प्रतिशत अंक से अधिक वालों को लैपटाप की राशि प्रदान की जाएगी।

संविधान की प्रस्तावना नहीं बदलेगी सरकार आरक्षण रहेगा बरकरार : सिंह

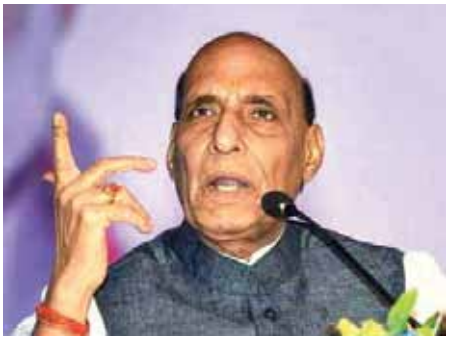

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार कभी भी संविधान नहीं बदलेगी और न ही आरक्षण खत्म करेगी। उन्होंने कांग्रेस पर "भय" पैदा करने और वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। सिंह ने एक साक्षात्कार के दौरान कांग्रेस पर यह अफवाह फैलाने का आरोप लगाया कि भाजपा सत्ता में रही तो संविधान बदल देगी। उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि संविधान की प्रस्तावना को बदलने का कोई सवाल ही नहीं है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि भाजपा अगर सत्ता में रही तो वह संविधान को "फाड़कर फेंक देगी।" कांग्रेस के कुछ अन्य पदाधिकारियों ने आशंका जताई है कि भाजपा संविधान की प्रस्तावना से "धर्मनिरपेक्ष" शब्द हटा सकती है। रक्षा मंत्री ने कहा, "कांग्रेस ने संविधान में 80 बार संशोधन किए। उन्होंने आपातकाल के दौरान प्रस्तावना में बदलाव किया।" सिंह ने कहा, "भाजपा संविधान नहीं बदलेगी। संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा था कि प्रस्तावना में कोई बदलाव होगा। आपने (कांग्रेस) संविधान के मूल विचार को चोट पहुंचाने का काम किया।"

उन्होंने कहा, संविधान की प्रस्तावना को बदलने का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने इसे बदल दिया और अब वे हम पर निराधार आरोप लगा रहे हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान के सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है। साल 1976 में 42वें संशोधन के तहत भारत के परिचय को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया था। सिंह ने कहा, ''वे (कांग्रेस) नागरिकों में डर पैदा करके लोगों का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।'' उन्होंने कहा, ''मैं सुझाव देना चाहता हूं कि उन्हें विश्वास पैदा करके लोगों का समर्थन हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, न कि डर पैदा करके। चुनावी अभियान तथ्यों पर आधारित होना चाहिए।

शुक्रवार को राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) भारत के लोकतंत्र पर लगातार हमला कर रहे हैं तथा देश के संविधान को नष्ट करना चाहते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा, कांग्रेस भय का माहौल पैदा कर रही है और वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैला रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरक्षण के मुद्दे पर भी कांग्रेस देश को गुमराह कर रही है। सिंह ने कहा, ''कांग्रेस लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। आरक्षण खत्म नहीं होगा। वे हम पर झूठे आरोप लगा रहे हैं।''

कांग्रेस ने भाजपा नेताओं से इस बारे में पार्टी का रुख स्पष्ट करने को कहा है कि क्या वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा हटा देगी।

भू-राजनीति में रचा गया इतिहास

अंतरराष्ट्रीय दबाव के बीच भारत और ईरान के साथ ऐतिहासिक अनुबंध

भारत द्वारा ईरान से चाबहार बंदरगाह के प्रबंधन के लिए किया गया दस वर्षीय अनुबंध भू-राजनीतिक दृष्टि से एक जबर्दस्त रणनीतिक कदम है। इससे न केवल चीन के बेल्ट ऐंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला किया जा सकता है, बल्कि पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह भी संतुलित होगा।

लोकसभा चुनाव के ऐन बीच में भारत द्वारा ईरान से चाबहार बंदरगाह के प्रबंधन के लिए किया गया दस वर्षीय अनुबंध को भू-राजनीतिक दृष्टि से एक जबर्दस्त रणनीतिक कदम बताया जा रहा है। भारत द्वारा किसी विदेशी या बाहरी बंदरगाह के प्रबंधन का यह पहला प्रयास है। ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में स्थित गहरे पानी का बंदरगाह चाबहार भारत के सबसे नजदीक खुले समुद्र में स्थित है, जहां भारी मालवाहक जहाज सरलतापूर्वक सुरक्षित रूप से पहुंच सकते हैं। साथ ही इस बंदरगाह में भारत, ईरान, अफगानिस्तान और यूरेशिया को आपस में जोड़ने की क्षमता है और यह चीन के बेल्ट ऐंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) का वैकल्पिक रास्ता मुहैया करवा सकता है।

जाहिर है, क्षेत्रीय दृष्टि से इस कदम के दूरगामी परिणाम होंगे। इससे न केवल चीन के बेल्ट ऐंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला किया जा सकता है, बल्कि पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह भी संतुलित होगा। चाबहार को इंटरनेशनल नार्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (आईएनएसटीसी) से जोड़ने की भी योजना है, जिससे ईरान से होकर भारत के लिए रूस का रास्ता भी खुल जाएगा। यह बंदरगाह पाकिस्तान को दरकिनार कर अफगानिस्तान और केंद्रीय एशिया के लिए भी भारत का रास्ता साफ करेगा।

विदेश मंत्रालय के जानकार सूत्रों के अनुसार, इस दिशा में पिछले साल से ही काम चल रहा था। पिछले वर्ष अगस्त में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के बीच हुई चर्चा में चाबहार मुख्य मुद्दा था। फिर नवंबर में दोनों नेताओं की फोन पर हुई बातचीत का केंद्र बिंदु भी चाबहार बंदरगाह ही था। वर्ष 2018 में तत्कालीन ईरानी राष्ट्रपति रूहानी की भारत यात्रा में बंदरगाह के विकास में भारत की बढ़ी हुई भूमिका का मुद्दा और परवान चढ़ा। फिर विदेश मंत्री एस. जयशंकर की इसी साल जनवरी में हुई तेहरान यात्रा में बात और आगे बढ़ी। ऐसा नहीं है कि यह समझौता पहली बार हुआ है। वस्तुतः यह समझौता 2016 में मोदी की ईरान यात्रा के दौरान ही हो चुका था। मूल समझौते में चाबहार बंदरगाह के बहिश्ती टर्मिनल के ऑपरेशन ही शामिल थे, जिसका हर साल नवीनीकरण होता था। मई 2016 में भारत ने शाहिद बहिश्ती टर्मिनल के विकास के लिए अफगानिस्तान और ईरान के साथ एक त्रिपक्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। अब यह दीर्घकालीन अनुबंध प्रारंभिक समझौते का स्थान लेगा। पिछले दो दशकों में चीन और भारत क्रमशः दुनिया की दूसरी और पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के रूप में ऊपर उठ चुके हैं। व्यापार और सुरक्षा के क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए इन दोनों एशियाई महाशक्तियों ने अंतरराष्ट्रीय गलियारों-विशेष रूप से हिंद महासागर पर ध्यान केंद्रित किया है। हिंद महासागर क्षेत्र में तीन महाद्वीपों के 28 देश आते हैं, जिनमें से कुछ तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाएं भी शामिल हैं। इस क्षेत्र में विश्व के अत्यधिक मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे दुनिया के 16.8 प्रतिशत तेल भंडार और वैश्विक प्राकृतिक गैस के 27.9 प्रतिशत भंडार। चीन ने हिंद महासागर में अपने रणनीतिक हितों के संरक्षण के लिए 'मोतियों की लड़ी' (स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स) की समुद्री रणनीति अपनाई है। बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव और तंजानिया जैसे तटीय दक्षिण एशियाई और अफ्रीकी देशों में बंदरगाहों की दीर्घकालीन पट्टे और उनके निर्माण में भारी निवेश उसकी इस रणनीति का एक हिस्सा है। हिंद महासागर में चीन की इस संलिप्तता के जवाब में भारत ने हिंद महासागर के देशों के साथ सहयोग, वार्ता, विकास में मदद और निवेश के लिए अपनी 'हीरों का हार' (नेकलेस ऑफ डायमंड्स) रणनीति बनाई है।

वस्तुतः यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यापक 'लुक ईस्ट' योजना का हिस्सा है, जो आसियान देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने और चीन के समुद्री वर्चस्व से उपजी चिंताओं से निपटने के लिए बनाई गई है। हिंद महासागर में चीन और भारत के बीच प्रतिस्पर्धा का सर्वाधिक स्पष्ट पहलू है-पाकिस्तान का चीन संचालित ग्वादर बंदरगाह और ईरान का भारत द्वारा संचालित चाबहार बंदरगाह।

मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान केंद्रीय एशियाई देशों को हिंद महासागर क्षेत्र में पहुंच बनाने के लिए कराची बंदरगाह का इस्तेमाल करने के लिए काफी समय से ललचा रहा है। जबकि भारत इन्हीं देशों को यह संकेत दे रहा है कि कराची की तुलना में चाबहार अधिक आकर्षक विकल्प है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे प्रचुर संसाधन वाले, किंतु मार्गहीन केंद्रीय एशियाई देश हिंद महासागर क्षेत्र और भारतीय बाजार तक पहुंच बनाने के लिए चाबहार बंदरगाह का उपयोग करने के लिए काफी उत्सुक हैं। यह बंदरगाह केंद्रीय एशिया में रुचि रखने वाले भारतीय व्यापारियों और निवेशकों के लिए भी काफी उपयोगी साबित होगा।

आने वाले दशकों में ग्वादर और चाबहार बंदरगाह नजर रखने लायक मुख्य क्षेत्र होंगे, क्योंकि हिंद महासागर में भारत-चीन प्रतिद्वंद्विता स्पर्धा के एक बड़े इलाके को चिह्नित करेगी। प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से क्षेत्र की महत्वपूर्ण भू-रणनीतिक प्रकृति के मद्देनजर हिंद महासागर में चीन, भारत और अन्य उभरते हुए देशों द्वारा रणनीतिक बढ़त हासिल करने के गंभीर वैश्विक परिणाम होंगे।

राह नहीं आसान; भाजपा को फायदा

कांग्रेस के मजबूत प्रत्याशियों को कमजोर कर रही गुटबाजी...

एक तो संगठन नहीं होने के चलते भाजपा के मुकाबले कांग्रेस बूथ स्तर तक पहुंचने में पिछड़ रही है। दूसरा, प्रदेश के दिग्गज नेताओं की गुटबाजी भी पार्टी के लिए घातक साबित हो रही है। अभी तक हरियाणा में पार्टी के स्टार प्रचारक नहीं उतर पाए हैं। केवल पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ही कमान संभाल रहे हैं। ये दोनों भी सिरसा जाने से बच रहे हैं। कांग्रेस अभी तक हाईकमान के नेताओं के लिए रैलियों की तारीख व स्थान भी तय नहीं कर पाई है। दूसरी तरफ, भाजपा के सीएम और पूर्व सीएम प्रदेश के 86 विजय संकल्प रैलियां कर चुके हैं। इसके अलावा 16 मई से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी हरियाणा में दस्तक देकर धड़ाधड़ रैलियां करके अपने पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास करेगा। कई सर्वे के बाद 26 अप्रैल को जब कांग्रेस ने प्रदेश की आठ लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे तो उस समय प्रदेश में अचानक से कांग्रेस की हवा बनी और लोगों में चर्चा थी कि इस बार कांग्रेस कई सीटों पर जीत सकती है। आम व्यक्ति से लेकर सट्टा बाजार और चुनावी विश्लेषक तक कांग्रेस की पांच सीटों पर जीत तय मान रहे थे, लेकिन जैसे-जैसे मतदान की तिथि नजदीक आ रही है, भाजपा ने पूरी ताकत के साथ जमीनी स्तर पर काम तेज कर दिया है और दूसरी तरफ कांग्रेस का प्रचार कमजोर पड़ रहा है।

हरियाणा में लोकसभा चुनाव में अब महज 10 दिन का समय बचा है। चुनाव प्रचार अब आठ दिन और चलेगा। दोनों पार्टियों का आकलन करें तो अब तक भाजपा 86 विजय संकल्प रैलियां कर चुकी है। मनोहर और नायब सिंह सैनी की जोड़ी अधिकतर विधानसभा हलकों को कवर कर चुकी है। वहीं, देरी से प्रत्याशी उतारने के चलते भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र अब तक सात लोकसभा क्षेत्रों में 28 रैलियां ही कर पाए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पंचकूला में रोड शो कर चुके हैं और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भी हरियाणा में प्रचार में उतर चुके हैं। 16 मई से उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी प्रचार को धार देने आएंगे।

इसके बाद हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बारी आएगी। पीएम नरेंद्र मोदी की चार रैलियां और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के तीन कार्यक्रम तय हो चुके हैं। वहीं, कांग्रेस आलाकमान की ओर से अभी तक कोई बड़ा नेता हरियाणा में नहीं आ पाया है।

कांग्रेस ने 40 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया है। इनमें मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी केंद्रीय नेता हैं। इनके अलावा हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह, पूर्व मंत्री आनंद शर्मा, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, अजय माकन, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल व सचिन पायलट समेत अन्य नाम शामिल हैं। इनमें से कोई भी नेता हरियाणा नहीं आया है। इनके अलावा हरियाणा के ही नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला सिर्फ सिरसा लोकसभा क्षेत्र तक सीमित हैं, जबकि अन्य विधायक और पूर्व विधायक भी अपने-अपने हलकों में ही सक्रिय हैं।

चुनाव विशेषज्ञों का मानना है कि किसान आंदोलन के नाम पर भाजपा और जजपा प्रत्याशियों के विरोध किए जाने से भी भाजपा को फायदा मिलने की संभावना है। इससे मतदाता मुखर व साइलेंट दो भागों में बंट गए हैं। जो शांत हैं, वह अधिकतर भाजपा के साथ जा सकते हैं। इसी कारण जहां-जहां विरोध हो रहा है, भाजपा उस क्षेत्र और गांव के साइलेंट मतदाताओं पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने की तैयारी कर रही है। चुनाव की घोषणा से पहले महिला पहलवानों के यौन शोषण का मुद्दा पूरे देश में गूंजा, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में कामयाब नहीं रही, जबकि आंदोलन के समय कांग्रेस ने खुलकर खिलाड़ियों का साथ दिया था, लेकिन चुनाव में इस मुद्दे को लेकर कांग्रेसी नेता सरकार को घेरने में सफल नहीं हुए। इसके अलावा किसानों के मुद्दों पर भी कांग्रेस नेता उनके साथ खड़े नजर नहीं आ रहे हैं।

मजबूत प्रत्याशियों और एंटी इंकमबेंसी के चलते कांग्रेस के पक्ष में बनी हवा के बावजूद लोकसभा चुनाव पार्टी के लिए अब इतना आसान नहीं लग रहा। प्रदेश में कांग्रेस के लिए कई चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। मतदान की तिथि तक अपने पक्ष में माहौल को बनाए रखना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है।

चुनाव से पहले तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश में बेरोजगारी दर बढ़ने का मुद्दा कई बार उठाया, लेकिन चुनाव आते-आते यह मुद्दा भी ठंडा पड़ गया है। कद्दावर नेताओं को सौंपी मोदी की रैली की जिम्मेदारी... पिछले डेढ़ महीने से विजय संकल्प रैलियां और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच जा रही भाजपा चुनाव प्रचार को इन आठ दिनों में और गति देने की तैयारी में है।भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां के प्रबंधन के लिए अपने कद्दावर नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। जींद के विधायक डॉ. कृष्ण मिढ़ा गोहाना में होने वाली प्रधानमंत्री की रैली का प्रबंधन संभालेंगे। अंबाला की रैली का प्रबंधन मंत्री कंवरपाल व महेंद्रगढ़ रैली की जिम्मेदारी मुख्य प्रवक्ता जवाहर यादव देखेंगे।

विकास के दौर में नासूर बनती बाल विवाह जैसी कुप्रथा...

देश में बाल विवाह के 50 प्रतिशत से अधिक मामले केवल 5 राज्यों से संबंधित हैं जिनमें उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। शेष चार राज्यों में बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश शामिल हैं। वर्तमान में भारत में बाल विवाह के लगभग 22 प्रतिशत मामले हैं जो कि लगातार कम हो रहे हैं।

हमारे देश में प्राचीन समय से कुछ ऐसी प्रथाएं चली आ रही है। जिसका लोगों के दैनिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जिनमें बाल विवाह भी एक हैं। किसी भी बच्चे की शादी उसके निश्चित आयु से पहले यानी बाल्यकाल में होना बाल विवाह कहलाता है। यह एक रूढ़िवादी प्रथा है। यह प्रथा बच्चों की सारे मनवा अधिकारों को खत्म कर देता है। जैसे- खेलकूद, मनोरंजन, शिक्षा आदि के अधिकारों को समाप्त कर उन्हें ऐसे बंधन में बांध दिया जाता है, जिसके बारे में उन्हें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है। प्राचीन सभी प्रथाओं में बाल विवाह सबसे बड़ा कुप्रथा है। क्योंकि कम उम्र में बच्चों की शादी कर देने से उनके स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक विकास के साथ-साथ उनके खुशहाल जीवन पर असर पड़ता है। साथ ही वह अपने शिक्षा और खेलकूद के अधिकारों आदि से वंचित रह जाते हैं। इस कुप्रथा का शिकार ज्यादातर कम उम्र की लड़कियां होती है। बाल्यकाल में विवाह होने से बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास नहीं हो पाता है।

विकास के दौर में बाल विवाह एक नासूर के समान है। देश में हर व्यक्ति को शिक्षित करने की मुहिम चल रही है। हर व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में बाल विवाह होना समाज के माथे पर एक कलंक के समान है। देश में अक्षय तृतीया (आखा तीज) पर हर वर्ष हजारों की संख्या में बाल विवाह किए जाते हैं। तमाम प्रयासों के बाबजूद हमारे देश में बाल विवाह जैसी कुप्रथा का अन्त नही हो पा रहा है। भारत में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान के शुरू होने के बावजूद एक नाबालिग बेटी की जबर्दस्ती शादी करा दी जा रही है। बाल विवाह मनुष्य जाति के लिए एक अभिशाप है। यह जीवन का एक कड़वा सच है कि आज भी छोटे-छोटे बच्चे इस प्रथा की भेंट चढ़े जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जगह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। देश के सभी प्रदेशों में बेटियां शिक्षित हो रही है। ऐसे में समाज को आगे आकर कम उम्र में लड़कियों के होने वाले बाल विवाह रुकवाने के प्रयास करने होंगे। आजकल कई लड़कियां खुद भी आगे आकर अपना बाल विवाह रुकवाने का प्रयास करने लगी है। भारत में यह प्रथा लम्बे समय से चली आ रही है जिसके तहत छोटे बच्चों का विवाह कर दिया जाता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि आज के पढ़े लिखे समाज में भी यह प्रथा अपना स्थान बनाए हुए है। जो बच्चे अभी खुद को भी अच्छे से नहीं समझते। जिन्हें जिन्दगी की कड़वी सच्चाईयों का कोई ज्ञान नहीं। जिनकी उम्र अभी पढने लिखने की होती है। उन्हे बाल विवाह के बंधन में बांधकर क्यों उनका जीवन बर्बाद कर दिया जाता है।

देश में बाल विवाह के 50 प्रतिशत से अधिक मामले केवल 5 राज्यों से संबंधित हैं जिनमें उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। शेष चार राज्यों में बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश शामिल हैं। वर्तमान में भारत में बाल विवाह के लगभग 22 प्रतिशत मामले हैं जो कि लगातार कम हो रहे हैं। इसके प्रमुख कारणों में महिलाओं में साक्षरता और जागरूकता का बढ़ना, शिक्षा के प्रसार के कारण लड़कियों के प्रति अभिभावकों की सोच में परिवर्तन आना, शहरीकरण में वृद्धि तथा कठोर कानूनों की उपस्थिति को माना जा सकता है।

भारत में बाल विवाह में गिरावट आई है। लेकिन देश में पांच लड़कियों में से एक और छह लड़कों में से एक की अभी भी बचपन में शादी कर दी जाती है। हाल के वर्षों में यह प्रथा कुछ राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में अधिक प्रचलित हो गई है। दिसंबर 2023 में द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार यह अनुमान लगाने वाले पहले अध्ययनों में से एक है कि राज्य व केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर समय के साथ लड़की और लड़के के बाल विवाह की दर में क बदलाव आया है। अध्ययन में पाया गया कि 1993 से 2021 के बीच राष्ट्रीय स्तर पर बाल विवाह में गिरावट आई है। बालिका बाल विवाह का प्रचलन 1993 में 49 प्रतिशत से घटकर 2021 में 22 प्रतिशत हो गया। जबकि बालक बाल विवाह 2006 में 7 प्रतिशत से घटकर 2021 में 2 प्रतिशत हो गया। बाल विवाह के प्रचलन में सबसे बड़ी कमी 2006 और 2016 के बीच हुई। सबसे कम कमी 2016 से 2021 के बीच हुई। इन बाद के वर्षों के दौरान छह राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में बालिका विवाह में वृद्धि देखी गई।

आंकड़ों से साफ है कि आजादी के 77 साल बाद भी इस देश में महिलाओं की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं आया है। हम अपनी बेटियों को बाल विवाह और कम उम्र की गर्भावस्था से नहीं बचा पाए हैं। यही कारण है कि इस देश में 50 फीसदी से ज्यादा महिलाएं और बच्चे एनीमिया (रक्ताल्पता) के शिकार हैं। यूनिसेफ द्वारा जारी की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत के कई क्षेत्रों में अब भी बाल विवाह हो रहा है। इसमें कहा गया है कि पिछले कुछ दशकों के दौरान भारत में बाल विवाह की दर में कमी आई है। लेकिन कई प्रदेशों में यह प्रथा अब भी जारी है। रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह की यह कुप्रथा आदिवासी समुदायों सहित कुछ विशेष जातियों के बीच प्रचलित है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि बालिका शिक्षा की दर में सुधार, किशोरियों के कल्याण के लिये सरकार द्वारा किये गए निवेश व कल्याणकारी कार्यक्रम और इस कुप्रथा के खिलाफ सार्वजनिक रूप से प्रभावी संदेश देने जैसे कदमों के चलते बाल विवाह की दर में कमी देखने को मिली है। यूनिसेफ के अनुसार अन्य सभी राज्यों में बाल विवाह की दर में गिरावट लाए जाने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। किंतु कुछ जिलों में बाल विवाह का प्रचलन अब भी उच्च स्तर पर बना हुआ है।

यह रिपोर्ट हमारे सामाजिक जीवन के उस स्याह पहलू कि ओर इशारा करती हैं। जिसे अक्सर हम रीति-रिवाज व परम्परा के नाम पर अनदेखा करते हैं। देश में बाल विवाह के खिलाफ कानून बने हैं और समय-समय पर उसमें संशोधन कर उसे ओर प्रभावशाली बनाया गया हैं। फिर भी लगातार बाल विवाह हो रहे हैं। भारत में बाल विवाह पर रोक संबंधी कानून सर्वप्रथम सन् 1929 में पारित किया गया था। बाद में सन् 1949, 1978 और 2006 में इसमें संशोधन किये गए। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह कराने पर 2 साल की जेल व एक लाख रुपए का दंड निर्धारित किया है।

अगर सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद देश में बाल विवाह जैसी कुप्रथा का अन्त नही हो पा रहा है। तो इस असफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण है इसके प्रति सामाजिक जागरुकता की कमी। जब तक समाज में बाल विवाह रोकने के प्रति जागरूकता नहीं आएगी तब तक यह कुरीति खत्म नही होने वाली है। बाल विवाह एक सामाजिक समस्या है। सिर्फ कानून के भरोसे बाल विवाह जैसी कुप्रथा को नहीं रोका जा सकता है। देश में बाल विवाह जैसी कुप्रथा को जड़ से खत्म करना है तो इसके लिए समाज को ही आगे आना होगा तथा बालिकाओं के पोषण, स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करना होगा।

समाज में शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। अभिभावकों को बाल विवाह के दुष्परिणामों के प्रति जागरुक करना होगा। सरकार को भी बाल विवाह की रोकथाम के लिये बने कानून का कड़ाई से पालन करवाना होगा। बाल विवाह प्रथा के खिलाफ समाज में जोरदार अभियान चलाना होगा। साथ ही सरकार को विभिन्न रोजगार के कार्यक्रम भी चलाने होंगे ताकि गरीब परिवार गरीब परिवारों की बच्चियां बाल विवाह का निशाना न बन पाएं।

पीएम हैट्रिक की राह पर, विकसित भारत के निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं : अनुराग

ठाकुर ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर के पाकिस्तान का सम्मान करने वाले एक पुराने वीडियो का जिक्र करते हुए कहा, ''वे पाकिस्तान को कैसे याद करते हैं और पाकिस्तान कांग्रेस को कैसे याद करते हैं?''

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश की प्रगति के लिए शासन में निरंतरता को महत्वपूर्ण बताते हुए रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चुनावी हैट्रिक लगाने और विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं। ठाकुर ने एक साक्षात्कार में कहा कि विपक्ष द्वारा लगाया गया कोई भी आरोप मोदी के सामने टिक नहीं सकता। लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर विपक्ष के दावे को ''हास्यास्पद'' करार देते हुए ठाकुर ने विश्वास जताया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 370 सीट के लक्ष्य को हासिल करने की राह पर है, जिसमें पिछली बार जीती गई 303 सीट और 70 वे सीट शामिल हैं, जहां वह दूसरे स्थान पर रही थी।

ये 70 सीट उन 160 संसदीय क्षेत्रों का हिस्सा हैं, जिन्हें भाजपा ने 2019 के बाद व्यापक मंत्रिस्तरीय संपर्क कार्यक्रम शुरू करने के लिए चिह्नित किया था। ठाकुर ने कहा, ''तीसरे चरण के चुनाव के बाद मैं कह सकता हूं कि मोदी जी हैट्रिक पर हैं। मैं ऐसा एकतरफा मतदान के कारण कह रहा हूं। कांग्रेस कार्यकर्ता मैदान से पीछे हट गए हैं। सूरत और इंदौर में कांग्रेस उम्मीदवार चुनाव से हट गए। ओडिशा में कांग्रेस उम्मीदवार ने टिकट लौटा दिया। राहुल गांधी 2019 में अमेठी से भाग गए और वायनाड चले गए। अब वह रायबरेली आ गए हैं, मुझे नहीं पता कि वह आगे कहां जाएंगे।''

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से लगातार पांचवीं बार चुनाव लड़ रहे चार बार के सांसद ठाकुर ने कहा कि वह मोदी के नाम पर और सांसद के रूप में पिछले कुछ वर्षों में शुरू किए गए विकास कार्यों के नाम पर भी एक बार फिर लोगों से जनादेश मांग रहे हैं। उन्होंने कहा, ''स्थिरता और निरंतरता देश की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। यह सरकार को नीतियों और कार्यक्रमों को जारी रखने में सक्षम बनाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर बना रहे। जैसे कि यह 2014 से पहले 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से मोदी शासन के तहत पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया।''

ठाकुर ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर के पाकिस्तान का सम्मान करने वाले एक पुराने वीडियो का जिक्र करते हुए कहा, ''वे पाकिस्तान को कैसे याद करते हैं और पाकिस्तान कांग्रेस को कैसे याद करते हैं?'' उन्होंने यह भी सवाल किया कि 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' के लोग कांग्रेस में क्यों शामिल होते हैं और पीएफआई तथा एसडीपीआई कांग्रेस का समर्थन क्यों करती हैं। ठाकुर ने आरोप लगाया, ''जब भारत विरोधी ताकतें कांग्रेस का समर्थन करती हैं, तो स्वाभाविक सवाल उठता है कि कांग्रेस वोट के लिए किस हद तक गिर सकती है।'' यह पूछे जाने पर कि क्या 'नेशनल हेराल्ड' मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ मामले में तेजी लाई जाएगी, ठाकुर ने कहा कि जांच एजेंसियां कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने कहा, ''दोषियों को सजा देने में अदालत कितना समय लगाएगी, यह कोई तय नहीं कर सकता। हमारी तरफ से तो बहुत पहले ही राहुल जी, सोनिया जी और चिदंबरम जी के खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। निर्भया दुष्कर्म मामले में भी अपराध 2012 में हुआ था लेकिन सजा 2020 में दी गई।

एक दिन डायनासोर की तरह लुप्त हो जाएगी कांग्रेस : राजनाथ

वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेंगे

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 30 अप्रैल को खंडवा पहुंचे। उन्होंने जिले के पुनासा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने यहां खंडवा संसदीय क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में ये सभा की। उन्होंने कहा कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। 2014 और 2019 में आपने सरकार बनाई तो काम जन-जन तक पहुंचा। पहले भारत की बातों को दुनिया गंभीरता से नहीं लेती थी। लेकिन, अब दुनिया कान खोलकर भारत की बात सुनती है। भारत का कद तेजी से बढ़ा है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा था। बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। उस वक्त हमारे बच्चे मेडिकल, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की वहां पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि 10 साल बाद बच्चे से पूछोगे तो कहेगा कि कौन कांग्रेस? जैसे धरती से डायनासोर विलुप्त हो गए थे, वैसे कांग्रेस भी गायब हो जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस और यूक्रेन से बात की। साढ़े 4 घंटे युद्ध रोक दिया गया और हमारे बच्चे सुरक्षित वापस आ गए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। यहां विकास की बयार बह रही है। अब हमें विधानसभा और लोकसभा के चुनाव 5 वर्षों में एक बार में करा देने चाहिए। इस बार जो चुनाव होंगे, वो एक साथ कराएंगे, जो संशोधन होंगे वो कर देंगे। उन्होंने कहा कि उज्जैन में भव्य मंदिर, कॉरिडोर, काशी में भी कॉरिडोर, सोमनाथ में भी भव्य मंदिर बन गया है।

कांग्रेस को डूबने से कोई नहीं बचा सकता- राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री सिंह ने कहा कि कांग्रेस डूबता जहाज है। इसके तल में छेद हो गया है। इसे डूबने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। भारत में लोकतंत्र की बहाली हो गई है। खुद महात्मा गांधी ने कांग्रेस को भंग करने की बात कही थी। जनता ने इस बात को पूरा करने की ठान ली है। गरीबी मिटाने की बात कांग्रेस ने बार-बार कहकर जनता की आंखों में झूल झोंकी। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार देश में 8 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। सिंह ने कहा कि आगामी 3 साल में एक घर भी ऐसा नहीं मिलेगा, जो पक्का न हो। कांग्रेस अनर्गल आरोप लगाती है।

रक्षा मंत्री ने फिल्मों का दिया उदाहरण

फ्री राशन पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ खाते ही नहीं होंगे, बचाकर बेचते भी होंगे। कांग्रेस की सरकार में रोटी-कपड़ा और मकान फिल्म बनी थी, उसमें गाना था कि महंगाई मार गई। पीपली लाइव में महंगाई डायन खाए जात है, गाना बना। ये दोनों फिल्में कांग्रेस के शासनकाल में बनी थीं। आज भाजपा के शासनकाल में ऐसी फिल्म नहीं बनती, क्योंकि महंगाई दर कम हुई है।

मोदी का कांग्रेस को चैलेंज

370 फिर से लागू कराने की किसी में हिम्मत नहीं...

प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 को वापस लाना विपक्ष के अधिकार क्षेत्र में नहीं है. मोदी ने कहा कि भले ही वह जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री हों, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस या किसी अन्य विपक्षी दल को जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 वापस लाने की चुनौती दी है। विपक्षी नेताओं द्वारा अनुच्छेद 370 वापस लाने की घोषणा पर एक सवाल का जवाब देते हुए मोदी ने एक साक्षात्कार में कहा कि जो कोई भी भारत के संविधान, संघीय ढांचे और अधिकार क्षेत्र में क्या है, उसे समझता है, वह ऐसी बातें नहीं कहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 को वापस लाना विपक्ष के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मोदी ने कहा कि भले ही वह जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री हों, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें वही करेंगी जो उनके दायरे में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लेकिन लोगों को बेवकूफ बनाना आजकल एक चलन है। उन्हें अंधेरे में रखना। इसलिए वे कुछ भी बोलते रहते हैं।

मोदी ने कांग्रेस को एक प्रेस वार्ता आयोजित करने और घोषणा करने की चुनौती दी कि पार्टी अनुच्छेद 370 को बहाल करेगी। सबसे पुरानी पार्टी पर अपना हमला जारी रखते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस संविधान और बाबासाहेब अंबेडकर के बारे में 'बड़ी' बात करती है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान पूरे देश में लागू नहीं था। 70 वर्षों तक, भारतीय संविधान जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं था। प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में पहली बार दलितों और वाल्मिकियों को आरक्षण मिल रहा है। 5 अगस्त, 2019 को नरेंद्र मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया, जिससे जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हो गया। पूर्ववर्ती राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया था।

राजस्थान में चुनाव खत्म

जीत की अटकलों का बाजार गर्म... सबके अपने दावे

प्रदेश में इस बार लोकसभा चुनावों में मतदान भले ही पिछली बार की तुलना में कम हुआ हो लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता अपने-अपने गणित के साथ अपनी पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं। लोकसभा चुनावों में मतदान का प्रतिशत भले ही कम रहा हो लेकिन दोनों ही दिग्गज पार्टियों के नेता यहां अपनी-अपनी पार्टी की जीत का दावा करते हुए अलग-अलग गणित बैठा रहे हैं।

भाजपा नेता जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर मोहर लगने की बात कह रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस नेता कम मतदान को अपने पक्ष में बताते मोदी का जादू नहीं चलने की बात कह रहे हैं। भाजपा जहां शुरू से प्रदेश की सभी 25 सीटें जीतने का दावा कर रही है तो कांग्रेस का दावा है कि वे प्रदेश में अच्छी-खासी संख्या में सीटें जीतने वाले हैं। राजस्थान में पहले चरण में 12 लोकसभा तथा दूसरे चरण में 13 सीटों पर मतदान हुआ और देखा जाए तो पिछले चुनाव वर्ष 2019 की तुलना में कुल सारी 25 सीटों पर 4.54 प्रतिशत कम मतदान हुआ। इस कम मतदान को लेकर भाजपा ने केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट भेजा है कि पार्टी का मार्जिन घट सकता है लेकिन नुकसान नहीं होगा। भाजपा सभी 25 सीटें जीतेगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता मान रहे हैं कि पार्टी को 8 से 11 सीटों पर फायदा होगा और चार से पांच सीटों पर नजदीकी मामला बन सकता है। जहां कांग्रेस दौसा, सवाई माधोपुर, झुंझुनू, कोटा, भरतपुर, सीकर, जयपुर ग्रामीण आदि सीटों पर बढ़त मानी रही है, वहीं भाजपा तर्क देते हुए कह रही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता उदासीन रहे और वोट डलवाने नहीं निकले, भाजपा कार्यकर्ताओं ने वोट डलवाए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कम मतदान का फायदा कांग्रेस को मिलेगा। राज्य के जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का कहना है कि भाजपा का 400 पार का नारा पूरा होगा। भाजपा प्रत्याशी तीन लाख मतों से जीतेंगे। राजस्थान में मोदी की लहर चल रही है, हम सभी सीटें जीतेंगे और 400 का लक्ष्य पार होगा।

यह चुनाव लोकतंत्र और देश के संविधान बचाने का : राहुल

सत्ता में आने पर हटा देंगे 50% आरक्षण सीमा

राहुल ने कहा कि हमारे लिए आदिवासी का मतलब- जो देश के सबसे पहले मालिक हैं। लेकिन भाजपा के लोग आपको 'वनवासी' कहते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं आपको जल-जंगल-जमीन न मिले। उन्होंने कहा कि आरक्षण एक सोच है। इसका मतलब है हिंदुस्तान के पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों को उनकी भागीदारी मिलनी चाहिए।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी पहले '400 पार' का नारा दे रहे थे और अब 150 पार भी नहीं बोल रहे। क्योंकि.. जनता समझ गई है कि भाजपा के लोग 400 पार के नारे की आड़ में संविधान और गरीबों के अधिकार छीनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देश में आरक्षण, वोट, अधिकार.. ये सभी संविधान की देन हैं। अगर संविधान नहीं रहा तो आदिवासी साथियों के हाथ से जल-जंगल-जमीन गायब हो जाएंगे। हम जिन्हें 'आदिवासी' कहते हैं, भाजपा के लोग उन्हें 'वनवासी' कहते हैं। कांग्रेस के चुनावी वादों पर प्रकाश डालते हुए गांधी ने कहा कि 'इंडिया' के सत्ता में आने के बाद 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा हटा दी जाएगी।

राहुल ने कहा कि हमारे लिए आदिवासी का मतलब- जो देश के सबसे पहले मालिक हैं। लेकिन भाजपा के लोग आपको 'वनवासी' कहते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं आपको जल-जंगल-जमीन न मिले। उन्होंने कहा कि आरक्षण एक सोच है। इसका मतलब है हिंदुस्तान के पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों को उनकी भागीदारी मिलनी चाहिए। लेकिन.. जब ये सरकारी चीजों को प्राइवेट करते हैं, आरक्षण को खत्म करते हैं। अग्निवीर जैसी स्कीम लाते हैं, आरक्षण को खत्म करते हैं। उन्होंने कहा कि पब्लिक सेक्टर में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को जगह मिलती थी, लेकिन जैसे ही उसे प्राइवेट किया जाता है, इनको जगह नहीं मिलती।

गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। उन्होंने संविधान की पुस्तक को दिखाते हुए कहा, यह चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है, संविधान को प्रधानमंत्री जी, भाजपा के नेता और आरएसएस के लोग बदलना और खत्म करना चाहते हैं।

एक तरफ वह संविधान को खत्म करने में लगे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इसे बचाने की कोशिश कर रही है। गांधी ने कहा कि संविधान सिर्फ एक पुस्तक नहीं है, बल्कि यह इस देश में गरीबों को अधिकार देता है, उनकी रक्षा करता है और उनके भविष्य की देखभाल करता है, लेकिन भाजपा चाहती है कि इसे फाड़ कर फेंक दिया जाए।

भोपाल में 64% वोटिंग, लकी ड्रा में इनाम मिले, खिले वोटर्स के चेहरे

लोकसभा संसदीय क्षेत्र भोपाल में मंगलवार को कुल 64 प्रतिशत ही मतदान हो सका है। यह मतदान वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव की अपेक्षा एक प्रतिशत कम रहा। इतना ही नहीं सीहोर सहित सभी आठ विधानसभा क्षेत्रों में भी मतदान कम हुआ है। इनमें नरेला और हुजूर में चार प्रतिशत तक मतदान में कमी आई है। बता दें कि लोकसभा संसदीय क्षेत्र में कुल 23 लाख 39 हजार 406 मतदाता हैं जिनमें से लगभग 15 लाख मतदाताओं ने ही अपने मताधिकार का उपयोग किया है।हालांकि जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी किए गए यह आंकड़े अंतिम नहीं हैं , इनमें भी बदलाव होने की संभावना है।

लोकसभा चुनाव के पिछले दो चरणों में कम मतदान प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने व्यापारियों के सहयोग से जिले के मतदाताओं को बाहर आने और वोट डालने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक पहल की। इसके तहत हर मतदान केंद्र पर लकी ड्रा आयोजित किए गए, जिसमें हर बूथ पर तीन गिफ्ट लकी ड्रा के कूपन के माध्यम से विजेताओं को प्रदान किए गए। ऐसे में 6291 को पुरस्कार दिए गए। लोकसभा चुनाव के दौरान भोपाल की सात विधानसभा क्षेत्र के दो हजार 97 और सीहोर विधानसभा क्षेत्र के 266 केंद्रों पर पुरुषों के साथ -साथ महिला मतदाता भी कम ही मतदान करने पहुंची।इसी वजह से आठों विधानसभा क्षेत्र में कम मतदान हुआ है। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां नरेला विधानसभा क्षेत्र में 64.87 प्रतिशत मतदान हुआ था तो इस बार 60.56 हुआ जो कि 4.31 प्रतिशत कम है। इसी तरह दक्षिण -पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में 2019 में 59.35 प्रतिशत मतदान हुआ था लेकिन इस

भोपाल जिले की सात विधानसभा क्षेत्र हुजूर, नरेला, बैरसिया,मध्य, गोविंदपुरा, दक्षिण-पश्चिम और उत्तर में विधानसभा चुनाव 2023 में 66.66 प्रतिशत मतदान हुआ था। जबकि लोकसभा में इन सातों विधानसभा क्षेत्र में लगभग 62 प्रतिशत यानि दो प्रतिशत कम मतदान हुआ है। लोकसभा में सीहोर क्षेत्र का मतदान मिलाने के बाद आंकड़ा 64 प्रतिशत तक पहुंचा है।

बार 55.07 प्रतिशत ही मतदान हुआ है। जो कि 4.28 प्रतिशत कम रहा है। बैरसिया में तीन, मध्य में तीन, गोविंदपुरा में एक प्रतिशत मतदान कम हुआ है। जबकि उत्तर विधानसभा क्षेत्र में मतदान प्रतिशत लगभग बराबर ही रहा है।

सातों विधानसभा क्षेत्र के दो हजार 97 मतदान केंद्रों पर सुबह छह बजे से मतदाताओं की भीड़ देखी गई थी।मतदान केंद्रों पर ईवीएम में समस्या आने के कारण आधे से एक घंटे देरी से मतदान हुआ । इस वजह से सुबह नौ बजे तक 12 प्रतिशत मतदान हुआ तो फिर 11 बजे तक 27 प्रतिशत मतदान हुआ। इसके बाद एक बजे तक 40, तीन बजे 50 और शाम पांच बजे तक 58 प्रतिशत मतदान हो सका था। इसके बाद देर रात 10 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार कुल 64 प्रतिशत ही मतदान हो सका है।इसस स्पष्ट है कि दोपहर बाद मतदाता केंद्रों तक नहीं पहुंचे।

लोकसभा चुनाव के मतदान होने के बाद संसदीय क्षेत्र भोपाल के भाजपा उम्मीदवार आलोक शर्मा और कांग्रेस उम्मीदवार अरुण श्रीवास्तव सहित कुल 22 उम्मीदवारों का भविष्य कुल दो हजार 363 ईवीएम में बंद हो गया है।इधर सुबह सात बजे से मतदान शुरु होने के बाद लोकसभा क्षेत्र की नरेला, मध्य, हुजूर और बैरसिया के कई मतदान केंद्रों पर धीमा मतदान हुआ। जिसको लेकर कांग्रेस उम्मीदवार अरुण श्रीवास्तव ने जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद इन मतदान केंद्रों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट भेजकर तेजी लाने की कोशिश की गई।

पिछले 2019 में हुआ था 65 प्रतिशत मतदान लोकसभा चुनाव वर्ष 2019 में कुल 65 प्रतिशत मतदान हुआ था। इसी लक्ष्य को पार करने के लिए जिला प्रशासन, निर्वाचन कार्यालय सहित अन्य विभाग के अधिकारी कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित कर मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास कर रहे थे। इसका नतीजा यह रहा कि मतदान प्रतिशत 65 प्रतिशत के आसपास पहुंच गया।जबकि भीषण गर्मी और सुस्त चुनाव प्रचार -प्रसार एवं खामौश मतदाताओं की वजह से इतने प्रतिशत की भी उम्मीद नहीं की जा रही थी।

प्याज पर से बैन हटा

सरकार के फैसले से क्या फिर महंगे हो जाएंगे प्याज के दाम?

प्याज के बिन भारत में बनी कोई भी डिश फीकी ही होती है। प्याज खाने में इस्तेमाल होने वाली चीजों में सबसे जरूरी चीज होती है। इससे किसी भी सब्जी का किसी भी पकवान का स्वाद और बढ़ जाता है। लेकिन पिछला कुछ समय प्याज के बाजार को लेकर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है। भारत सरकार ने पिछले साल 8 दिसंबर को प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। प्याज पर लगे बैन को अब हटा लिया गया है। अब ऐसे में लोगों को ख़दशा यही सता रहा है कि कहीं प्याज के दाम दोबारा से आसमान न छू जाएं। चलिए जानते हैं क्या वाकई बढ़ सकते हैं प्याज के दाम।

किसलिए हटाया गया बैन?

भारत में प्याज की बढ़ती कीमतों को देखकर भारतीय सरकार ने पिछले साल दिसंबर के महीने में 8 तारीख को प्याज के निर्यात पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था। दिसंबर में लगाया बहन मार्च तक के लिए था। लेकिन हालात को देखते हुए इसे आगे थोड़ा और आगे बढ़ा दिया गया था। अब सरकार ने बीते कल यानी 4 मई को प्याज के निर्यात पर लगे बैन को लिफ्ट कर दिया है। भारत में रबी की अच्छी फसल होने के चलते और अच्छे मानसून के अनुमान के चलते खरीफ में अच्छी पैदावार होगी। इस संभावना को देखते हुए सरकार ने निर्यात पर लगे बैन को हटाने का फैसला किया है। सरकार ने निर्यात के लिए न्यूनतम कीमत 550 डॉलर प्रति टन तय यानी लगभग 45,800 रुपये तय की है।

फिर बढ़ जाएंगी कीमतें ?

प्याज पर लगे बैन के हटने के बाद आम जनता फिर इसी सोच में पड़ गई है कि कहीं दोबारा से प्याज के भावों में उछाल न आ जाए। लेकिन अभी फिलहाल इस बात की आशंका नहीं जताई जा रही है। भारत में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की सचिव निधि खरे ने इस बारे में बात करते हुए जानकारी दी है। उन्होंने इस बारे में कहा 'निर्यात होने के बावजूद प्याज की घरेलू कीमतों पर कोई खास असर नहीं होगा। अगर कीमतें बढ़ेंगी भी तो वह खास नहीं बढ़ेंगी। सरकार के विभाग भी पूरी स्थिति पर नजर बना कर रखेंगे। सरकार किसानों के साथ ही उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए भी प्रतिबद्ध है।' इसके साथ ही उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि रबी फसल में प्याज की पैदावार 191 लाख टन होने का अनुमान है। जो देश में खपत होने वाली मात्रा के लिए काफी है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार प्याज के बफर स्टॉक को भी बढ़ा रही है।

भारत से मॉरीशस भेजा जाएगा गैर-बासमती चावल

केंद्र सरकार ने 14,000 मीट्रिक टन एक्सपोर्ट की दी मंजूरी

प्याज के एक्सपोर्ट पर लगे प्रतिबंध को हटाने के बाद सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने मॉसीशस को 14,000 मिट्रीक टन गैर-बासमती सफेद चावल के एक्सपोर्ट की मंजूरी दे दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की ओर से जारी एक अधिसूचना के मुताबिक, भारत ने सोमवार को सफेद चावल के निर्यात पर मुहर लगाई है। डीजीएफटी ने कहा, 'नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से मॉरीशस को 14,000 मीट्रिक टन गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दी गई है।'

जुलाई में लगाया था प्रतिबंध

इससे पहले जुलाई 2023 में केंद्र सरकार ने गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, हालांकि सरकार ने यह भी कहा था कि अन्य देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने और उन देशों के अनुरोध के आधार पर निर्यात की इजाजत दी जाएगी। भारत ने अप्रैल-फरवरी वित्तीय वर्ष 2024 में 790.58 मिलियन डॉलर के गैर-बासमती सफेद चावल का एक्सपोर्ट किया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2023 में यह 2.2 बिलियन डॉलर का था। 2023-24 में भारत ने केन्या, मोजाम्बिक और वियतनाम को सबसे ज्यादा गैर-बासमती सफेद चावल का निर्यात किया था।वहीं, मॉरीशस को 7.48 मिलियन डॉलर का चावल निर्यात किया गया था। बता दें कि देश में हो रहे लोकसभा चुनाव 2024 के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए हाल ही में प्याज के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। इसके अलावा प्याज पर 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाने का भी ऐलान किया है। सरकार की ओर जारी एक नॉटिफिकेशन के मुताबिक, ये बदलाव शनिवार यानी 4 मई से प्रभावी हो गए हैं। सरकार ने प्रतिदिन 550 डॉलर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी)लगाया है। बता दें कि महाराष्ट्र में किसानों के असंतोष बीच सरकार की ओर से अनिश्चित काल के लिए बढ़ाए गए बैन को 43 दिन बाद हटाया गया था।

आर्थिक क्षेत्र में नित नए विश्व रिकार्ड बनाता भारत

आज भारत आर्थिक क्षेत्र में वैश्विक मंच पर नित नए रिकार्ड बना रहा है। वैश्विक स्तर पर विदेशी प्रेषण के मामले में आज भारत प्रेषण प्राप्तकर्ता के रूप में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। भारत में आज सबसे बड़ा सिंक्रोनाईजड बिजली ग्रिड है।

दिनांक 1 मई 2024 को अप्रेल 2024 माह में वस्तु एवं सेवा कर के संग्रहण से सम्बंधित जानकारी जारी की गई है। हम सभी के लिए यह हर्ष का विषय है कि माह अप्रेल 2024 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर का संग्रहण पिछले सारे रिकार्ड तोड़ते हुए 2.10 लाख करोड़ रुपए के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया है, जो निश्चित ही, भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022 में वस्तु एवं सेवा कर का औसत कुल मासिक संग्रहण 1.20 लाख करोड़ रुपए रहा था, जो वित्तीय वर्ष 2023 में बढ़कर 1.50 लाख करोड़ रुपए हो गया एवं वित्तीय वर्ष 2024 में 1.70 लाख करोड़ रुपए के स्तर को पार कर गया। अब तो अप्रेल 2024 में 2.10 लाख करोड़ रुपए के स्तर से भी आगे निकल गया है। इससे यह आभास हो रहा है कि देश के नागरिकों में आर्थिक नियमों के अनुपालन के प्रति रुचि बढ़ी है, देश में अर्थव्यवस्था का तेजी से औपचारीकरण हो रहा है एवं भारत में आर्थिक विकास की दर तेज गति से आगे बढ़ रही है। कुल मिलाकर अब यह कहा जा सकता है कि भारत आगे आने वाले 2/3 वर्षों में 5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। भारत में वर्ष 2014 के पूर्व एक ऐसा समय था जब केंद्रीय नेतृत्व में नीतिगत फैसले लेने में भारी हिचकिचाहट रहती थी और भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की हिचकोले खाने वाली 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल थी। परंतु, केवल 10 वर्ष पश्चात केंद्र में मजबूत नेतृत्व एवं मजबूत लोकतंत्र के चलते आज वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। आज भारत आर्थिक क्षेत्र में वैश्विक मंच पर नित नए रिकार्ड बना रहा है। वैश्विक स्तर पर विदेशी प्रेषण के मामले में आज भारत प्रेषण प्राप्तकर्ता के रूप में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। भारत में आज सबसे बड़ा सिंक्रोनाईजड बिजली ग्रिड है। बैंकिंग क्षेत्र में वास्तविक समय लेनदेन की सबसे बड़ी संख्या आज भारत में ही सम्पन्न हो रही है। भारत आज विश्व में दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है एवं भारत आज पूरे विश्व में मोबाइल फोन का निर्माण करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। भारत में आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेट्वर्क है। मात्रा की दृष्टि से भारत में आज विश्व का तीसरा सबसे बड़ा फार्मासीयूटिकल उद्योग है। भारत में आज पूरे विश्व में तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेट्वर्क है।

भारत ने स्टार्टअप को विकसित करने के उद्देश्य से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र खड़ा कर लिया है। भारत का स्टॉक बाजार, पूंजीकरण के मामले में, विश्व में चौथे स्थान पर आ गया है। भारत में आज विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेट्वर्क है। विश्व में पैटेंट हेतु आवेदन किए जाने वाले देशों में भारत आज छठे स्थान पर आ गया है। आर्थिक क्षेत्र में भारत को यह सभी उपलब्धियां पिछले 10 वर्षों के दौरान प्राप्त हुई हैं।

पिछले केवल 10 वर्षों के दौरान शेयर बाजार में निवेशकों को अपार सफलता हासिल हुई है और सेन्सेक्स ने 200 प्रतिशत की रिकार्ड वृद्धि दर्ज की है, इसी प्रकार निफ्टी भी इसी अवधि में 206 प्रतिशत की रिकार्ड वृद्धि दर्ज करने में सफल रहा है। यह स्थानीय एवं विदेशी निवेशकों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपना विश्वास जता रहा है।

भारत में शेयर बाजार में व्यवहार करने के उद्देश्य से खोले जाने वाले डीमेट खातों की संख्या वर्ष 2014 में 2.2 करोड़ थी जो वर्ष 2024 में बढ़कर 15.13 करोड़ हो गई है अर्थात इन 10 वर्षों में 7 गुणा से अधिक की वृद्धि दर अर्जित की गई है। देश का प्रत्येक उद्यमी/उपक्रमी/व्यवसायी बहुत उत्साह में है कि देश में व्यापार करने हेतु वातावरण में बहुत सुधार हुआ है एवं ईज आफ डूइंग बिजनेस में काफी सुधार हुआ है। आज भारत ही नहीं बल्कि भारतीय कम्पनियों द्वारा विदेश में भी पूंजी उगाहना बहुत आसान हो गया है। अतः एक प्रकार से उद्यमियों के लिए पूंजी की समस्या तो नहीं के बराबर रह गई है। भारतीय नागरिकों में आज स्व का भाव जगाने में भी कामयाबी मिली है, जिसके चलते स्वदेश में निर्मित वस्तुओं का उपयोग बढ़ रहा है एवं अन्य देशों से विभिन्न उत्पादों के आयात कम हो रहे हैं। इसके चलते भारत के विदेशी व्यापार घाटे में सुधार दृष्टिगोचर है।

भारत ने स्टार्टअप को विकसित करने के उद्देश्य से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र खड़ा कर लिया है। भारत का स्टॉक बाजार, पूंजीकरण के मामले में, विश्व में चौथे स्थान पर आ गया है। भारत में आज विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेट्वर्क है।

आज भारत से विभिन्न उत्पादों के निर्यात में मामूली वृद्धि दर्ज हो रही है तो कई उत्पादों के आयात में कमी दिखाई देने लगी है। इसे भारतीय नागरिकों के आत्म निर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम के रूप में देखा जा सकता है। फरवरी 2024 माह में भारत का व्यापारिक निर्यात 11.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 4140 करोड़ अमेरिकी डॉलर का हो गया, जो पिछले 20 महीनों में उच्चतम स्तर पर है। इसके अतिरिक्त, सेवा निर्यात 3210 करोड़ अमेरिकी डॉलर के रिकार्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। फरवरी 2024 माह में माल एवं सेवाओं को मिलाकर कुल निर्यात 7355 करोड़ अमेरिकी डॉलर का रहा है, जो फरवर 2023 की तुलना में 14.2 प्रतिशत अधिक है। इसी कारण से, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी आज 64,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर को पार कर गया है।

आज भारतीय नागरिकों ने सनातन संस्कृति का अनुपालन करते हुए भारत को विकसित एवं मजबूत बनाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा लिए हैं। आज भारत में प्रत्येक नागरिक का औसत जीवन वर्ष 2022 के 62.7 वर्ष से बढ़कर 67.7 वर्ष हो गया है। यह भारत में लगातार हो रही स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के चलते ही सम्भव हो सका है। संयुक्त राष्ट्र के एक प्रतिवेदन के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय में पिछले 12 महीनों के दौरान 6.3 प्रतिशत की वृद्ध दर्ज हुई है। इसी प्रकार, एक सर्वे के अनुसार, आज भारत में 36 प्रतिशत कम्पनियां आगामी 3 माह में नई भर्तियां करने पर गम्भीरता से विचार कर रही हैं, इससे भारत में रोजगार के लाखों नए अवसर निर्मित होते दिखाई दे रहे हैं। गरीब वर्ग को भी केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाये जाने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। जल जीवन मिशन ने पूरे भारत में 75 प्रतिशत से अधिक घरों में नल के पानी का कनेक्शन प्रदान करके एक बढ़ा मील का पत्थर हासिल कर लिया है। लगभग 4 वर्षों के भीतर मिशन ने 2019 में ग्रामीण नल कनेक्शन कवरेज को 3.23 करोड़ घरों से बढ़ाकर 14.50 करोड़ से अधिक घरों तक पहुंचा दिया गया है। इसी प्रकार, पीएम आवास योजना के अंतर्गत, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 4 करोड़ से अधिक पक्के मकान बनाए गए हैं एवं सौभाग्य योजना के अंतर्गत देश भर में 2.8 करोड़ घरों का विद्युतीकरण कर लिया गया है। विश्व भर के सबसे बड़े सरकारी वित्तपोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना- के अंतर्गत 55 करोड़ लाभार्थियों को माध्यमिक एवं तृतीयक देखभाल एवं अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जा रहा है। साथ ही, पीएम गरीब कल्याण योजना के माध्यम से मुफ्त अनाज के मासिक वितरण से 80 करोड़ से अधिक परिवारों को लाभ प्राप्त हो रहा है। पीएम उज्जवल योजना के अंतर्गत 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किये गए हैं। इन महिलाओं के जीवन में इससे क्रांतिकारी परिवर्तन आया है क्योंकि ये महिलाएं इसके पूर्व लकड़ी जलाकर अपने घरों में भोजन सामग्री का निर्माण कर पाती थीं और अपनी आंखों को खराब होते हुए देखती थीं।

पलामू में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का बड़ा हमला

पाकिस्तानी नेता कांग्रेस के शहजादे को पीएम बनाने की दुआ कर रहे हैं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए झारखंड दौरे पर हैं और पलामू में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में एक समय ऐसी स्थिति थी, जब आतंकी हमले के बाद कांग्रेस की डरपोक सरकार दुनियाभर में जा जाकर रोती थी, लेकिन आज वो वक्त चला गया है। आज हालात ये है कि पाकिस्तान दुनिया में जा जाकर रो रहा है। आज पाकिस्तान के नेता भी ये दुआ कर रहे हैं कि कांग्रेस के शहजादे किसी तरह प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन मजबूत भारत तो अब मजबूत सरकार ही चाहता है। पलामू में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर और अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आपके एक वोट की ताकत से जम्मू कश्मीर में धारा 370 की दीवार को हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि आप सभी अपने एक वोट की ताकत को अच्छी तरह से जानते हैं। आपने 2014 में अपने एक वोट से कांग्रेस की महा भ्रष्ट सरकार को सत्ता से हटा दिया था।

भाई राहुल को 'शहजादा' कहने पर भड़कीं प्रियंका, PM मोदी को बताया शहंशाह, कहा- आप महल में रहते हैंभाई राहुल को 'शहजादा' कहने पर भड़कीं प्रियंका, PM मोदी को बताया शहंशाह, कहा- आप महल में रहते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 500 साल से हमारी कितनी ही पीढ़ियां राम मंदिर के लिए संघर्ष करती रहीं। लाखों लोग इसके लिए शहीद हो गए। दुनिया में शायद ही इतना लंबा अविरत संघर्ष कहीं नहीं हुआ होगा, जो अयोध्या में हुआ। लेकिन आपके एक वोट की ताकत देखिए, 500 साल तक जो काम नहीं हुआ, वो आपके एक वोट से हो गया। आज आज राम मंदिर बन गया।

पलामू में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं गरीबी का जीवन जीकर आया हूं। गरीब की जिंदगी कितनी तकलीफ वाली होती है, मैं उससे अच्छी तरह जानता हूं। बीते 10 सालों में गरीब कल्याण की हर योजना की प्रेरणाओं ने मेरे अपने जीवन के अनुभव से जन्म लिया है। जिसने अपना पेट बांधकर मां को सोते नहीं देखा, जिसने लोटा भर पानी पीकर मां को भूख मिटाते नहीं देखा, जिसने अपनी बीमारी को छिपाते नहीं देखा, वे लोग मोदी के इन आंसुओं का मर्म और दर्द नहीं समझ सकते हैं। कांग्रेस के शहजादे मोदी के आंसुओं में अपनी खुशी खोज रहे हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस वालों की नजर आपकी जमीन-जायदाद पर है। कांग्रेस हो या JMM हो, दोनों को कुछ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस कह रही है कि आपकी संपत्ति का एक्स-रे करेंगे। कितनी जमीन है, घर कहां है, कितने कमरे हैं, घर में सोना है कि नहीं है, चांदी है कि नहीं है, मंगलसूत्र है कि नहीं। हर चीज की जांच कराने की बात कह रही है। फिर उसमें से कुछ हिस्सा आपसे छीन लेंगे। आपसे वो लेकर अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं।

भगवान महाकाल के शिखर दर्शन चारों दिशाओं से बगैर बाधा के हो सकेंगे

उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर शिखर दर्शन के महत्व को देखते हुए महाकाल मंदिर शिखर दर्शन योजना के तहत मंदिर के चारों ओर निर्माण धीरे-धीरे हटाया जा रहा है। अब मंदिर के शिखर दर्शन बगैर बांधा के स्पष्ट किए जा सकेंगे। उज्जैन के हजारों नागरिक प्रतिदिन महाकाल मंदिर के शिखर दर्शन करते हैं। लेकिन दर्शन करने के लिए उन्हें महाकाल मंदिर के पूर्व मुख्य द्वार के मेन चौराहे पर आना पड़ता था एवं उन्हें शिखर दर्शन मिलते थे। महाकाल मंदिर के फेज-2 के तहत चल रहे सौंदर्यीकरण कार्य में महाकाल मंदिर शिखर दर्शन योजना भी शामिल है। इसी के तहत मंदिर के चारों ओर निर्माणों को हटाया गया है। उज्जैन सहित देशभर से महाकाल दर्शन को आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को अब रुद्रसागर की तरफ से भी ज्योतिर्लिंग महाकाल के शिखर दर्शन स्पष्ट रूप से हो सकेंगे। मंदिर प्रबंध समिति ने परिसर में स्थित देवास धर्मशाला को पूरी तरह से हटा दिया है।

धर्मशाला बीच में आने से शिखर दर्शन में बांधा आ रही थी। लेकिन अब इसके हटने के बाद बीच में कोई भवन सामने नहीं रहेगा। पूर्व में कोटितीर्थ कुंड के पास बनी प्राचीन धर्मशाला के पुराने भवन को अब मंदिर प्रबंध समिति ने हटाया है। इसके कुछ हिस्से को पहले हटाने की कार्रवाई की गई थी। महाकाल मंदिर विस्तार योजना के तहत 16.10 करोड़ रुपये में रुद्रसागर शिखर दर्शन परियोजना बनाई गई है, जिसके चलते ही धर्मशाला हटाकर अब शिखर दर्शन की सीधे व्यवस्था कर दी गई है।

महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल ने बताया कि शिखर दर्शन आसान हो सकें, इसके लिए पुराने भवन व धर्मशाला आदि को हटाया गया है। उनके स्थान पर अब भविष्य में कोई भी नया निर्माण नहीं किया जाएगा। ऐसे में पर्व, त्योहार, नव वर्ष के दौरान लाखों की संख्या में उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं को रुद्रसागर सहित चारों दिशाओं से भी आसानी से शिखर दर्शन करने का लाभ मिलेगा। महाकाल मंदिर पुजारियों के अनुसार कहा गया है कि शिखर दर्शनम् पाप नाशनम् महाकाल मंदिर के शिखर के दर्शन करने भर से सभी पापों का नाश हो जाता है।

ऐसा मानकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन उज्जैन में महाकाल के शिखर दर्शन ही करने आते हैं। अब मंदिर की चारों दिशाओं से महाकाल के शिखर दर्शन किए जा सकेंगे। शिखर दर्शन की पूरी योजना इस तरह है। इस कार्य की लागत 16.10 करोड़ रुपये है। निर्माण आदि का क्षेत्रफल 52,000 वर्ग फीट यह रहेगा। अब तक परिसर में कोटितीर्थ कुंड के पास प्रवचन हॉल और धर्मशाला की जगह पर शिखर दर्शन योजना के तहत नवनिर्माण किया है। हरसिद्धि, बड़ा गणेश मंदिर की ओर से आने वाले श्रद्धालु दूर से ही शिखर दर्शन का लाभ ले सकेंगे। शिखर दर्शन के लिए एक प्लेटफार्म भी बनाया गया है, जहां पर कोटितीर्थ कुंड के पास रेलिंग लगाई है। वहां तक दर्शनार्थी आकर शिखर दर्शन कर सकते हैं।

माथे के साथ गले पर भी लगाएं हल्दी का तिलक...

हल्दी सदियों से भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। वैसे तो आमतौर पर इसका इस्तेमाल रसोई घर में खाना पकाते समय होता है मगर पूजा-पाठ के लिए भी हल्दी को शुभ माना जाता है। हल्दी अपने कई औषधीय गुणों के लिए भी जाना जाता है, यही कारण है कि बहुत सी बीमारियों में भी हल्दी के सेवन का सुझाव दिया जाता है। खैर, हल्दी का तिलक लगाना हिंदू धर्म में एक आम प्रथा है। आमतौर पर इसे माथे पर लगाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माथे के अलावा भी शरीर के किसी और अंग पर हल्दी तिलक लगाना शुभ माना जाता है? जी हां, अक्सर लोग सिर्फ माथे पर ही तिलक लगाते हैं मगर बहुत कम लोगों को मालूम है कि गले पर भी तिलक लगाया जा सकता है। इसलिए आइए आज के इस लेख में जानते हैं कि माथे के साथ गले पर तिलक लगाने के क्या-क्या फायदे होते हैं-

माना जाता है कि हल्दी में सकारात्मक ऊर्जा स्रोत होता है। गले पर हल्दी का तिलक लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और मन शांत रहता है। साथ ही भगवान विष्णु का नाम लेकर हल्दी का तिलक लगाने से पाप मिटते हैं। प्रतिदिन गले पर हल्दी का तिलक लगाने से आत्मविश्वास बढ़ता है। यह आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है।

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गले पर हल्दी का तिलक लगाने से ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव कम होता है। यह स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त करने में मदद करता है। हल्दी का तिलक माथे पर और गले पर लगाने से आपका आभा मंडल आलोकित होता है। इतना ही नहीं, मुख मंडल पर तेज बढ़ता है और चेहरा कांतिवान होता है। श्रीहरि के नाम लेकर माथे पर या गले पर हल्दी का तिलक लगाने से आपके दोष दूर होते हैं। साथ ही भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आपके बिगड़े कार्य बनने लगते हैं।

क्या है हल्दी का तिलक लगाने का सही तरीका?

सबसे पहले, हल्दी और पानी का गाढ़ा पेस्ट बना लें। अपनी उंगली या तिलक लगाने वाली कलम से गले के बीच में एक छोटा सा तिलक लगाएं। तिलक को सूखने दें। आप रोजाना सुबह स्नान करने के बाद गले पर हल्दी का तिलक लगा सकते हैं। वैसे तो रोज हल्दी का तिलक लगाना शुभ माना जाता है मगर गुरुवार के दिन सुबह में नित्य कर्मों से मुक्त होकर माथे पर तिलक लगाना अत्यंत फलदायी माना जाता है। माथे के साथ गले पर हल्दी का तिलक लगाने से न केवल आध्यात्मिक बल्कि स्वास्थ्य और सौंदर्य संबंधी भी कई लाभ मिलते हैं।

क्रिकेट की नई क्रांति का उदय

ग्वालियर में नवनिर्मित शंकरपुर स्टेडियम में सिंधिया कप से फटाफट क्रिकेट की नई क्रांति का आगाज होने जा रहा है... आईपीएल की तर्ज पर होने वाली मध्यप्रदेश लीग (एमपीएल) में क्रिकेट का रोमांच देखने को मिलेगा। जिसके साक्षी बनेंगे भारत को पहली बार वर्ल्ड कप जिताने वाले महान क्रिकेटर कपिल देव और देश की जानी-मानी हस्तियां।

15 जून का दिन ग्वालियर के खेल प्रेमियों और क्रिकेट जगत के लिए सौगातों भरा साबित होगा। जब जगमगाती रोशनी में देश की जानी-मानी हस्तियों की मौजूदगी में फटाफट क्रिकेट का रोमांच देखने को मिलेगा। ग्वालियर के शंकरपुर क्षेत्र में शनिवार को एक नई क्रांति का उदय जो हो रहा है। इस क्षेत्र को अब एक नई पहचान मिलने जा रही है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एमपीसीए) ने यहां एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के अत्याधुनिक क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया है। स्टेडियम खेल प्रेमियों के स्वागत को तैयार है। यह स्टेडियम न केवल ग्वालियर और आसपास के क्षेत्र के खेल प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल बनेगा, बल्कि अंचल के युवाओं को अपने खेल-कौशल को निखारने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करेगा।

इंदौर के होल्कर स्टेडियम के बाद यह प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। पर्यावरण की दृष्टि से स्टेडियम का निर्माण महत्वपूर्ण है। क्योंकि पर्यावरण संरक्षण का विशेष ध्यान रखा गया है। आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर स्टेडियम को ऊर्जा-सक्षम बनाया गया है। इसके अलावा, परिसर में हरियाली और पर्यावरण मित्र तत्वों को भी शामिल किया गया है। हरे-भरे पहाड़ों की खूबसूरती के बीच यह प्रकृति के करीब होने का अहसास भी कराएगा।

करीब 200 करोड़ की लागत से 30 एकड़ में बने स्टेडियम में 50 हजार दर्शक मैच देख सकेंगे। इसमें 14.4 मीटर ऊंचाई का पवैलियन बनाया गया है। एलईडी वाली नई तकनीक की 6 फ्लड लाइट स्टेडियम में चार चांद लगाएंगी। जो खिलाड़ियों और दर्शकों को उच्चस्तरीय अनुभव कराएंगी।

स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय मानकों के मुताबिक स्वीमिंगपुल, सोना बाथ के साथ अत्याधुनिक जिम और ड्रेसिंग रूम भी तैयार किए गए हैं। प्रवेश के लिए 8 गेट हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए 30 बॉक्स का निर्माण किया गया है। मीडिया के लिए भी बेहतर इंतजाम हैं। इस क्रिकेट स्टेडियम की विशेषताएं इसे अनोखा और महत्वपूर्ण बनाती हैं। जिससे यह मध्य प्रदेश के प्रमुख स्टेडियमों में से एक बन जाएगा। उच्च स्तरीय आधुनिक स्टेडियम का निर्माण न केवल खेल के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल प्रदान करेगा। स्थानीय लोगों को रोजगार के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही होटल, रेस्टोरेंट व्यवसाय सहित परिवहन सेवा में भी वृद्धि होने की संभावना है। स्टेडियम से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे क्षेत्र का समग्र विकास संभव हो सकेगा।

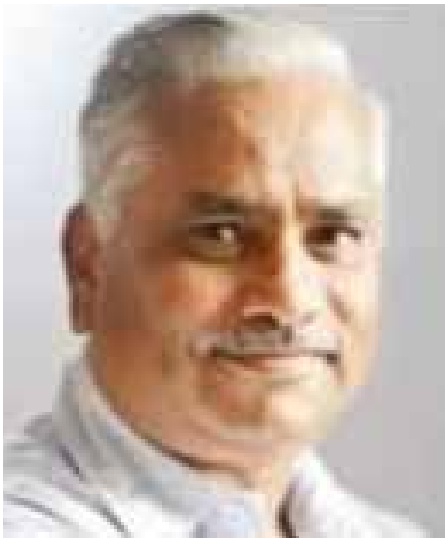

डॉ. केशव पाण्डेय

स्टेडियम क्षेत्र के युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर साबित होगा। यह उन्हें खेल की दुनिया में अपनी पहचान बनाने का मंच प्रदान करेगा। स्थानीय क्रिकेट क्लबों और स्कूलों के लिए यह एक उत्कृष्ट स्थल होगा जहां वे अपने खेल कौशल को निखार सकेंगे और उच्चस्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग ले सकेंगे। स्टेडियम में नियमित रूप से कोचिंग कैंप और प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया जाएगा, ताकि उभरते हुए खिलाड़ियों को उच्चस्तरीय मार्गदर्शन प्राप्त हो सके।

इसी उद्देश्य से ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष महाआर्यमन सिंधिया ने सार्थक पहल की है। जिसके तहत 15 से 23 जून तक मध्य प्रदेश लीग (एमपीएल) का आयोजन किया जा रहा है।

एमपीएल में पांच टीमें भाग लेंगी। जिसमें ग्वालियर चीताज, मालवा पैंथर्स, जबलपुर लायंस, भोपाल लैपड्र्स और रीवा जैगुआर्स शामिल हैं। उद्घाटन मैच ग्वालियर चीताज और मालवा पैंथर्स के बीच होगा। जीयो सिनेमा और स्पोर्ट्स टीवी पर इसका लाइव प्रसारण देखने को मिलेगा। 23 जून को फाइनल होगा। मैच देखने के लिए आम दर्शकों को स्टेडियम में निःशुल्क प्रवेश मिलेगा।

एमपीएल के आगाज के साथ खेल गतिविधियों का श्रीगणेश होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव जय शाह, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश सरकार के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर व महाआर्यमन सिंधिया की मौजूदगी में एमपीएल का शुभारंभ किया जाएगा।

एमपीएल के आगाज और स्टेडियम के निर्माण से खेल संस्कृति का विकास होगा। यहां विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मैचों के आयोजन किये जा सकेंगे। जिससे स्थानीय निवासियों को उच्चस्तरीय खेल देखने का मौका मिलेगा। इससे खेल के प्रति उनकी रुचि और जागरूकता में वृद्धि होगी। साथ ही, स्थानीय युवाओं को बड़े खिलाड़ियों से मिलने और उनसे प्रेरणा लेने का भी अवसर मिलेगा।

आपको बता दें कि स्टेडियम का निर्माण कैलाशवासी माधवराव सिंधिया के ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा था। जिसे उनके पुत्र केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साकार किया है। ज्योतिरादित्य के पुत्र महाआर्यमन एमपीएल कराकर युवाओं को फटाफट क्रिकेट की सौगात देने जा रहे हैं। इस स्टेडियम के निर्माण के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो प्रतिबद्धता दिखाई है और विभिन्न स्तरों पर सहयोग प्रदान किया है वह तारीफे काबिल है। उनका खेल प्रेम और स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देने का उद्देश्य इस स्टेडियम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाएगा।

स्टेडियम के निर्माण से जहां खेल-प्रेमी खुश हैं वहीं स्थानीय समुदाय ने निर्माण का स्वागत करते हुए इसे क्षेत्र के समग्र विकास का प्रतीक बताया है। उनका मानना है कि इससे आस-पास के इलाकों का तेजी से विकास होगा और युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। स्थानीय खेल संगठनों और क्लबों ने भी इस पहल की सराहना की है और इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। भविष्य में स्टेडियम परिसर में एक स्पोर्ट्स अकेडमी और प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया जाएगा, जहां विभिन्न खेलों के लिए उच्चस्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। कहा जा सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की यह सार्थक पहल खेल के साथ ही क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी इससे न केवल खेल प्रेमियों को एक उत्कृष्ट स्थल प्राप्त होगा, बल्कि यह स्थानीय अर्थव्यवस्था और युवाओं के लिए भी नए अवसर प्रदान करेगा। ग्वालियर को खेलों के नक्शे पर एक नई पहचान दिलाएगा। इस स्टेडियम के माध्यम से शंकरपुर न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में खेलों के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरेगा।

नींबू पानी पीते हैं तो ध्यान दें

कहीं फायदे की जगह नुकसान तो नहीं हो रहा आपके शरीर को...

गर्मियों में नींबू पानी को काफी पसंद किया जाता रहा है। ये पेय न सिर्फ शरीर को निर्जलीकरण से बचाती है साथ ही नींबू पानी पीने से सेहत को भी कई लाभ मिलते हैं। तेज गर्मी में शरीर को तरोताजा करने, नींबू में विटामिन-सी की मौजूदगी के कारण इम्युनिटी मजबूत होने सहित इसके कई लाभ हैं। पर इस तरह के फायदों के लिए कहीं आप बहुत अधिक मात्रा में तो इसका सेवन नहीं कर रहे हैं?

अध्ययनों में नींबू पानी पीने से होने वाले तमाम प्रकार के स्वास्थ्य लाभ के बारे में बताया गया है, जिनमें हाइड्रेशन को बढ़ावा देना, वजन घटाने में सहायता करना और विटामिन-सी की पूर्ति करना प्रमुख है। पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, इसका सेवन आपको संयमित मात्रा में ही करना चाहिए।

बहुत अधिक मात्रा में नींबू पानी पीने या गलत तरीके से इसका सेवन करने से दांतों से लेकर संपूर्ण स्वास्थ्य को कई प्रकार से नुकसान हो सकता है। आइए नींबू पानी पीने से होने वाले फायदों और नुकसान के बारे में जानते हैं।

नींबू को कई प्रकार के पोषक तत्वों से भरपूर माना जाता है, मुख्यरूप से ये विटामिन-सी का सबसे अच्छा स्रोत है। इसे हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है साथ ही कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि खाली पेट गुनगुने पानी में नींबू और शहद मिलाकर इसका सेवन करने से वजन को कंट्रोल रखने में मदद मिल सकती है। नींबू पानी किडनी स्टोन से बचाने, एनीमिया के खतरे को कम करने और पाचन स्वास्थ्य में सुधार करने में भी आपके लिए मददगार है। इन फायदों के इतर नींबू पानी पीने के कई दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं जिसके बारे में जानना जरूरी है।

दांतो के लिए ये बहुत नुकसानदायक

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बताया नींबू के रस में लगभग 5-6% साइट्रिक एसिड होता है। इसके अधिक सेवन से नींबू पानी में मौजूद एसिड के संपर्क में आने से दांतों के इनेमल को काफी नुकसान हो सकता है। यहां तक कि नींबू पानी की अधिकता दांतों की कठोर बाहरी परत से लेकर डेंटिन तक को क्षति पहुंचा सकती है। डेंटिन इनेमल के नीचे की परत है जो तंत्रिकाओं की रक्षा करती है और दांत की मुख्य सहायक संरचना है।

सावधानी रखें

- नींबू पानी से होने वाले दुष्प्रभावों से बचाव के लिए कुछ प्रकार के उपायों से लाभ पाया जा सकता है।
- नींबू के रस को ठंडे पानी में आधा-आधा अनुपात में मिलाएं। ठंडा पानी नींबू की घुलनशीलता को कम कर देता है जिससे यह इनेमल को कम नुकसान पहुंचाता है।
- नींबू पानी पीने के लिए स्ट्रॉ का उपयोग करें और इससे दांतों से इसका सीधा संपर्क नहीं होता है।
- नींबू पानी के एसिड लार में मिलकर भी दांतों को क्षति पहुंचा सकते हैं। इससे बचावे के लिए नींबू पानी पीने के बाद अच्छे से कुल्ला जरूर करें।
- साइट्रिक एसिड के क्षयकारी प्रभाव को कम करने के लिए नींबू पानी पीने के लगभग एक घंटे बाद अपने दांतों को अच्छे से साफ करें।

गर्मी से कोई हो जाए बेहोश तो बिल्कुल न करें ये गलती...

देश के अधिकतर राज्य इन दिनों भीषण गर्मी-लू की चपेट में हैं। बढ़ते तापमान को स्वास्थ्य विशेषज्ञ सेहत के लिए काफी हानिकारक मानते हैं। गर्मी-लू के कारण ब्लड प्रेशर लो होने के साथ, हृदय गति में परिवर्तन, बेहोशी-चक्कर आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

गर्मी और तेज धूप की चपेट में आने के कारण आपने भी कई लोगों में बेहोशी और चक्कर आने जैसे मामलों के बारे में जरूर सुना और देखा होगा। अक्सर ऐसे लोगों को समय पर सही उपचार नहीं मिल पाता है जिसके कारण सेहत के और खराब होने का खतरा हो सकता है। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए हीटवेव से निपटने के लिए जरूरी दिशानिर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा यदि आपको या किसी को धूप लगने के कारण चक्कर आ रहा है तो उन्हें कुछ प्राथमिक चिकित्सा दी जानी चाहिए, जिससे लक्षणों को बिगड़ने से बचाया जा सके। हालांकि बेहोशी की स्थिति में कुछ चीजें करने से सेहत को नुकसान भी हो सकता है। आइए इस बारे में जानते हैं।

चक्कर आने पर क्या करें?

स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक्स पर किए एक पोस्ट में बताया गर्मी के कारण बेहोशी-चक्कर आने जैसी दिक्कत महसूस हो रही है तो सबसे पहले शरीर को निर्जलीकरण की समस्या से बचाने के लिए पानी पिलाएं। संभव हो तो कपड़े उतार दें और तुरंत ठंडे स्थान पर जाएं। बेहोशी-चक्कर आने के अधिकतर मामले शरीर के डिहाइड्रेट होने और शरीर का तापमान सामान्य से अधिक हो जाने के कारण होते हैं। ऐसे में इन उपायों से काफी हद तक आराम मिल सकता है।

बेहोश व्यक्ति को न पिलाएं पानी

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, ध्यान रहे बेहोश व्यक्ति कुछ भी निगलने में असमर्थ होता है, ऐसे में उसे जबरदस्ती कुछ भी खिलाने-पिलाने से बचना चाहिए। बेहोशी की स्थिति में भोजन या तरल पदार्थ पेट के बजाय फेफड़ों तक पहुंच सकते हैं, जिससे श्वसन संबंधी परेशानी बढ़ने का खतरा रहता है। बेहोश व्यक्ति के हृदय गति और ब्लड प्रेशर की जांच करें, अगर ये बहुत बढ़ा हुआ या कम लग रहा है तो तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए।

वायुमार्ग-सांस न होने पाए बाधित

बेहोश व्यक्ति के वायुमार्ग में कोई समस्या न आए और वो सही तरीके से सांस लेता रहे इसके लिए ठुड्डी को ऊपर उठाकर और सिर को एक तरफ थोड़ा झुका दें। सुनिश्चित करें कि बेहोश व्यक्ति अच्छी तरह से सांस ले रहा हो। यदि उसे सांस लेने में कोई दिक्कत है तो आवश्यकतानुसार सीपीआर दी जा सकती है। सामान्य उपचारों की मदद से भी यदि लक्षणों में कोई आराम नहीं मिल रहा है और व्यक्ति होश में नहीं आ रहा है तो बिना देर किए उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाएं।

गर्मियों में चक्कर आने बेहोशी से कैसे बचें

- डॉक्टर द्वारा दिए गए कुछ सुझावों का पालन करके गर्मियों में चक्कर आने-बेहोशी से बचा जा सकता है।
- पर्याप्त मात्रा में पानी पीना सुनिश्चित करें। पानी से भरपूर फलों-सब्जियों का भी सेवन जरूर करें।
- अत्यधिक चाय या कॉफी पीने से बचें। इनसे निर्जलीकरण का खतरा हो सकता है।
- ओआरएस (ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन) लेते रहें। शरीर के तरल पदार्थों को जल्दी से पूरा करने में इससे मदद मिल सकती है।
- गर्मियों में नारियल पानी और नींबू पानी जैसे पेय का सेवन जरूर करते रहें।
- जितना संभव हो सके सूरज के संपर्क में आने से बचें, खासकर दोपहर के दौरान।
- सूती, ढीले-ढाले और हल्के कपड़े पहनें।

सागर की गोद में है ये शिव मंदिर, दिन में दो बार होता है गायब

गुजरात में शिवजी का एक ऐसा मंदिर है जिसका अभिषेक खुद समुद्र देवता करते हैं। यह मंदिर वडोदरा से 85 किमी दूर स्थित जंबूसर तहसील के कावी-कंबोई गांव में है। स्तंभेश्वर नाम का यह मंदिर दिन में दो बार सुबह और शाम को कुछ देर के लिए जलमग्न हो जाता है और कुछ देर बाद दिखाई देने लग जाता है। ऐसा ज्वार भाटा उठने के कारण होता है। इसके चलते आप मंदिर के शिवलिंग के दर्शन तभी कर सकते हैं,जब समुद्र में ज्वार कम हो। ज्वार के समय शिवलिंग पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है और मंदिर तक कोई नहीं पहुंच सकता। यह प्रक्रिया सदियों से चली आ रही है। मंदिर अरब सागर के कैम्बे तट पर स्थित है। इस मंदिर की खोज लगभग 150 साल पहले हुई। मंदिर में स्थित शिवलिंग का आकार 4 फुट ऊंचा और दो फुट के व्यास वाला है। इस प्राचीन मंदिर के पीछे अरब सागर का सुंदर नजारा दिखाई पड़ता है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खासतौर से पर्चे बांटे जाते हैं जिसमें ज्वार-भाटा आने का समय लिखा होता है ताकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना न करना पड़े।

ये है पौराणिक कथा

शिवपुराण के अनुसार,ताड़कासुर नाम के असुर ने भगवान शिव को अपनी तपस्या से प्रसन्न कर दिया था।जब शिव उसके सामने प्रकट हुए तो उसने वरदान मांगा कि उसे छह दिन की आयु का सिर्फ शिवजी का पुत्र ही मार सकेगा। शिव ने उसे यह वरदान दे दिया था। वरदान मिलते ही ताड़कासुर ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। देवताओं और ऋषि-मुनियों को आतंकित कर दिया। देवताओं और ऋषि मुनियों ने शिव जी से उसका वध करने की प्रार्थना की। शिव-शक्ति से श्वेत पर्वत के कुंड में उत्पन्न हुए शिव पुत्र कार्तिकेय के 6 मस्तिष्क, चार आंख, बारह हाथ थे। कार्तिकेय ने ही मात्र 6 दिन की आयु में ताड़कासुर का वध किया था। जब कार्तिकेय को पता चला कि ताड़कासुर भगवान शंकर का भक्त था, तो वे काफी व्यथित हुए। फिर भगवान विष्णु ने कार्तिकेय से कहा कि वे वधस्थल पर शिवालय बनवा दें, इससे उनका मन शांत होगा। कार्तिकेय ने ऐसा ही किया। सभी देवताओं ने मिलकर महिसागर संगम तीर्थ पर विश्वनंदक स्तंभ की स्थापना की, जिसे आज स्तंभेश्वर तीर्थ के नाम से जाना जाता है।मान्यता है कि स्तंभेश्वर महादेव मंदिर में स्वयं शिवशंभु (भगवान शंकर) विराजते हैं इसलिए समुद्र देवता स्वयं उनका जलाभिषेक करते हैं। यहां पर महिसागर नदी का सागर से संगम होता है।

बेहद कठिन है यह तीर्थ यात्रा, यहां सागर से होता है गंगा का मिलन

युगों की तपस्या के बाद मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ। धरती पर फैले अकाल, कष्टों और पाप को मिटाने के लिए मां गंगा धरती पर लायी गईं थीं। भगवान शंकर की जटाओं से निकल कर इनके पवित्र जल ने धरती को पावन कर दिया। हिमालय पर्वत की चोटी गंगोत्री से भागीरथी का उद्गम हुआ है। अलकनंदा से देवप्रयाग में मिलने के बाद ये मां गंगा के रूप में दर्शन देती हैं। इनकी महिमा का वर्णन पुराणों शास्त्रों में दिया गया है। बड़ी ही सुंदरता से इनके संपूर्ण स्वरुप को शब्दों में पिरोकर चित्रित किया गया है। यहां हम आपको एक ऐसी ही कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जो मां गंगा के अवतरण से जुड़ी हुई है।

भूलवश किया था अपमान

धर्मिक ग्रंथों और शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि भूलवश राजा सगर के 60 हजार पुत्रों ने कपिल मुनि का अपमान कर दिया था। जिससे कुपित होकर उन्होंने सभी राजकुमारों को श्राप दे दिया और वे जलकर भस्म हो गए। जब राजा सगर को ये पता चला तो उन्होंने क्षमा याचना की और उनकी मुक्ति का मार्ग पूछा, इस पर कपिल मुनि ने कहा कि श्राप का विफल होना तो संभव नहीं है, किंतु यदि स्वर्ग से पुण्यसलिला मां गंगा को धरती पर ले आया जाए तो उनके जल से ही इनका उद्धार हो सकता है। इस पर उन्होंने मां गंगा को लाने के लिए कठिन तप किया, किंतु सफल नहीं हुए। इसके पश्चात भागीरथ ने मां गंगा को लाने का प्रण लिया और घोर तप किया। इससे मां गंगा प्रसन्न हुईं और इसी वजह से भी उन्हें भागीरथी कहा जाता है।

कपिल मुनि का आश्रम

इसी स्थान पर गंगा सागर से मिलीं। जिसकी वजह से इस स्थान का नाम ही गंगासागर पड़ गया। गंगा का जल पड़ते ही राजकुमारों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। यहां समीप ही कपिल मुनि का आश्रम भी बना हुआ है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि गंगासागर के जल में एक बार डुबकी लगाने का पुण्य अश्वमेध यज्ञ के समान है।

कठिन है यहां की यात्रा

हालांकि यहां की यात्रा करना अत्यंत ही कठिन है। आमतौर पर यहां का मौसम बिगड़ जाता है जिसकी वजह से यहां आपदा प्रबंधन के इंतजाम भी किए जाते हैं। समीप ही सुंदरवन भी है जो जिसका 51 प्रतिशत हिस्सा बांग्लादेश में है। साल में एक बार जनवरी माह में यहां समीप ही मेला भी भरा जाता है अस्थायी टैंट आदि लगाए जाते हैं जो कि प्रायः खराब मौसम की वजह से उड़ जाते हैं। इसी वजह से भी इस यात्रा को बेहद ही कठिन बताया गया है। इस तीर्थ स्थल के बारे में कहा जाता है- बाकी तीरथ चार बार, गंगा सागर एक बार।

इस शुभ पहर में करनी चाहिए हनुमान जी की पूजा, मिलेगी सभी कष्टों से मुक्ति...

माना जाता है कि एक निश्चित समय में भगवान की पूजा करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पूजा के दौरान सही समय का पालन करने से घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है। वहीं हनुमान जी की पूजा का भी एक निश्चित समय निर्धारित किया गया है।

सनातन धर्म में देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना का विशेष महत्व माना गया है। वहीं पूजा-पाठ के कई नियम भी बनाए गए हैं। इन नियमों का पालन करने से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि आती है। वहीं माना जाता है कि एक निश्चित समय में भगवान की पूजा करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पूजा के दौरान सही समय का पालन करने से घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है। वहीं हनुमान जी की पूजा का भी एक निश्चित समय निर्धारित किया गया है। इस दौरान की गई पूजा को हनुमान जी स्वीकार करते हैं। तो आइए जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा का शुभ समय क्या होता है।

हनुमान जी की पूजा का महत्व

पौराणिक कथाओं के मुताबिक केसरी और अंजना भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव जैसा पुत्र पाने के लिए वायु के देवता पवन देव की पूजा-उपासना की थी। पवन देव के आशीर्वाद से अंजना के गर्भ में भगवान शिव का अंश आया और उन्होंने भगवान शिव के जैसे समान शक्तिशाली पुत्र को जन्म दिया। बता दें कि हनुमान जी की पूजा-अर्चना भगवान शि के अवतार के रूप में की जाती है। हनुमान जी में पवन देव की शक्तियां समाहित हैं। इसलिए हनुमान जी को पवनसुत भी कहा जाता है। हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी का विधि-विधान से पूजा-अर्चना करनी चाहिए। इस साल 23 अप्रैल 2024 को हनुमान जंयती का पर्व मनाया गया। सही समय पर हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व होता है और यह फलदायी होती है।

पूजा का सही समय

ज्योतिष और पौराणिक कथाओं के मुताबिक शाम के समय हनुमान जी की पूजा करना सबसे ज्यादा फलदायी होता है। संध्याकाल के समय हनुमान जी की पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ज्योतिष के मुताबिक रात बजे के बाद हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ घी का दीपक जलाकर करना चाहिए। हनुमान जयंती के दिन इस समय पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। दिन में हनुमान जी की पूजा इसी समय करनी चाहिए। जिससे आपको हनुमान जी के आशीर्वाद के साथ मानसिक शांति भी मिले। वहीं कुंडली में यदि ग्रह अनुकूल नहीं है, तो इस दौरान पूजा करने से ग्रह मजबूत होते हैं।

शाम के समय की पूजा

रामायण के मुताबिक राम और रावण के बीच युद्ध के बाद विभीषण जी को हनुमान जी से गहरा लगाव व स्नेह हो गया था। वहीं रावण की मृत्यु के बाद विभीषण ने हनुमान जी से लंका में रुकने का अनुरोध किया। लेकिन भगवान राम का अनुयायी होने की वजह से हनुमान जी ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। लेकिन विभीषण के बहुत अनुरोध करने पर हनुमान जी ने रोजाना दिन के समय लंका जाने और शाम को वापस अयोध्या लौटने का वादा किया। बताया जाता है कि जिस दौरान हनुमान जी अयोध्या में वास करते हैं, उस दौरान पूजा करने पर विशेष फल प्राप्त होता है। शाम के समय हनुमान जी की पूजा करने से पूर्ण फल मिलता है।

दोपहर के समय की पूजा

पौराणिक कथाओं के अनुसार, दोपहर के समय भगवान हनुमान की पूजा करना फलदायी नहीं माना जाता है। क्योंकि विभीषण को दिए वादे के हिसाब से हनुमान जी दोपहर के समय लंका में विराजमान होते हैं। इसलिए इस दौरान की हुई पूजा उनतक नहीं पहुंचती है। वहीं यह प्रथा सदियों से चली आ रही है और इसको आज भी सत्य माना जाता है। मान्यता है कि हनुमान जी आज पृथ्वी पर जीवंत रूप में मौजूद हैं। ऐसे में जो भी भक्त हनुमान जी की सही तरीके से पूजा-अर्चना करता है, तो उसको सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है।

किस दिन करें की पूजा

वैसे तो आप रोजाना विधि-विधान से हनुमान जी की पूजा-अर्चना कर सकते हैं। लेकिन शनिवार और रविवार को विशेष रूप में पूजा करनी चाहिए। इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष के द्वार खुलते हैं। मंगलवार के दिन ही हनुमान जी का जन्म हुआ था इसलिए इस दिन उनकी पूजा करना विशेष माना जाता है। वहीं शनिवार के दिन पूजा करने से शनि की कुदृष्टि से बचा जा सकता है। शनिदेव से जुड़ी पौराणिक कथा के मुताबिक शनिवार को हनुमान जी की पूजा करना बेहद महत्वपूर्ण होता है।

खाली पेट पिएं सौंफ और मिश्री का पानी, मिलेंगे अद्भुत छह फायदे

सौंफ और मिश्री का पानी गर्मी से होने वाली बीमारियों के इलाज का प्राचीन इलाज है। गर्मियों में यह अमृत शरीर और दिमाग को कितने फायदे पहुंचा सकता है। सौंफ के बीज और मिश्री दोनों में शीतलन गुण होते हैं जो आपके पेट को शांत कर सकते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ावा दे सकते हैं।

सुबह के समय अपने शरीर को एनर्जी देने से बेहतरीन स्वास्थ्य प्राप्त करने में काफी मदद मिल सकती है। गर्मियों में कम भूख और पाचन संबंधी समस्याएं आम हैं क्योंकि उच्च तापमान हमारे शरीर के कार्यों को प्रभावित कर सकता है। लू के दौरान शरीर को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखने और अपने पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी जाती है। सौंफ और मिश्री का पानी, गर्मी आधारित बीमारियों के इलाज के साथ-साथ डिटॉक्स और पाचन में सहायता करने का प्राचीन इलाज है। यह एक समर सीजन का अमृत है जो शरीर और दिमाग के लिए कई तरह के लाभ ला सकता है। सौंफ या सौंफ के बीज और मिश्री दोनों में शीतलन गुण होते हैं जो आपके पेट को शांत कर सकते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ावा दे सकते हैं, वजन घटाने में सहायता कर सकते हैं और यहां तक कि तनाव को भी दूर कर सकते हैं। सौंफ में कैल्शियम, विटामिन सी, आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम का भंडार हैं। एनेथोल नामक यौगिक के कारण इसमें कैंसर-विरोधी गुण भी होते हैं, शोध के अनुसार जो स्तन कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने और यहां तक कि स्तन और यकृत कैंसर कोशिकाओं के प्रसार को रोकने में भी प्रभावी है। मिश्री को थकान दूर करने और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। सौंफ और मिश्री का संयोजन चिलचिलाती गर्मी से निपटने में काम आ सकता है।

सौंफ और मिश्री का पानी कैसे बनाएं? : सौंफ और मिश्री के पानी को अपनी सुबह की दिनचर्या में शामिल करना आसान है। बस एक चम्मच सौंफ और एक छोटा टुकड़ा मिश्री को रात भर एक गिलास पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट इसे पी लें। वैकल्पिक रूप से, आप सामग्री को कुछ मिनटों के लिए एक साथ उबाल सकते हैं, छान सकते हैं और इसमें मिला हुआ पानी पी सकते हैं। यहां छह ठोस कारण बताए गए हैं कि क्यों अपने दिन की शुरुआत सौंफ और मिश्री के पानी से करना आपके स्वास्थ्य के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है।

पाचन सहायता

सौंफ में आवश्यक तेल होते हैं जो पाचन रस के स्राव को उत्तेजित करते हैं, पाचन प्रक्रिया में सहायता करते हैं। जब पानी के रूप में सेवन किया जाता है, तो यह सूजन, अपच और कब्ज को कम करने में मदद करता है और स्वस्थ आंत को बढ़ावा देता है।

विषैले पदार्थों को हटाता है

सौंफ और मिश्री दोनों में विषहरण गुण होते हैं जो प्रदूषक तत्वों, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और तनाव के दैनिक संपर्क से शरीर में जमा हुए विषाक्त पदार्थों को साफ करने में मदद करते हैं। इस पानी का नियमित सेवन लीवर के कार्य को समर्थन देता है और शरीर के प्राकृतिक विषहरण तंत्र को बढ़ाता है।

वजन प्रबंधन करने में सहायक

जो लोग अपना वजन नियंत्रित करना चाहते हैं उनके लिए सौंफ और मिश्री का पानी पीना फायदेमंद हो सकता है। यह संयोजन भूख को दबाने, अस्वास्थ्यकर स्नैक्स की लालसा को रोकने और चयापचय को बढ़ावा देने में मदद करता है, जिससे संतुलित आहार और नियमित व्यायाम के साथ वजन घटाने के प्रयासों में सहायता मिलती है।

ओरल हेल्थ में सुधार करता है

सौंफ अपने रोगाणुरोधी गुणों के लिए जाना जाता है, जो ओरल संक्रमण, सांसों की दुर्गंध और मसूड़ों की बीमारी को रोकने में मदद कर सकता है। जब पानी के रूप में सेवन किया जाता है, तो यह मुंह को साफ करके और दंत समस्याओं के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया के विकास को कम करके ओरल स्वच्छता को बढ़ावा देता है।

एंटी-इन्फ्लेमेटरी प्रभाव

सौंफ और मिश्री दोनों में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो गठिया, गठिया और मांसपेशियों में दर्द जैसी सूजन संबंधी स्थितियों के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं। इस पानी के नियमित सेवन से सूजन कम हो सकती है और जोड़ों की गतिशीलता में सुधार हो सकता है।

तनाव से राहत

सौंफ की सुगंध का मन और शरीर पर शांत प्रभाव पड़ता है, जिससे यह तनाव से राहत और आराम के लिए एक उत्कृष्ट प्राकृतिक उपचार बन जाता है। सौंफ और मिश्री के पानी के साथ दिन की शुरुआत करने से दिन के लिए सकारात्मक माहौल बनाने, मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है।

भारत गुवाहाटी में BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा...

बीडब्ल्यूएफ ने जानकारी दी कि विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी अगले साल गुवाहाटी में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र करेगा। विश्व बैडमिंटन महासंघ (बीडब्ल्यूएफ) की इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का आयोजन भारत में वर्ष 2008 के बाद यह पहली बार होगा। भारत ने पिछली बार पुणे में इस प्रतियोगिता की मेजबानी की थी।

भारत अगले साल गुवाहाटी में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। खेल की वैश्विक संचालन संस्था बीडब्ल्यूएफ ने मंगलवार को यह जानकारी दी। वर्ष 2008 के बाद यह पहली बार होगा जब विश्व बैडमिंटन महासंघ (बीडब्ल्यूएफ) की इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का आयोजन भारत में होगा। बीडब्ल्यूएफ ने एक विज्ञप्ति में कहा, ''टीम और व्यक्तिगत दोनों स्पर्धाएं देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय बैडमिंटन संघ (बीएआई) के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में आयोजित की जाएंगी।'' भारत ने पिछली बार पुणे में इस प्रतियोगिता की मेजबानी की थी।

बीडब्ल्यूएफ के अध्यक्ष पॉल-एरिक होयर ने कहा, ''भारत में तेजी से बैडमिंटन में एलीट प्रतिभाएं सामने आ रही हैं और हमारी विश्व जूनियर प्रतियोगिता को दूसरी बार भारत लाना बीडब्ल्यूएफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।'' उन्होंने कहा, ''बीएआई का नया राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र बैडमिंटन के लिए एक अत्याधुनिक सुविधा है और यह हमारी अगली पीढ़ी की प्रतिभाओं के लिए टीम और व्यक्तिगत खिताब के लिए चुनौती पेश करने का आदर्श स्थल होगा।''

हालांकि 2025 में होने वाले इस टूर्नामेंट की तारीखों की अभी पुष्टि नहीं हुई है। बीडब्ल्यूएफ के थॉमस और उबेर कप फाइनल्स का अगला सत्र डेनमार्क के होर्सेन्स में होगा। यह दूसरी बार है जब डेनमार्क बीडब्ल्यूएफ विश्व पुरुष और महिला टीम चैंपियनशिप का आयोजन करेगा। वह इससे पहले 2021 में आरहस में इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर चुका है। बीडब्ल्यूएफ परिषद की 28 अप्रैल को हुई बैठक में मेजबानी के अधिकार की पुष्टि की गई।

भारतीय एथलीट खुद को दुनिया के शीर्ष एथलीटों से कम नहीं समझते : तूर

एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता तजिंदरपाल सिंह तूर ने कहा कि चोपड़ा की उपलब्धि के बाद मानसिकता में आए बदलाव ने भारतीय एथलीटों को विश्वास दिलाया है कि वे पेरिस ओलंपिक में सिर्फ भाग लेने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लक्ष्य के साथ जा रहे हैं।

भारतीय के शीर्ष गोला फेंक खिलाड़ी तजिंदरपाल सिंह तूर का मानना है कि तोक्यो ओलंपिक में विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा के ऐतिहासिक स्वर्ण पदक से भारतीय खिलाड़ियों का 'विश्वास बढ़ा' है और वे खुद को 'शीर्ष वैश्विक एथलीटों से कम नहीं' समझते हैं। दो बार के एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता तूर ने कहा कि चोपड़ा की उपलब्धि के बाद मानसिकता में आए बदलाव ने भारतीय एथलीटों को विश्वास दिलाया है कि वे पेरिस ओलंपिक में सिर्फ भाग लेने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लक्ष्य के साथ जा रहे हैं। तूर ने शनिवार को यहां 'टीसीएस विश्व 10के बेंगलुरु' की पूर्व संध्या पर आयोजित एक पैनल चर्चा में कहा, '' तोक्यो ओलंपिक खेलों में नीरज चोपड़ा के स्वर्ण पदक के बाद से खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ा है। हम में से हर कोई इसमें केवल भाग लेने के लिए नहीं जा रहा है। हम पदक जीतने की मानसिकता के साथ वहां जा रहे हैं। उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि आज मानसिकता में बदलाव आया है। हम अपने आप को उन शीर्ष वैश्विक एथलीटों से कम नहीं समझते जिनके साथ हम प्रतिस्पर्धा करते हैं। विश्व चैंपियनशिप के नतीजों को देखें, हमारे पास नीरज और किशोर जेना पोडियम पर थे। हमारे पास डीपी मनु भी थे। वह इसी स्पर्धा के फाइनल में पहुंचे थे।'' चर्चा में 27 बार के आईबीएसएफ विश्व चैंपियन पंकज आडवाणी, शीर्ष निशानेबाज तेजस कृष्ण प्रसाद, स्क्वाश स्टार जोशना चिनप्पा, पूर्व अंतरराष्ट्रीय एथलीट और अर्जुन पुरस्कार विजेता अश्विनी नचप्पा भी शामिल थे।

मेनोपॉज शुरू होने पर ब्रेस्ट में क्यों होता है दर्द...

मेनोपॉज शुरू होने पर महिलाओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस दौरान वेजाइनल ड्राइनेस, हॉट फ्लैशेस पसीने और ब्रेस्ट में दर्द होता है। हम बताने जा रहे हैं कि मेनोपॉज के दौरान महिलाओं को ब्रेस्ट में दर्द क्यों होता है। जब महिलाओं में प्राकृतिक रूप से पीरियड साइकिल बंद हो जाता है, तो इस फेस को मेनोपॉज कहा जाता है। हर महिला को इससे गुजरना पड़ता है। आमतौर पर करीब 40-50 साल की उम्र में मेनोपॉज शुरू होता है। इस दौरान महिलाओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस दौरान वेजाइनल ड्राइनेस, हॉट फ्लैशेस पसीने और ब्रेस्ट में दर्द होता है। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम बताने जा रहे हैं कि मेनोपॉज के दौरान महिलाओं को ब्रेस्ट में दर्द क्यों होता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ब्रेस्ट में दर्द होना मेनोपॉज की एक सामान्य वजह है। अलग-अलग महिलाओं में अलग-अलग तरीकों से अनुभव होता है। कुछ महिलाओं को जलन, कोमलता और दर्द

होता है, तो वहीं कुछ महिलाओं को चुभने वाला दर्द होता है। क्योंकि आपके ब्रेस्ट के टिशु हार्मोन के प्रति संवेदनशील होते हैं। मेनोपॉज या पेरी मेनोपॉज में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन में ड्रॉप होता है। हांलाकि यह हार्मोनल बदलाव ही है, तो स्तन में दर्द का अनुभव देते हैं। एस्ट्रोजन में गिरावट होने की वजह से सपोर्टिंग कनेक्टिव टिशू कम हो जाता है। जिसकी वजह से ब्रेस्ट में दर्द और कोमलता आती है। ऐसा होना सामान्य प्रक्रिया है, जिसे लेकर महिलाओं को घबराना नहीं चाहिए। वहीं अगर आप ज्यादा दर्द से परेशान हैं तो डॉक्टर से संपर्क कर सकती हैं।

ऐसे रखें ख्याल

- कैफीन,स्मोकिंग और अल्कोहल का सेवन करने से परहेज करें
- ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करें
- हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल चुने
- नियमित रूप से ब्रेस्ट की जांच कारण
- रेगुलर एक्सरसाइज करें
- तनाव को मैनेज करें
- सपोर्टिव ब्रा पहने

PCOS महिलाओं की मेंटल हेल्थ पर डाल सकता है बुरा असर...

पीसीओएस से पीड़ित महिलाओं में मोटापा, अनियमित मासिक धर्म, पिंपल्स, बालों का झड़ना और गर्भधारण करने में परेशानी होती है। वहीं इस समस्या के कारण कई बार महिलाओं की मेंटल हेल्थ भी खराब हो जाती है। पीसीओएस यानी कि पॉली सिस्टिक ओवरी सिंड्रोम से पीड़ित महिलाएं कई समस्याओं का सामना करती हैं। साथ ही यह एक गंभीर समस्या है। वर्तमान समय में बड़ी संख्या में महिलाएं इस समस्या का सामना कर रही हैं। बता दें कि 18 से 35 साल तक की महिलाएं तेजी से पीसीओएस की चपेट में आ रही हैं। इस स्थिति में महिला के अंडाशय से एग तय समय से पहले रिलीज होने लगती हैं। जो बाद में सिस्ट में बदल जाते हैं।

इसकी वजह से महिलाओं में मोटापा, अनियमित मासिक धर्म, पिंपल्स, बालों का झड़ना और गर्भधारण करने में परेशानी होती है। वहीं इस समस्या के कारण कई बार महिलाओं की मेंटल हेल्थ भी खराब हो जाती है। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको पीसीओएस के लक्षण और कारणों के बारे में बताने जा रहे हैं। बता दें कि महिला के प्रजनन चक्र में हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्राथमिक होते हैं। लेकिन पीसीओएस की समस्या में मेल हार्मोन एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। वहीं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा कम होने लगती है। हार्मोन में उतार-चढ़ाव होने पर सेरोटोनिन के स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह नींद चक्र, मूड और भूख कों कंट्रोल करता है। इसी वजह से महिलाओं में तनाव, मूड स्विंग्स और चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है।

इस समस्या से पीड़ित महिलाओं में आत्मविश्वास की कमी देखी जाती है। यह महिलाएं खुद को दूसरों से कंपेयर करती हैं। जिसके कारण उनको तनाव होने लगता है। सेरोटोनिन को हैप्पी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। वहीं इसकी कमी होने पर बात-बात पर गुस्सा होना,उदासी महसूस होना और मूड स्विंग्स होने लगता है।

PCOS में बॉडी में कई तरह के बदलाव होते हैं। जैसे- मुंहासे आना, वजन बढ़ना और बालों का झड़ना आदि शामिल है। इन सारी चीजों को देखकर महिलाएं तनाव में रहने लगती हैं और धीरे-धीरे वह डिप्रेशन व एंग्जाइटी का शिकार हो जाती हैं। इस समस्या से पीड़ित महिलाएं खुद को फिजिकली काफी कम अट्रैक्टिव मानती हैं।

उर्वशी रौतेला ने ड्रामेटिक स्लीव्स वाले लाल गाउन में जलवा बिखेरा...

उर्वशी रौतेला कान्स फिल्म फेस्टिवल 2024 के लिए फ्रेंच रिवेरा में हैं। गुरुवार को अभिनेता ने प्रतिष्ठित कार्यक्रम में रेड कार्पेट पर वॉक किया। उर्वशी, जो पहले कान्स फिल्म फेस्टिवल में ज्यादातर चमकीले रंग के परिधानों में शामिल हुई थीं।

उर्वशी रौतेला कान्स फिल्म फेस्टिवल 2024 के लिए फ्रेंच रिवेरा में हैं। गुरुवार को अभिनेता ने प्रतिष्ठित कार्यक्रम में रेड कार्पेट पर वॉक किया। उर्वशी, जो पहले कान्स फिल्म फेस्टिवल में ज्यादातर चमकीले रंग के परिधानों में शामिल हुई थीं, अपनी मुख्य शैली पर कायम रहीं। अपनी ताजा उपस्थिति के लिए, उन्होंने चमकदार लाल अलंकरणों वाला एक ऑफ शॉल्गाडर गाउन चुना। तीसरे दिन, अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने फ्रेंच रिवेरा में कान्स फिल्म फेस्टिवल 2024 में चमकदार लाल अलंकरणों से सजे शॉल्गाडर रंग के गाउन में शोभा बढ़ाई। यह लुक तब आया है जब अभिनेता ने पहले दिन रेड कार्पेट पर हॉट गुलाबी रफ़ल्ड पोशाक में सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा था।

तीसरे दिन, उर्वशी रौतेला ने कान्स 2024 में एक शानदार बयान दिया। उन्होंने ट्यूनीशियाई डिजाइनर, सौहिर एल गब्सी द्वारा एक चमकदार बॉडीकॉन ऑफ-शोल्डर गाउन में फ्रेंच रिवेरा को लाल रंग में रंग दिया। उनके आउटफिट का मुख्य आकर्षण लाल फूली हुई आस्तीन थी। उर्वशी ने फ्रांसिस फोर्ड कोपोला के 'मेगालोपोलिस' के प्रीमियर में भाग लिया।

कान्स फिल्म फेस्टिवल 2024 के उद्घाटन समारोह के बाद, उर्वशी ने रात के लिए अपने लुक की कई तस्वीरें और वीडियो इंस्टाग्राम पर साझा कीं: एक गुलाबी रफ़ल गाउन। फूशिया पोशाक लेबनानी लेबल, खालिद और मारवान द्वारा थी। उर्वशी ने अपने एक पोस्ट को कैप्शन दिया, 'फेस्टिवल डे कान्स 2024 का उद्घाटन समारोह मेरी परम पसंदीदा मेरिल स्ट्रीप के साथ।'

77वां कान्स फिल्म फेस्टिवल मंगलवार रात ग्रैंड थिएटर लुमियर में ग्लैमर और प्रतिभा के शानदार प्रदर्शन के साथ शुरू हुआ। मेहमानों में कोई और नहीं बल्कि हॉलीवुड आइकन मेरिल स्ट्रीप थीं, जिन्हें प्रतिष्ठित मानद पाल्मे डी'ओर से सम्मानित किया गया था।

किरदार चुनते वक्त इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे : मनोज

मशहूर फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी ने मंगलवार को कहा कि उन्हें अदाकारी को लेकर किसी बक्से में कैद होना पसंद नहीं है और किरदार चुनते वक्त वह इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे। बाजपेयी अपनी आगामी फिल्म ''भैयाजी'' के प्रचार के लिए इंदौर आए थे।

मशहूर अभिनेता मनोज बाजपेयी ने मंगलवार को कहा कि उन्हें अदाकारी को लेकर किसी बक्से में कैद होना पसंद नहीं है और किरदार चुनते वक्त वह इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे। बाजपेयी अपनी आगामी फिल्म ''भैयाजी'' के प्रचार के लिए इंदौर आए थे। यह उनके करियर की 100वीं फिल्म है जिसमें वह मार-धाड़ वाले किरदार में नजर आएंगे। बाजपेयी ने संवाददाताओं से कहा, ''आगे भी मेरी जो फिल्में आएंगी, वे पहले से अलग होंगी क्योंकि मुझे किसी बक्से में बंद होकर रहना पसंद नहीं है। मैं एक ही तरह के किरदारों से ऊब जाता हूं। उन्होंने कहा, ''मुझे (अभिनेता के तौर पर) लगातार नयी चुनौतियों का सामना करते हुए खुद को बदलते रहना पसंद है। मेरा इस बात पर ज्यादा ध्यान रहता है कि एक अभिनेता के रूप में मेरा विकास हो रहा है या नहीं? लोग क्या कहेंगे, मैं इस बारे में थोड़ा कम सोचता हूं या सच बोलूं तो मैं इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता हूं।'' यह पूछे जाने पर कि क्या पारिवारिक और सामाजिक कहानियों वाली फिल्मों के लिए दर्शकों की भीड़ सिनेमाघरों में लौटेगी, बाजपेयी ने कहा, ''आज के दौर में सबसे पहले जरूरी यह है कि दर्शक सिनेमाघरों में लौटें और पहले की तरह मिल-बैठकर फिल्मों का मजा लें। यह आज हर फिल्म निर्माता और हर कलाकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।'' उन्होंने कहा, ''मैं मानता हूं कि किसी फिल्म के हर विभाग का पूरा आनंद बड़े परदे वाले सिनेमाघर में 100-150 लोगों के साथ बैठकर ही लिया जा सकता है, फिर फिल्म चाहे किसी भी तरह की हो।'' मनोरंजन जगत में ओटीटी मंचों का जोर बढ़ने पर बाजपेयी ने कहा कि लोग इन दिनों मोबाइल फोन पर भी फिल्में देख रहे हैं, लेकिन फोन पर किसी फिल्म के हर कलात्मक पहलू का पूरा आनंद लिया जाना मुमकिन नहीं है। राजनीति में आने की संभावना के सवाल पर उन्होंने कहा कि सियासत की दुनिया उन्हें समझ नहीं आती, लेकिन वह हर पांच साल में मतदान की जिम्मेदारी जरूर निभाते हैं और इसके बाद मनोरंजन जगत में अपने काम में फिर से जुट जाते हैं।

अंकिता ने करण जौहर की स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 को किया रिजेक्ट

अभिनेत्री के करीबी एक विश्वसनीय सूत्र ने बताया कि अंकिता को स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 की पेशकश की गई थी, जो एक वेब सीरीज होगी, लेकिन उन्होंने करण जौहर के प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का अवसर उन कारणों से ठुकरा दिया, जो उन्हीं को पता है। इस कारण का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। बिग बॉस 17 में अपने सफल कार्यकाल के बाद अंकिता लोखंडे सफलता की राह पर हैं। न्यूज18 शोशा को विशेष रूप से पता चला है कि अभिनेत्री को हाल ही में करण जौहर की स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 की पेशकश की गई थी। हालांकि, 'पवित्र रिश्ता' स्टार ने इसे अस्वीकार कर दिया है। अभिनेत्री के करीबी एक विश्वसनीय सूत्र ने बताया कि अंकिता को स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 की पेशकश की गई थी, जो एक वेब सीरीज होगी, लेकिन उन्होंने करण जौहर के प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का अवसर उन कारणों से ठुकरा दिया, जो उन्हीं को पता है। इस कारण का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है।

अंदरूनी सूत्र ने बताया हां, अंकिता को स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 के लिए संपर्क किया गया था। मैं उस भूमिका के बारे में निश्चित नहीं हूं जो उन्हें ऑफर की गई थी, लेकिन उनसे यह जरूर पूछा गया था कि क्या वह SOTY फ्रेंचाइजी का हिस्सा बन सकती हैं। हालाँकि, उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है और उनके निर्णय के पीछे का कारण कोई नहीं जानता।

44वीं शादी की सालगिरह पर हेमा मालिनी - धर्मेन्द्र की अनदेखी तस्वीर साझा की

दिग्गज बॉलीवुड सितारे हेमा मालिनी और धर्मेंद्र आज, 2 मई, 2024 को अपनी 44वीं शादी की सालगिरह मना रहे हैं। इस विशेष अवसर पर अपने माता-पिता को शुभकामनाएं देते हुए, ईशा देओल ने अपने माता-पिता की एक मनमोहक और अनदेखी तस्वीर साझा की।

दिग्गज बॉलीवुड सितारे हेमा मालिनी और धर्मेंद्र आज, 2 मई, 2024 को अपनी 44वीं शादी की सालगिरह मना रहे हैं। इस विशेष अवसर पर अपने माता-पिता को शुभकामनाएं देते हुए, ईशा देओल ने अपने माता-पिता की एक मनमोहक और अनदेखी तस्वीर साझा की। उन्होंने तस्वीर के साथ लिखा, मेरे पापा और माँ को सालगिरह की शुभकामनाएँ। मैं आपकी पूजा करती हूं, मैं आपसे प्यार करती हूं और मैं बस आपको गले लगाना चाहती हूं। तस्वीर में हेमा मालिनी को धर्मेंद्र के कंधे पर सिर झुकाए देखा जा सकता है। 'बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल' फ्लोरल प्रिंट में 'खूबसूरत' लग रही हैं। दूसरी ओर, धर्मेंद्र हरे रंग की शर्ट में 'डैपर' लग रहे हैं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी 1980 में हुई और उनकी दो बेटियाँ हैं, ईशा देओल और अहाना देओल। हेमा दिग्गज अभिनेता की दूसरी पत्नी हैं। धर्मेंद्र के पहली पत्नी प्रकाश कौर से दो बेटे सनी देओल और बॉबी देओल और दो बेटियां हैं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की पहली मुलाकात 1970 में फिल्म तुम हसीं मैं जवान की शूटिंग के दौरान हुई थी। फिल्म में दोनों ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इन वर्षों में, दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो गया, भले ही धर्मेंद्र एक विवाहित व्यक्ति थे और उनके चार बच्चे थे। हालाँकि, आख़िरकार दोनों 1980 में शादी के बंधन में बंध गए। इस बीच, काम के मोर्चे पर, धर्मेंद्र को आखिरी बार शाहिद कपूर और कृति सेनन की फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में देखा गया था। वह अगली बार श्रीराम राघवन की फिल्म इक्कीस में नजर आएंगे। लोकसभा चुनावों के बीच हेमा मालिनी अपने राजनीतिक कार्यकाल में काफी व्यस्त हैं। भाजपा उम्मीदवार मथुरा से फिर से चुनाव की मांग कर रही हैं, जिस निर्वाचन क्षेत्र का वह 2014 से प्रतिनिधित्व कर रही हैं।

हमारा देश हमारा अभिमान

हर-हर महादेव

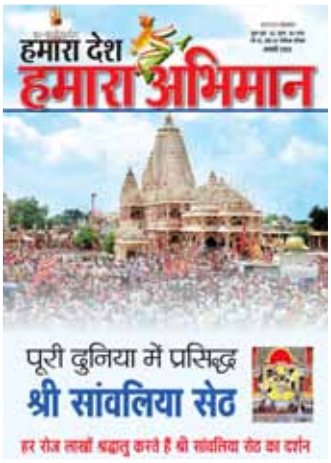

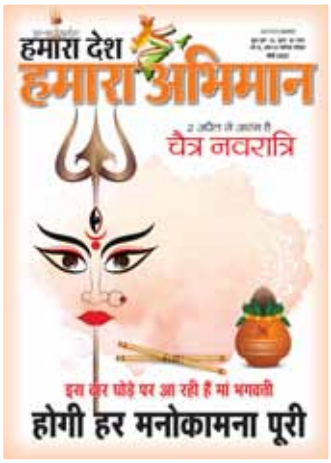

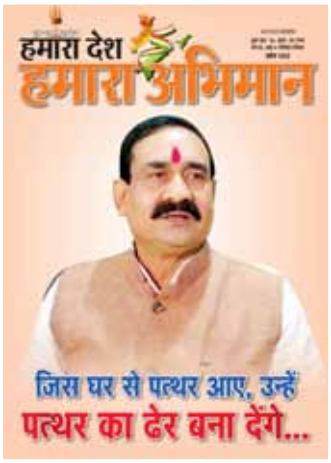

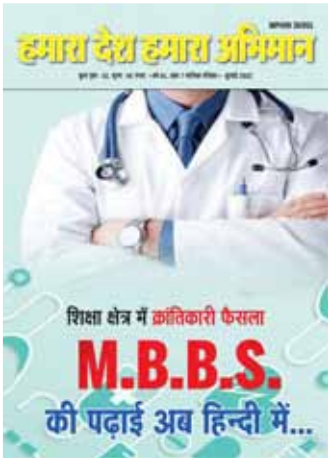

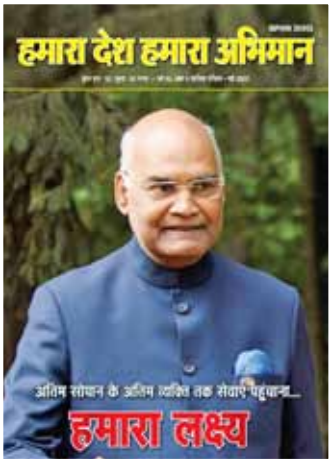

हमारा देश हमारा अभिमान मासिक पत्रिका की प्रति बुक करने के लिए सम्पर्क करें..

मनोज चतुर्वेदी : 98266 36922, 88392 59136

जटा टवी गलज्जलप्रवाह पावितस्थले गलेऽव लम्ब्यलम्बितां भुजंगतुंग मालिकाम्।
डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् ॥1॥

अर्थ : उनके बालों से बहने वाले जल से उनका कंठ पवित्र है, और उनके गले में सांप है जो हार की तरह लटका है, और डमरू से डमट् डमट् डमट् की ध्वनि निकल रही है, भगवान शिव शुभ तांडव नृत्य कर रहे हैं, वे हम सबको संपन्नता प्रदान करें।